



बुनियादी ढाँचे में हुआ  
अभूतपूर्व निवेश  
सौम्य क्रांति घोष

16



नतीजों से पहले सीमेंट  
और फार्मा में हैं अवसर  
दीपन मेहता

25



आज तो दूसरे देशों से  
और अच्छा है भारत  
समीर अरोड़ा

26

वर्ष : 12 अंक : 10

30 सितंबर 2023

मूल्य : 50 रुपये

# निवेश मंथन

मोदी सरकार के दसवें साल का बड़ा सवाल  
एक दशक में कितना बदला देश का हाल



अर्थनीति

बदलती तस्वीर में हैं भारत की  
तरक्की के साक्ष्य

18

विश्व मंच

जी20 ने भारत का मान  
बढ़ाया

31





The difference  
between falling  
and flying is  
**Risk Management.**

**Managing risk is more important than  
simply taking risk.**

#EdgeOfKnowledge

**133** years of  
Global Experience

Taking risks isn't enough. Optimizing risks, weighing pros and cons, and reducing the probability of untoward occurrence, is what differentiates falling and flying in investing.

Strong processes and risk management help you achieve your goals steadily and sustainably.

An investor education and awareness initiative of Nippon India Mutual Fund

Contact your Mutual Fund Distributor or Investment Advisor | Give us a missed call on 8000112244 | Visit [mf.nipponindiaim.com/edgeofknowledge](http://mf.nipponindiaim.com/edgeofknowledge)

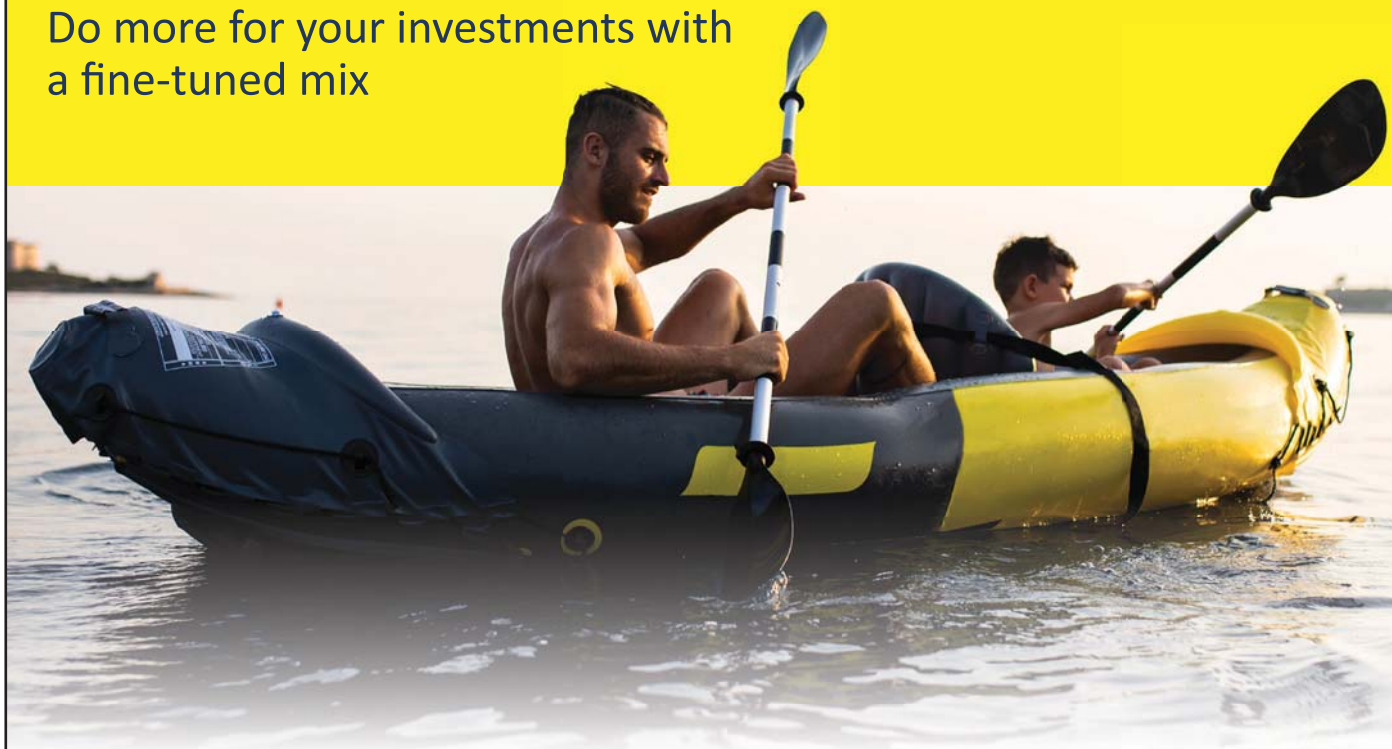
Helpful Information for Mutual Fund Investors: All Mutual Fund investors have to go through a one-time KYC (know your Customer) process. Investors should deal only with registered mutual funds, to be verified on SEBI website under 'Intermediaries/Market Infrastructure Institutions'. For redressal of your complaints, you may please visit [www.scores.gov.in](http://www.scores.gov.in). For more info on KYC, change in various details and redressal of complaints, visit [mf.nipponindiaim.com/InvestorEducation/what-to-know-when-investing](http://mf.nipponindiaim.com/InvestorEducation/what-to-know-when-investing)

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



# DON'T CHOOSE BETWEEN STABILITY OR GROWTH. GET BOTH.

Do more for your investments with a fine-tuned mix



## Motilal Oswal Large and Midcap Fund

Diverse portfolio with existing and emerging leaders

Guided by **Quality, Growth, Longevity, and Price (QGLP)** Investment Philosophy

Aimed towards investing in companies with a competitive advantage

Visit: [motilaloswalmf.com](http://motilaloswalmf.com) or consult your Financial Advisor/Distributor

**THINK EQUITY**  
**THINK MOTILAL OSWAL**



Please refer Scheme Information Document (SID) for detailed Investment Strategy.

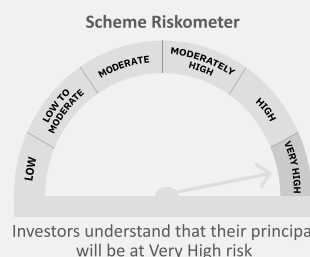
### Name of the scheme

Motilal Oswal Large and Midcap Fund (Large and Midcap Fund - An open ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks)

### This product is suitable for investors who are seeking\*

- Long-term capital growth
- Investment predominantly in equity and equity related instruments of large and midcap stocks

\*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.



**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

# विषय सामग्री



विकास मोदी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक नारा भी रहा है। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की चाल कहीं बदली है, या जो भी प्रगति हम देख रहे हैं वह तो वैसे भी होनी ही थी? इसे समझने के लिए बीते दो दशकों में अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख संकेतकों की दशा-दिशा को सामने रख रही है इस अंक की आमुख कथा।

9

संपादकीय - पारिवारिक बचत दर में कमी चिंताजनक	8
बहुत बड़े स्तर पर सुधरी है भारत की बांड छवि : सैम बलसारा	12
आमुख कथा : मोदी सरकार के नौ साल - उपलब्धियों का पीछा करते सवाल	15
नतीजों से पहले सीमेंट और फार्मा में हैं अवसर : दीपन मेहता	25
आज तो दूसरे देशों से और अच्छा है भारत : समीर अरोड़ा	26
जी20 ने भारत का मान बढ़ाया	31
न्यूचुअल फंडों ने क्या खरीदा, क्या बेचा : अगस्त 2023	34
स्मॉलकैप में निवेश के लिए और अधिक सही है न्यूचुअल फंड	35
ऐक्टिव और पैसिव फंडों के बीच कैसे बनायें संतुलन	39
महंगाई कब तक? जब तक समोसे में आलू!	40
नये डीमैट खातों की संख्या 19 महीनों के शिखर पर	41
महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष का कसमसाता समर्थन : कौशल सिखौला	43
नये उत्पाद : 'होंडा एलिवेट ने दिल खुश कर दिया' : टुट्टु धवन	44



पब्लिक डिजिटल इन्फ्रा और बैंकों में सुधार बड़ी उपलब्धियाँ  
इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा से बातचीत।

24



10 वर्षों में हुआ बुनियादी ढाँचे में अभूतपूर्व निवेश

एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष से बातचीत।

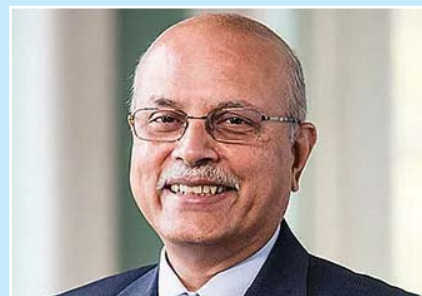
16



बदलती तस्वीर में हैं भारत की तरक्की के साक्ष्य

बीते एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था में आये बदलावों को रेखांकित कर रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ रस्तोगी।

18



देश, बैंक और कॉर्पोरेट : तीनों की बैलेंस शीट सुधरी

जाने-माने चार्टर्ड एकाउंटेंट शैलेष हरिभक्ति की नजर में बीते दशक में आये प्रमुख बदलाव।

23



## NSE के मैसेज और आपके ट्रेड्स

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि उनके ट्रांजेक्शन्स के बारे में एक्सचेंज द्वारा भेजे गए दैनिक SMS और ईमेल संदेशों की ध्यान से जांच कर लें, ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनके निर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग सदस्य द्वारा सभी ट्रेड्स निष्पादित किए गए हैं।

किसी प्रकार की विसंगति होने पर, कृपया हमें 1800 266 0050 पर कॉल करें।

अधिक जानकारी के लिए,

यहां विजिट करें [www.nseindia.com/invest/be-a-smart-investor](http://www.nseindia.com/invest/be-a-smart-investor)

या QR कोड को स्कैन करें।



@nseindia



## महंगाई से समय रहते निपटना जरूरी

पिछले अंक में 'महंगाई का जिन्न खुला घूम रहा है' लेख पढ़ा। अप्रैल-जून में विकास दर 7.8% रही, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 4.7% रही। भू-संपदा की गतिविधियाँ भी बढ़ीं, जिसे एक अच्छा संकेत माना गया। मगर महंगाई अभी चिंता का सबब बनी हुई है। महंगाई का असर निजी उपभोग पर पड़ सकता है, जिसके नतीजे में पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जुलाई में अलग-अलग खंडों में महंगाई दर के आँकड़े काफी परेशान करने वाले रहे। सरकार को बाकी चीजों के साथ-साथ महंगाई के लिए भी खास रणनीति बनानी होगी। वरना यूरोप की तरह भारत की आम जनता भी परेशानी झेलेगी। यूरोप में इस समय महंगाई ने जीवनयापन की लागत का संकट खड़ा कर दिया है। यह चुनौती भारत के सामने भी आ सकती है।

- कौशल वर्मा, पटना

## पत्र भेजें पुरस्कार जीतें

हम हर महीने एक पत्र को पुरस्कृत करने की योजना चला रहे हैं, जिसमें पुरस्कृत पत्र लेखक को निवेश मंथन की एक वर्ष की सदस्यता मुफ्त दी जाएगी।



## बूँद-बूँद से भरेगी पैसों की गगरी

पिछले अंक की आमुख कथा का एक हिस्सा काफी दिलचस्प रहा। यह हिस्सा है 'कैसे बढ़ें इस रास्ते पर'। लेख का यह हिस्सा उन तीन अहम चीजों की ओर ध्यान दिलाता है, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये तीनों चीजें हैं खर्चों पर नियंत्रण यानी कम-से-कम फिजूलखर्ची से बचना, वित्तीय लक्ष्य यानी आपको हासिल क्या करना है और संपदा आवंटन के साथ निवेश यानी पैसा अलग-अलग जगहों पर बाँट कर निवेश करें। यदि आप फिजूलखर्ची रोके तो हर महीने बचत होगी ही। इस बचत का निवेश करें, मगर पहले यह तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए पैसे का अलग-अलग जगह निवेश करें। एक बात तय है कि जब हर महीने आप कुछ पैसा निवेश करेंगे और लाभ जुड़ने से वह पैसा धीरे-धीरे बढ़ता जायेगा तो आप और अधिक बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। इसी से आपको जीवन में मिलेगी वित्तीय स्वतंत्रता।

- शौकत अंसारी, इंदौर

## जवानी में ही सोचें बुढ़ापे के बारे में

निवेश मंथन के अगस्त अंक में 'अभी सोचें रिटायर होने के बाद की बात' लेख पढ़ा। लेख का शीर्षक पढ़ कर ही व्यक्ति समझ जायेगा कि यह लेख बुढ़ापे की तैयारी जवानी में करने की बात कर रहा है। सही तरीका भी यही है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जिनके पास रिटायर होने के समय सक्रिय आय का कोई जरिया होता है। इसलिए लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने का लक्ष्य बनायें और बुढ़ापे में खर्चों की चिंता से दूर रहने के तरीके ढूँढें और वह भी जवानी में ही। लेख में एक चीज काफी अहम है। यह है इक्विटी से दीर्घकालिक धन सृजन। जानकार इक्विटी में निवेश करने की सलाह तो देते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए। यानी आपको लक्ष्य भी लंबी अवधि का रखना होगा। देखा जाये तो रिटायरमेंट भी एक ऐसा ही लक्ष्य है। यानी इक्विटी आपकी रिटायरमेंट की तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है।

- विभा, जोधपुर

## मोदी बनाम राहुल नहीं चाहेगा आई.एन.डी.आई.ए

पिछले अंक में '2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल' लेख पढ़ा। जब से राहुल गाँधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तब से 2024 के चुनाव को पहले से ज्यादा मोदी बनाम राहुल की नजर से देखा जा रहा है। मगर आई.एन.डी.आई.ए गठबंधन ऐसा नहीं चाहेगा। अगर यह चुनाव मोदी बनाम राहुल हुआ तो आई.एन.डी.आई.ए की चुनावों में जो थोड़ा-बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी, वह भी खत्म हो जायेगी। इसलिए आई.एन.डी.आई.ए इस चुनाव को बड़े स्तर पर ढेर सारे मुद्दों को आधार बना कर लड़ना चाहेगा। अगर यह चुनाव मोदी बनाम राहुल बना तो असल में यह भाजपा बनाम कांग्रेस बन जायेगा, जिसमें किस पक्ष की हार होगी, इसे सब जानते हैं। इसलिए आई.एन.डी.आई.ए आगामी चुनाव को मोदी बनाम राहुल नहीं बनाना चाहेगा।

- अमित सक्सेना, कानपुर

## निवेश मंथन

वर्ष : 12, अंक : 10  
सितंबर 2023

### सलाहकार संपादक

राजेश रपरिया

### संपादक

राजीव रंजन झा

### संपादकीय कार्यालय

138-ई, पॉकेट-1, मयूर विहार

फेज-1, दिल्ली 110091

दूरभाष : 011-79633546

011-47529834

ईमेल : edit@sharemanthan.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राजीव रंजन झा ने 138-ई, पॉकेट-1, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली 110091 से प्रकाशित और ऑल टाइम ऑफसेट प्रिंटर्स, एफ 406, सेक्टर 63, नोएडा 201307 से मुद्रित किया।

## स्पष्टीकरण

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) : निवेश मंथन पर दी जाने वाले कोई भी जानकारी लेख व विशेषज्ञों की बात केवल आपकी मदद के लिए हैं। इसे निवेश मंथन, सहयोगी प्रकाशनों या प्रकाशित की सलाह नहीं समझें। यह जरूरी नहीं है कि विश्लेषकों की सलाह से निवेश मंथन और इससे संबद्ध व्यक्ति/निकाय सहमत हों। संबंधित शेयरों में विशेषज्ञ या उनके ग्राहकों के हित जुड़े हो सकते हैं। निवेश संबंधी किसी भी फैसले से पहले अपनी खोजबीन जरूर करें और मान्यता प्राप्त पेशेवर व्यक्तियों से सलाह लें। इस पत्रिका में प्रकाशित सारी सामग्री शेयर मंथन वेबसाइट (www.sharemanthan.in) पर दिये गये विस्तृत स्पष्टीकरण के अधीन है।



CELEBRATING

5

YEARS OF

**SUNDARAM**  
**Services Fund**

An open ended equity scheme  
investing in Services Sector

**CONTROLLED  
AGGRESSION**

Since Inception CAGR: **20%**

**₹1,00,000 invested at NFO is now worth ₹2,46,093!**

**Thank you, investors and partners for believing in us!**

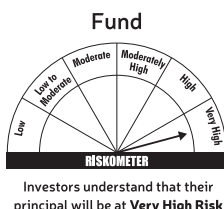
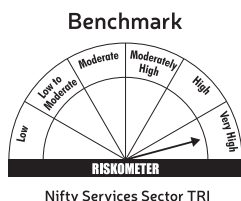
Scheme Details



**Consult your Mutual Fund Distributor or call us on 1860 425 7237 for more details.**

**f /SundaramAMC** **t /SundaramMF** **ig /sundarammutualofficial** **y /sundarammutual**

NAV: ₹24.6093. Data as on August 31, 2023. Returns are calculated on CAGR basis since inception of the scheme for Regular Plan - Growth Option. For performance details of Sundaram Services Fund and other schemes managed by the fund manager, visit <https://bit.ly/3PodleJ>. Computation: In-house, Bloomberg.



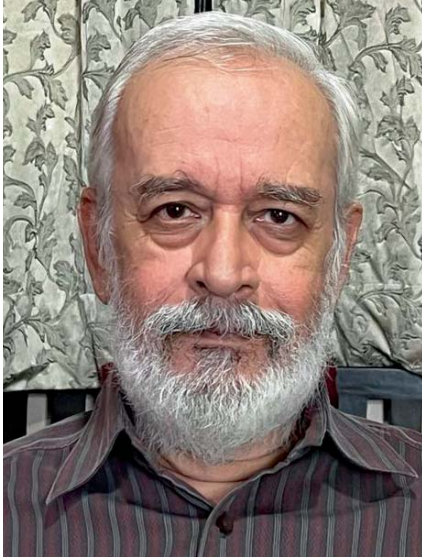
**This product is suitable for investors who are seeking\***

● Long term capital growth ● Investment in equity / equity related instruments of companies who have businesses predominantly in the Services Sector of the Economy.

\*Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.

**Mutual fund investments are subject to market risks, please read all scheme related documents carefully before investing. Returns are not assured or guaranteed. Past performance may or may not be sustained in future.**

## पारिवारिक बचत दर में कमी चिंताजनक



राजेश रणेरिया  
सलाहकार संपादकीय

**चा** लू वित्त-वर्ष 2024 की पहली तिमाही अप्रैल-जून की विकास दर से सब आश्वस्त थे कि अर्थव्यवस्था की चमक और बढ़ेगी। लेकिन सितंबर महीने में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट ने सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को झकझोर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त-वर्ष 2022-23 में पारिवारिक शुद्ध वित्तीय बचत दर पिछले 50 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गयी है, जो देश की आय संबंधी गंभीर दिक्कतों को जताती है। सरकार की आय कर नीतियों में बदलाव के कारण बचत प्रवृत्ति प्रभावित हुई है।

आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में शुद्ध पारिवारिक वित्तीय बचत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1% रह गयी, जो इससे पिछले वर्ष में 7.2% थी। वित्त-वर्ष 2020-21 में यह आँकड़ा 11.5% था। दूसरा चिंताजनक पहलू यह है कि पारिवारिक देनदारियाँ बढ़ने की दर भी समाप्त वित्त-वर्ष में 5.8% पर पहुँच गयी है, जो 2020-21 में 3.8% पर थी। समाप्त वित्त-वर्ष में पारिवारिक वित्तीय देनदारियों की वृद्धि दर आजादी के बाद दूसरी सर्वाधिक उच्च वृद्धि दर है। यह वृद्धि दर 2006-07 में 6.7% थी, जब पूरी दुनिया पर घोर वित्तीय संकट छाया हुआ था। लेकिन इस समय कोई गहरा संकट विश्व स्तर या देश स्तर पर नहीं है। इसलिए यह वृद्धि दर हैरान कर देने वाली है। देनदारियों की तेज वृद्धि दर इंगित करती है कि लोगों ने उपभोग के लिए भी कर्ज लिया है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ज लेने से खर्च और संपदा सृजन में बढ़ोतरी होती है। इसलिए घरेलू उधार अर्थव्यवस्था के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अत्यधिक उधार से वित्तीय प्रणाली को भी खतरा हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास की राह कठिन हो जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कमजोर आय वृद्धि और कर्ज के कारण वित्तीय बचत की वृद्धि को बनाये रखना काफी मुश्किल है। वित्त-वर्ष 2020-21 के अंत में शुद्ध पारिवारिक संपदाएँ 22.80 लाख करोड़ रुपये की थीं, जो 2021-22 के अंत में 16.96 लाख करोड़ रुपये रह गयीं। वित्त-वर्ष 2022-23 के अंत में इसमें और गिरावट आयी और पारिवारिक शुद्ध संपदाएँ महज 13.76 लाख करोड़ रुपये रह गयीं। पारिवारिक संपदाओं में बैंक जमा राशि, बचत खातों में पड़ी राशि, सोना-चाँदी, बीमा, भूसंपदाएँ आदि शामिल हैं। दूसरी तरफ, पारिवारिक देनदारियाँ 2022-23 में बढ़ कर जीडीपी का 37.6% हो गयीं, जो 2021-22 में 36.9% थीं। जाहिर है कि देश की बड़ी आबादी ने गुजारा करने के लिए संपदाएँ बेचीं और कर्ज भी लिये, जो देश में गंभीर आय संकट की ओर इशारा करता है।

पिछले कुछ सालों से बचत के तौर-तरीकों में बदलाव आया है। आज भी लोग बचत का बड़ा हिस्सा भूसंपदा और सोने-चाँदी के रूप में रखते हैं। वित्तीय बचतों में बैंक जमा (डिपॉजिट) ही अब भी बचतकर्ताओं में सबसे लोकप्रिय है। पर बैंकों में ब्याज दर कम होने से बचतकर्ताओं का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार की ओर आकर्षित हुआ है। बढ़ते डीमैट खाते इसका प्रमाण हैं। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंडों की तरफ बढ़ते रुझान का एक बड़ा कारण मोदी सरकार के व्यक्तिगत आय कर संबंधी नये विधान भी हैं, जिसमें पुरानी व्यक्तिगत आय कर प्रणाली में उपलब्ध केवल 50,000 रुपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को छोड़ कर बाकी बचत राहतों को समाप्त कर दिया गया है।

इसका सीधा असर केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण उपायों पर पड़ सकता है, जो लघु बचतों (स्मॉल सेविंग्स) का एक बड़ा स्रोत थे। कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) फंड में एक साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा राशि जमा करने पर केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया है। इससे भी इस फंड की जमा वृद्धि पर असर पड़ सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। लेकिन अब इसमें अधिकाधिक राशि जमा कराने से बचतकर्ता पहले ही विमुख हो चुके हैं, क्योंकि इस योजना में कम ब्याज के चलते प्रतिफल पहले जैसे आकर्षक नहीं रह गये हैं।

बचत दर और खास कर पारिवारिक बचत दर का कमजोर होना किसी के हित में नहीं है। निर्विवाद सत्य है कि बचत पर ही निवेश और विकास की बुनियाद टिकी है। यदि आर्थिक विकास और वास्तविक आय में वृद्धि होती है, तब बचत दर की यह मौजूदा स्थिति बदल सकती है। समय रहते मोदी सरकार को बचत और आय बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय करने होंगे। लेकिन यदि अब बचत दर और फिसलती है, तो देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता लंबा हो सकता है। कमजोर बचत और बढ़ता कर्ज अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेत नहीं हैं।



# मोदी सरकार के दसवें साल का बड़ा सवाल

## एक दशक में कितना बदला देश

बाजार के जानकारों और अर्थशास्त्रियों के लिए विकास वह पैमाना है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और बाजार की संभावित दिशा को समझा जाता है। पर विकास मोदी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक नारा भी रहा है। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की चाल कहीं बदली है, या जो भी प्रगति हम देख रहे हैं वह तो वैसे भी होनी ही थी? इसे समझने के लिए बीते दो दशकों में अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख संकेतकों की दशा-दिशा को सामने रख रहे हैं **राजीव रंजन झा**।



2014



2015



2016



2017



2018



2019



2020



2021



2022



2023

**ज**ब हम मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में भारत की आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने बैठते हैं, तो सबसे पहले जिस एक चीज पर ध्यान जाता है, वह यही है कि वर्ष 2014 में भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में दसवें स्थान पर था, 2023 में यह पाँचवें स्थान पर है और आशा है कि अगले कुछ ही वर्षों में यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हालाँकि विपक्षी दलों के नेता इस पर कहते हैं कि यह तो भारत की स्वाभाविक प्रगति है, यदि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के बदले कोई और होते, तो भी ऐसा ही होता।

यहाँ यह याद रखना होगा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में 2008-2009 के दौरान वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में भारी संकट आया था और उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। इसी तरह मोदी सरकार के कार्यकाल में 2020 में शुरू हुई कोरोना महामारी ने सारी दुनिया के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए एकदम अटका दिया था।

इसके अलावा, मोदी सरकार के कार्यकाल में दो नीतिगत निर्णय ऐसे हुए जिनसे दीर्घकाल में लाभ-हानि पर जो भी बहस हो मगर तात्कालिक रूप से अर्थव्यवस्था की गति जरूर धीमी हुई। पहले नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई, और फिर जुलाई 2017 में जीएसटी लागू करने के समय भी छोटे-बड़े तमाम व्यवसायों को इस नयी व्यवस्था के साथ खुद को ढालने में समय लगा।

### विकास दर की तुलना

किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को जिस एक अंक से सबसे अधिक समझा जा सकता है, वह है उसकी विकास दर या सकल देशीय उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि की दर। वित्त-वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर 7.2% आँकी गयी है, जो दूसरी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आगे है। अगले वित्त-वर्ष में

भी देश की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो तमाम जी-20 देशों की विकास दर से अधिक होगी।

मोदी सरकार के नौ वर्षों के कार्यकाल, यानी 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि में देश की जीडीपी वृद्धि दर का औसत 5.7% है, जबकि यूपीए सरकार के दस वर्षों में, यानी 2004-05 से 2013-14 के लिए औसत विकास दर 6.8% रही थी। ये आँकड़े नयी संशोधित सीरीज वाले आँकड़ों के अनुसार हैं, जिनमें 2011-12 को आधार वर्ष रखा गया है। इनके आधार पर कहा जा सकता है यूपीए सरकार के समय में विकास दर कुछ ऊँची रही थी।

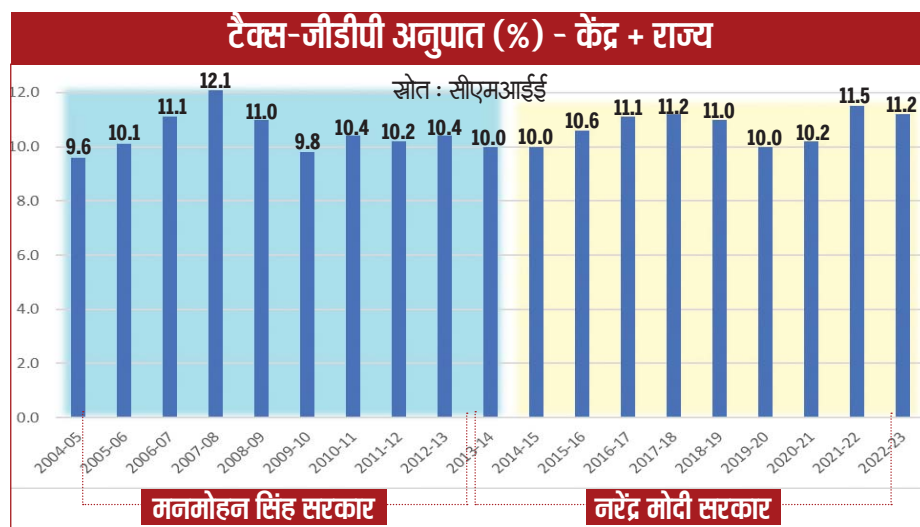
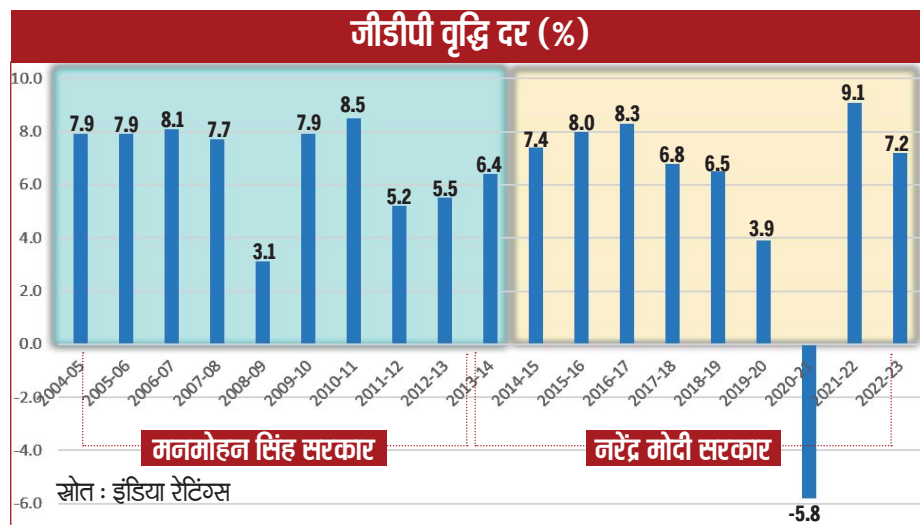
मगर साथ में विकास दर के ग्राफ को देखते समय यह भी ध्यान में आता है कि जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला, तो उन्हें पहले से गतिमान अर्थव्यवस्था मिली थी जो लगभग 8% की दर से आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब उन्होंने मई 2014 में पद छोड़ा, तो उस समय पिछले दो-तीन वर्षों से विकास दर 5-6% के दायरे में आ गयी थी। बीच में 2008-09 में विकास दर घट कर 3.1% पर भी आयी थी, हालाँकि उसका कारण वैश्विक वित्तीय संकट था।

वहीं मोदी सरकार के पहले तीन वित्त-वर्षों में विकास दर 7.4% से 8.3% तक पहुँची। नोटबंदी के बाद इसमें धीमापन आना शुरू हुआ और 2017 में जीएसटी लागू होने का भी असर नजर आया। 2020-21 में कोरोना की मार से नकारात्मक वृद्धि हुई, और जीडीपी 5.8% घट गयी। 2021-22 में 9.1% की ऊँची विकास दर दिखती है, पर वह निचले आधार के प्रभाव (बेस इफेक्ट) के चलते है। लेकिन अब 2022-23 में 7.2% विकास दर को मौजूदा वैश्विक स्थिति में एक अच्छी वृद्धि कहा जा सकता है और आगे के अनुमान भी संतोषजनक हैं।

## अधिक खर्च विकास के लिए

एक दिलचस्प तुलना यह दिखती है कि वाजपेयी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के समय केंद्र सरकार के बजट में पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) और सब्सिडी का जो अनुपात था, वह मनमोहन सिंह सरकार का कार्यकाल पूरा होते-होते एकदम पलट गया।

अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का समापन निकट आते-आते यह अनुपात वापस पलट कर लगभग वहीं पहुँच गया है, जहाँ वाजपेयी सरकार ने छोड़ा था। यह दरअसल भाजपा और कांग्रेस की प्राथमिकताओं को दिखाता है। पूँजीगत व्यय का मतलब है ऐसा



उपयोगी खर्च, जो निर्माण और भविष्य की पूँजी तैयार करने के काम आता है। वहीं सब्सिडी या राज-सहायता समाज या अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को ऐसी तात्कालिक मदद है, जो उस समय जरूरी तो लगती है, मगर उससे कोई पूँजी निर्माण नहीं होता। इसमें बुनियादी ढाँचा विकास की योजनाओं पर खर्च शामिल है, जैसे राजमार्ग, रेलवे, पुल, हवाई-अड्डे, बंदरगाह, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि के निर्माण पर होने वाला खर्च।

एक विश्लेषण के अनुसार, वित्त-वर्ष 2003-04 में केंद्र सरकार के बजट का आकार 4.71 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से 23.2% हिस्से या 1.09 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान पूँजीगत व्यय के लिए किया गया था। मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद 2013-14 में केंद्रीय बजट में पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी घट कर 12% रह गयी और 1.88 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी

फिर से बढ़ने लगी और 2023-24 के बजट में पूँजीगत व्यय के लिए 10.01 लाख करोड़ रुपये रखे गये, जो इस वर्ष बजट के कुल आकार 45.03 लाख करोड़ रुपये का 22.2% हिस्सा है। यह लगभग वही स्तर है, जो वाजपेयी सरकार के अंतिम वर्ष में था।

मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों में केंद्र सरकार का वार्षिक पूँजीगत व्यय कुल 72% बढ़ कर 1.09 लाख करोड़ रुपये से 1.88 लाख करोड़ रुपये पर पहुँचा। इन 10 वर्षों में कुल 12.4 लाख करोड़ रुपये इस मद में खर्च किये गये। मोदी सरकार के दसवें वर्ष में यह राशि 433% बढ़ कर 10.01 लाख करोड़ रुपये पर पहुँची, मतलब पाँच गुने से भी अधिक हो गयी। यानी मनमोहन सिंह सरकार के पूरे 10 वर्षों में पूँजीगत व्यय के लिए जितना पैसा रखा गया, उससे कुछ कम पैसा तो अब केवल एक साल के बजट में रखा जा रहा है।

मोदी सरकार की ओर से 10 वर्षों में पूँजीगत व्यय पर कुल खर्च 43.4 लाख करोड़ रुपये पर



## पिछले दो दशकों में अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (RE)	2023-24BE
जीडीपी वृद्धि (%)	7.9	7.9	7.9	8.1	7.7	3.1	7.9	8.5	5.2	5.5	6.4	7.4	8.0	8.3	6.8	6.5	3.9	-5.8	9.1	7.2	
राजकोषीय घाटा (जीडीपी के % में)	4.3	3.9	4.0	3.3	2.5	6.0	6.5	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	4.6	9.2	6.8	6.5	5.9
सरकारी ऋण (केंद्र + राज्य) (जीडीपी के % में)	83.2	82.1	79.1	74.7	71.4	72.2	70.6	65.6	67.4	66.7	67.1	66.6	68.5	68.4	73.2	73.3	76.9	91.6	86.4	83.7	
टैक्स-जीडीपी अनुपात (%) - केवल केंद्र सरकार	6.6	6.9	7.3	8.2	8.8	7.9	7.0	7.3	7.2	7.5	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	7.0	6.7	7.2	7.7	7.7	7.7
टैक्स-जीडीपी अनुपात (%) - केंद्र + राज्य		9.6	10.1	11.1	12.1	11.0	9.8	10.4	10.2	10.4	10.0	10.0	10.6	11.1	11.2	11.0	10.0	10.2	11.5	11.2	
निर्यात (वस्तु एवं सेवाएँ) में वृद्धि (%)	9.6	27.2	26.1	20.4	5.9	14.8	-4.8	19.5	15.5	6.8	7.8	1.8	-5.6	5.0	4.6	11.9	-3.4	-9.1	29.3	13.6	
निर्यात (जीडीपी के % में)	10.9	12.0	12.8	13.7	13.7	15.8	13.6	15.3	17.0	16.8	17.2	15.5	12.7	12.2	11.7	12.5	11.3	11.1	13.6	13.5	
वस्तु निर्यात (अब डॉलर)	64	84	103	126	163	185	179	251	306	300	314	310	262	275	303	330	313	292	422	451	
व्यापार घाटा (अब डॉलर)	-13.7	-33.7	-51.9	-61.8	-91.5	-119.5	-118.2	-127.3	-189.8	-195.7	-147.6	-144.9	-130.1	-112.4	-160.0	-180.3	-157.5	-102.2	-189.5	-265.3	
सीएडी (अब डॉलर)	-0.9	-1.0	-1.3	-2.9	-4.0	-3.5	-3.2	-2.9	-2.9	-2.2	-2.4	-2.8	-2.9	-3.4	-2.8	-2.4	-2.9	-3.0	-3.3	-2.4	
सीएडी (जीडीपी के % में)	-2.3	0.3	1.2	1.0	1.3	2.3	2.8	2.9	4.3	4.8	1.7	1.3	1.1	0.6	1.8	2.1	0.9	-0.9	1.2	2.1	
विदेशी मुद्रा भंडार (अब डॉलर)	113	142	152	199	310	252	279	305	294	292	304	342	360	370	425	413	478	577	607	578	
खुदरा मंहगाई दर (%), साल-दर-साल		3.8	4.2	5.8	6.4	8.3	10.9	12.0	8.9	9.5	9.0	6.7	4.9	4.9	3.3	3.9	3.7	6.6	5.1	6.1	
थोक मंहगाई दर (%), साल-दर-साल		5.5	6.5	4.5	6.6	4.7	8.1	9.6	8.9	6.9	5.2	1.3	-3.7	1.7	2.9	4.3	1.7	1.3	13	9.4	
बचत दर (जीडीपी के % में)		29.6	34.8	35.2	34.9	37.8	36.0	36.9	34.6	33.9	32.1	32.2	31.1	31.3	32.1	31.7	29.6	28.8	30.2		
निवेश दर (जीडीपी के % में)		29.0	35.2	36.4	36.0	39.1	38.4	39.8	39.0	38.7	33.8	33.5	32.1	32.0	33.9	33.8	30.4	27.9	31.4		
एफडीआई (अब डॉलर)		4.5	6.1	9.2	23.6	37.3	43.0	38.5	49.0	39.8	43.6	51.8	59.9	70.8	64.5	64.8	77.8	86.3	88.2	75.2	
एफडीआई (जीडीपी के % में)		0.9	1.0	1.3	2.9	4.0	3.5	3.2	2.9	2.2	2.4	2.8	2.9	3.4	2.8	2.4	2.9	3.0	3.3	2.4	
शिक्षा व्यय (अब रुपये)								519.0	601.5	660.5	713.2	686.8	672.4	720.2	802.1	803.4	894.4	842.2	803.5	998.8	1129.0
स्वास्थ्य व्यय (अब रुपये)								227.6	243.6	251.3	271.5	109.1	331.2	376.7	513.8	529.5	624.0	775.7	817.8	763.7	861.8



# बहुत बड़े स्तर पर सुधरी है भारत की ब्रांड छवि

भारत ने बीते दशक में बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाये हैं, जैसे हर भारतीय को आधार कार्ड देना, 100 करोड़ से अधिक जन-धन बैंक खाते खोलना और डिजिटलीकरण। विश्व के सभी देशों में हम स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर हैं, हमारे यहाँ डेटा का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है और डिजिटल लेन-देन की संख्या में हमारी सबसे अधिक हिस्सेदारी है। हमारी आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बहुत तेजी से बढ़ रही

है। हम इस बात के ठोस प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया उठ कर कहे, 'भारत विश्व में पहली कतार के देशों में जगह बनाने की राह पर है।' नया बेंगलुरु हवाई अड्डा, और इसी तरह मुंबई में तेजी से विकसित होने वाली तटीय सड़क (कोस्टल रोड) और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इसके उदाहरण हैं।

वास्तव में विश्व में भारत की ब्रांड छवि में बहुत बड़े स्तर पर सुधार हुआ है और आगे भी ऐसा होना जारी रहेगा। छवि हमेशा एक सापेक्ष

चीज है और हमें इस बात से भी मदद मिल रही है कि कोविड के बाद से कच्चे माल की कीमतों एवं उपभोक्ता कीमतों में ऊँची महँगाई, रूस-यूक्रेन युद्ध और कम रोजगार के चलते अमेरिका एवं यूरोप में नकारात्मक धारणा बनी हुई है।

हमारी 1.4 अरब की आबादी है, जिसे एक समय हमारे गले की फाँस माना जाता था। अब यही आबादी हमारी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गयी है, और ऐसे समय में जब अन्य बाजार नीचे दिख रहे हैं, भारतीय बाजार बढ़

पहुँच रहा है। यह बात केवल बजट का आकार बढ़ने के चलते नहीं हुई है, बल्कि वार्षिक बजट में पूँजीगत व्यय का हिस्सा मनमोहन सिंह सरकार के अंतिम वर्ष से अब लगभग दोगुने पर है।

वहीं सब्सिडी को देखें तो वित्त-वर्ष 2003-04 में सब्सिडी पर लगभग 44,300 करोड़ रुपये का खर्च हुआ, जो उस वर्ष के कुल बजट का 9.4% हिस्सा था। वित्त-वर्ष 2013-14, यानी मनमोहन सिंह सरकार के अंतिम वर्ष में सब्सिडी के लिए प्रावधान 2.55 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया, जो उस वर्ष के बजट का 16.3% हिस्सा था। इस तरह मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों में केंद्र सरकार का सब्सिडी पर वार्षिक खर्च 474% बढ़ गया, या मोटे तौर पर लगभग छह गुना हो गया।

मोदी सरकार के दसवें वर्ष, 2023-24 में सब्सिडी पर खर्च के लिए 4.03 लाख करोड़ रुपये रखे गये हैं और कुल बजट में इसकी हिस्सेदारी घट कर 9% रह गयी है। यह भी वाजपेयी सरकार के अंतिम वित्त-वर्ष के जैसा ही है। इन 10 वर्षों में सब्सिडी पर खर्च 58% बढ़ा है। जहाँ मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 वर्षों में सब्सिडी पर कुल 13.96 लाख करोड़ रुपये खर्च किये, वहीं मोदी सरकार के 10 वर्षों में यह खर्च 36.94 लाख करोड़ रुपये का रहने वाला है।

## बुनियादी ढाँचे का अभूतपूर्व जोर

यदि वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के रूप में भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना शुरू की थी, तो मोदी सरकार के कार्यकाल में बुनियादी ढाँचे के हर पहलू में

जबरदस्त तरीके से काम होता हुआ दिखता है। एक आम राय है कि इस सरकार ने बुनियादी ढाँचे के विकास में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और जितने संसाधन इस क्षेत्र में लगाये हैं, वे अभूतपूर्व हैं।

हाल में 4 अगस्त को केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह ने बुनियादी ढाँचा विकास की दिशा में अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) के निर्माण की गति यूपीए शासन के लगभग 11.6 किमी/दिन से बढ़ कर 2022-23 में लगभग 28.3 किमी/दिन हो गयी है।

ग्रामीण सड़कों में भी स्थिति काफी बदली है। मार्च 2014 तक ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गति प्रतिदिन 80 किमी की थी, जो जुलाई 2023 में प्रतिदिन 91 किमी हो गयी है। मार्च 2014 तक 1,11,325 करोड़ रुपये के खर्च से 3,81,393 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ था, जुलाई 2023 तक 3,06,358 करोड़ रुपये के खर्च से 7,42,398 किमी पर पहुँच गया।

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण देखें तो 2013-14 में 610 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण हुआ था, जो 2022-23 में बढ़ कर 6,565 आरकेएम हो गया, जो अब तक का सबसे अधिक विद्युतीकरण है। सरकार का दावा है कि चालू वित्त-वर्ष में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा।

पिछले नौ वर्षों में प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी से अधिक हो गयी। आर. के. सिंह ने बताया कि प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता इन नौ वर्षों में 8,710 लाख टन से बढ़ कर 16,100 लाख टन प्रति वर्ष को पार कर गयी है।

देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, जो दोगुनी होकर 2023 में 148 पर पहुँच गयी। इस अवधि में घरेलू विमानयात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गयी है। छोटे-छोटे शहरों के बीच हवाई यातायात को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने जो उड़ान योजना शुरू की है, उसके तहत अब तक 470 हवाई मार्गों को चालू किया जा चुका है।

आर. के. सिंह ने यह भी दावा किया कि अब बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में साढ़े 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में साढ़े 23 घंटे हो गयी है। हालाँकि इस दावे को बहुत-से क्षेत्रों के लोग अपने व्यावहारिक अनुभव से नकार सकते हैं, पर इतना जरूर माना जा सकता है कि बिजली की उपलब्धता यूपीए शासन की तुलना में काफी सुधरी है। यह भी बताया जाता है कि अब नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की हमारी लागत दुनिया में सबसे सस्ती है।

(संदर्भ : [https://pib.gov.in/](https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1945906)

[PressReleaseDetail.aspx?PRID=1945906](https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1945906))

## महँगाई कम हल्ला ज्यादा

जहाँ तक महँगाई का सवाल है, इसने यूपीए सरकार को बुरी तरह से परेशान किया। मोदी सरकार के कार्यकाल में अधिकांश वर्षों में यह आरबीआई की सहन-सीमा के अंदर रही, पर पिछले कुछ समय से और खास कर रूस-यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद से वैश्विक महँगाई की मार से भारत भी नहीं बचा है। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में महँगाई की औसत दर 8.1% रही, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में अब यह औसत लगभग 5.1% का है।

रहे हैं। इसका कारण है हमारे 30 करोड़ से अधिक के मध्यम वर्ग द्वारा होने वाला उपभोग (कंजप्शन)।

कुछ समय पहले तक देश में मध्यम वर्ग की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी और उनका ध्यान बचत पर था क्योंकि वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं रहते थे। खर्चों के रुझान से यह दिखता है कि भारतीय अब स्वयं और अपने देश को लेकर अधिक आत्मविश्वास से भरे हैं, इसलिए वे अधिक खर्च करने को तैयार हैं। वे बड़ा घर खरीद रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, विमान यात्राएँ कर रहे हैं, सार्वजनिक वाहन से चलने की जगह अब अपनी गाड़ी

ले रहे हैं और छोटी कार से बड़ी कार की ओर बढ़ रहे हैं।

मोदी सरकार ने निस्संदेह इस परिवर्तन की गति तेज करने में एक बड़ी भूमिका निभायी है। इसने समझदारी भरी वित्तीय नीतियाँ अपनायी हैं, जिनमें उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को सुधारना और करों को तर्कसंगत बनाना शामिल है। पर कुछ समुदाय मोदी सरकार से खुश नहीं हैं और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे प्रभावी रूप से यह संदेश जाये कि सरकार एक बहुलतावादी समाज के पक्ष में है।



सैम बलसारा  
चेयरमैन, मेडिसन वर्ल्ड

लेकिन औसत से अधिक यदि हम दोनों सरकारों के दौरान महँगाई दर की दिशा देखें तो यह पता चलता है कि जहाँ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के समय महँगाई दर नीचे चल रही थी और जैसे-जैसे उनका कार्यकाल आगे बढ़ा, वैसे-वैसे महँगाई दर लगभग 4% से बढ़ कर 12% तक चली गयी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में महँगाई दर 8.33% पर थी।

वहीं मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहले तो महँगाई दर ने मनमोहन सरकार के अंतिम समय के ऊँचे स्तरों से नीचे आने का रुझान दिखाया, और 2013-14 के लगभग 9% से घट कर 2017-18 तक 3.3% पर आ गयी। अगले दो वर्षों में भी यह 4% से नीचे रही। मगर वित्त-वर्ष 2020-21 से यह 5-7% के बीच चल रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महँगाई दर के बारे में 4% का वांछित स्तर और इससे 2% तक ऊपर-नीचे यानी 2-6% का एक दायरा बना रखा है, जो उसके लिए सहनशील दायरा है। मोदी सरकार के कार्यकाल के अधिकांश समय में महँगाई दर इसी दायरे में रही है, जबकि इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के शुरुआती तीन वर्षों को छोड़ दें तो अधिकांश समय में यह इससे ऊपर रही थी।

इसलिए यह समझा जा सकता है कि मोदी सरकार में महँगाई दर जो भी हल्ला-गुल्ला सुनाई पड़ता है, वह राजनीतिक ज्यादा है। कारण यह है कि महँगाई की दर भले ही कम हो, पर उपभोक्ता की जेब से निकलने वाली कीमतें तो हर साल पहले से ज्यादा ही होती हैं। इसलिए महँगाई बहुत हो जाने को लेकर सरकार की आलोचना भारत

की स्वतंत्रता के बाद से अब तक विपक्ष का हथियार निरंतर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जनता महँगाई को लेकर नाराज नहीं होती। लेकिन यह नाराजगी सत्ता के लिए खतरा तब बनती है, जब महँगाई बढ़ने की दर एकदम बेकाबू हो गयी हो और उसके साथ ही जनता को नाराज करने वाली कुछ और बातें जुड़ने लग जायें। फिलहाल, ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती है।

### बेरोजगारी की चुनौती

रोजगार की स्थिति सरकारों के लिए एक आर्थिक चुनौती भी रहती है और राजनीतिक चुनौती भी। अर्थव्यवस्था के कमजोर या मजबूत होने से रोजगार की स्थिति में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन कई बार सत्ता-परिवर्तन का भी वाहक बन जाता है। मगर वास्तव में देश में रोजगार की स्थिति क्या है, इसे मापना और आँकना बड़ा मुश्किल और विवादास्पद कार्य है। कारण यह है कि हमारे देश में रोजगार के, या बेरोजगारी के एकदम सटीक आँकड़े निकालने की ऐसी प्रणाली बनी ही नहीं है, जो देश की संपूर्ण श्रमशक्ति को अपने दायरे में समेट सके। ऐसे में रोजगार का तस्वीर का चित्रण अंशों के द्वारा उस हाथी के वर्णन जैसा हो जाता है, जिसमें कोई अंधा हाथी की सूँड़ पकड़ कर उसे अजगर बताये और कोई दूसरा अंधा उसके पाँव पकड़ कर उसे खंभा बताये।

हमारे सामने बेरोजगारी के आँकड़ों का एक स्रोत है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन चलने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सर्वेक्षण (एनएसएसओ)। इसके अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों

के लिए बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 के दौरान घट कर 6.8% हो गयी, जो एक साल पहले 8.2% थी। इससे लगता है कि बीते वित्त-वर्ष में रोजगार की स्थितियों में सकारात्मक बदलाव हुआ है।

लेकिन यदि हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आँकड़ों को लें, तो इसके नवीनतम आँकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जून 2023 के 8.45% से घट कर जुलाई 2023 में 7.95% पर आयी है। यदि सीएमआईई के आँकड़ों के अनुसार बीते वर्षों में हम बेरोजगारी दर को देखें, तो यह वर्ष 2008 से लेकर 2019 तक लगभग 5.5% पर रही है। यह 2008 में 5.41% पर थी और 2019 में 5.27% रही थी। मगर 2020 में कोरोना महामारी के बीच बेरोजगारी दर एकदम बढ़ कर 8% हो गयी। उसके बाद यह 2021 में 5.98%, 2022 में 7.33% और 2023 की ताजा स्थिति के अनुसार 7.95% पर है।

### ईपीएफओ के आँकड़ों का सच

श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) के ताजा आँकड़े देखें तो इस वित्त-वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान 60,33,296 लोग इस संगठन से जुड़े हैं। यह संख्या पिछले कुछ वित्त-वर्षों में तेजी से बढ़ी है। जहाँ 2018-19 में 61,12,223 लोग इससे जुड़े, वहीं 2019-20 में 78,58,394 और फिर 2020-21 में 77,08,375 लोग जुड़े। वित्त-वर्ष 2021-22 से यह संख्या एक करोड़ से ऊपर जाने लगी है और 2021-22 में 1,22,34,625, जबकि 2022-23 में 1,38,51,689 रही है।

ईपीएफओ के रोजगार आँकड़ों के आधार पर हम यूपीए बनाम एनडीए की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ईपीएफओ ने पहली बार अप्रैल 2018 में ही नये सदस्यों के मासिक आँकड़े जारी करना आरंभ किया, जिसमें सितंबर 2017 के आगे के आँकड़े हैं।

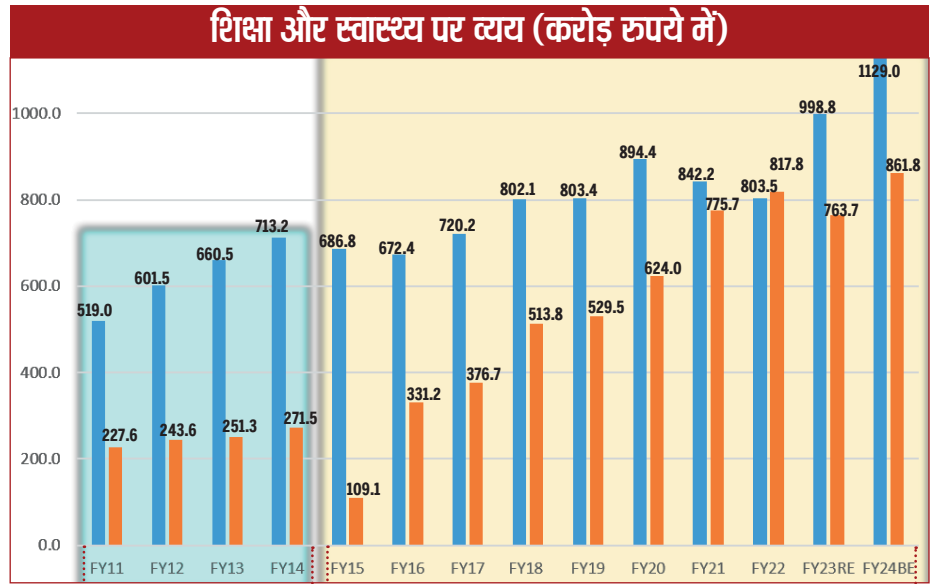
ईपीएफओ के आँकड़ों को जहाँ सरकार संगठित क्षेत्र में नये रोजगार सृजन के सबूत के तौर पर प्रस्तुत करती है, वहीं इसे नकारने वालों की भी कमी नहीं है। स्पष्ट रूप से, इसे नकारने वालों में राजनीतिक विरोधी और ऐसे अर्थशास्त्री अधिक हैं, जो इस सरकार की आर्थिक नीतियों से सहमत नहीं रहते हैं। हमें इन दोनों के बीच में से सत्य की ओर पहुँचना होगा।

जहाँ सरकारी पक्ष यह बतायेगा कि 2023-24 के इन प्रथम चार महीनों में 60 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए, वहीं आलोचक यह बतायेंगे कि इनमें से सभी लोग पहली बार ईपीएफओ से नहीं जुड़े हैं, यानी पहली बार ईपीएफओ से जुड़ने वालों की संख्या कम है। और उनमें भी 18-25 आयु-वर्ग के लोगों का प्रतिशत और भी कम है।

इस तरह वास्तव में नये रोजगार की संख्या ईपीएफओ की ओर से प्रस्तुत शुद्ध वृद्धि की संख्या काफी कम रहने का अंदेशा जताया जाता है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के तहत ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों-कर्मचारियों के लिए भी पीएफ अंशदान अनिवार्य बनाये जाने के चलते अब बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के ईपीएफओ से जुड़ने की बात कही जाती है, जो पहले असंगठित मजदूर के रूप में काम करते रहे हैं।

लेकिन इन सारे तर्कों के बाद भी यदि 2018-19 में 61.12 लाख लोगों की तुलना में 2022-23 के दौरान 1.39 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक बड़ी संख्या में लोगों को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला है। एक बात समझनी जरूरी है कि ईपीएफओ किसी महीने या साल में शुद्ध रूप से सदस्यों की संख्या में वृद्धि को बताता है, यानी जुड़ने वालों की कुल संख्या में से हटने वालों की संख्या घटाने के बाद बची संख्या।

हाल ही में एसबीआई रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि वित्त-वर्ष 2019-20 से 2022-23 के चार वित्त-वर्षों में 4.86 करोड़ शुद्ध नये ईपीएफओ सदस्य बने। इनमें से दोबारा जुड़ने वाले सदस्यों और असंगठित श्रमिकों के औपचारिक क्षेत्र से जुड़ने को समायोजित करने के बाद इन चार वर्षों में शुद्ध रूप से नयी (पहली) नौकरियाँ 2.27 करोड़ थीं। इस तरह



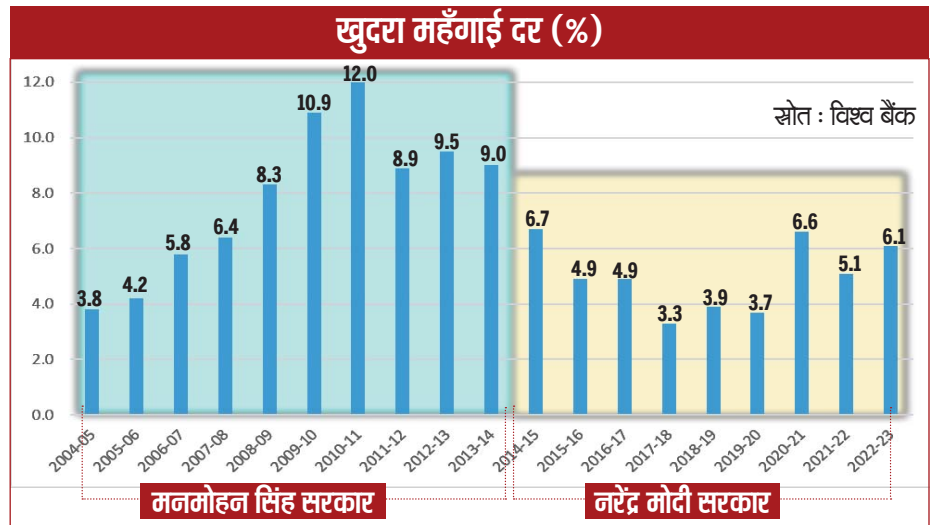
मनमोहन सिंह सरकार

नरेंद्र मोदी सरकार

शिक्षा

स्वास्थ्य

स्रोत : इंडिया रेटिंग्स



मनमोहन सिंह सरकार

नरेंद्र मोदी सरकार

स्रोत : विश्व बैंक

कुल शुद्ध नये सदस्यों में से पहली बार नौकरी में आये लोगों की संख्या 47% थी।

दूसरी बात यह है कि पहली बार रोजगार में आने वालों की संख्या को देखने के लिए केवल 18-25 वर्ष के आयुवर्ग के आँकड़ों को देखना बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। इससे अधिक आयुवर्ग के लोग भी पहली बार नौकरी पा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि यदि रोज-रोज काम तलाशने वाला एक दिहाड़ी मजदूर मान लें किसी निर्माण कंपनी में रोजगार पाकर औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है, तो क्या यह उसके लिए अधिक आय और रोजगार की सुरक्षा बढ़ने का संकेत नहीं है?

और हाँ, नयी पेंशन योजना (एनपीएस) के आँकड़े भी तो जोड़ने होंगे! एसबीआई रिसर्च

की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में एनपीएस के कुल 8.24 लाख नये सदस्य बने। इनमें सबसे अधिक 4.64 सदस्य राज्य सरकारों के, 2.30 लाख सदस्य गैर-सरकारी क्षेत्र से और 1.29 लाख सदस्य केंद्र सरकार के थे। यह रिपोर्ट बताती है कि ईपीएफओ और एनपीएस को मिला कर 2019-20 से 2020-23 तक के चार वित्त-वर्षों में कुल 5.2 करोड़ नौकरियाँ सृजित हुईं।

रोजगार के संदर्भ में एक और योजना के असर को देखना जरूरी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने 1.37 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है, जिससे वे अधिक उत्पादकता वाले रोजगार में जा सकें और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ें।



## रुपये का निरंतर अवमूल्यन

यदि हम 1947 में भारत की स्वतंत्रता से अब तक डॉलर की तुलना में रुपये की स्थिति देखें, तो लगातार रुपये के मूल्य में कमी और डॉलर के महँगे होते जाने का ही रूझान दिखता है। वर्ष 1947 में एक डॉलर 3.30 रुपये के बराबर था। वर्ष 2005 में डॉलर की विनिमय दर 43.50 रुपये पर थी, जो 2014 में 60.95 रुपये हो गयी। इस समय यह लगभग 83 रुपये पर है। यदि हम प्रतिशत में देखें तो इन दोनों सरकारों के समय में रुपये के अवमूल्यन की गति में कोई नाटकीय अंतर नहीं आया है।

इस निरंतर अवमूल्यन के पक्ष में तमाम कारण बताये जाते हैं और उनमें से एक मुख्य कारण है कि निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी रहने के लिए ऐसा जरूरी है। मगर रुपये का कमजोर होना सत्ताधारी दल को राजनीतिक रूप से कमजोर बनाता है, या कम-से-कम विपक्षी दलों को आलोचना का एक बिंदु देता है।

इसीलिए हम याद कर सकते हैं कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में यूपीए सरकार पर हमला करते थे तो रुपये की कमजोरी को भी एक मुद्दा बनाते थे। हाल में कांग्रेस के नेताओं के बयान भी इसी तर्ज पर रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में रुपये में आयी गिरावट को भुला कर मोदी सरकार में रुपये की गिरावट को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है।

वहीं विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखें तो 2003-04 के अंत में भारत के पास 113.00 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 2013-14 के अंत में 303.67 अरब डॉलर का हो गया। मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर 2022-23 के अंत में यह 578.45 अरब डॉलर पर था। वहीं यदि मोदी सरकार के सत्ता में आने के समय से ही देखें, तो 23 मई 2014 को समाप्त सप्ताह में यह 313 अरब डॉलर का था, जो अभी ताजा आँकड़ों के अनुसार 22 सितंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में 590.7 अरब डॉलर पर है।

मोदी सरकार की आलोचना में कुछ समय पहले कांग्रेस की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि नौ वर्षों में भारत का प्रति व्यक्ति कर्ज ढाई गुना से अधिक हो गया। यह आरोप सही है, पर आधा सच है। कांग्रेस ने अपने हिस्से के सच की बात नहीं की। ताजा आँकड़ों के अनुसार मार्च

2023 के अंत में घरेलू और विदेशी मिला कर केंद्र सरकार का कुल ऋण 155.6 करोड़ रुपये का था। मार्च 2014 के अंत में यह राशि 55.87 लाख करोड़ रुपये थी, यानी इन नौ वर्षों में इसमें 2.78 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन कांग्रेस ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मार्च 2004 के अंत में केंद्र सरकार का ऋण लगभग 17 लाख करोड़ रुपये का था और इस तरह मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों में यह तिगुने से अधिक हो गया था।

### ‘लोक कल्याण मार्ग’ पर मोदी सरकार

अतिशय गरीबी (एक्सट्रीम पोवर्टी) के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों यानी 2.15 डॉलर प्रति व्यक्ति दैनिक आय (2017 पीपीपी) के आधार पर विश्व बैंक का आकलन है कि वर्ष 2011 में भारत में अतिशय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 23% थी, जो 2019 में घट कर

**गरीबों की मदद के मामले में मोदी सरकार जिन आँकड़ों से अपनी पीठ थपथपाती है, उनमें 80 करोड़ लोगों मुफ्त अनाज देना, नौ वर्षों में तीन करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास देना, स्वच्छ भारत योजना के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण और 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुँचाना शामिल हैं। वहीं आधी आबादी को राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में करने के लिए सरकार बताती है कि इसने उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं, जिनसे महिलाओं को अपनी रसोई में धुएँ से मुक्ति मिली है। मुद्रा योजना में 27 करोड़ महिला लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराये गये। ये मोदी सरकार की ऐसी योजनाएँ हैं, जिनकी तुलना यूपीए के दौर से नहीं हो सकती। उज्ज्वला योजना का आरंभ ही मोदी सरकार के आने के बाद मई 2016 में हुआ।**

10% रह गयी। वहीं मनरेगा योजना में उपलब्ध कराये गये कार्यदिवसों का औसत यूपीए सरकार के 10 वर्षों में 208 करोड़ रहा था, जबकि मोदी सरकार के नौ वर्षों में यह वार्षिक औसत 248 करोड़ है।

गरीबों की मदद के मामले में मोदी सरकार जिन आँकड़ों से अपनी पीठ थपथपाती है, उनमें 80 करोड़ लोगों मुफ्त अनाज देना, नौ वर्षों में तीन करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास देना, स्वच्छ भारत योजना के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण और 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुँचाना शामिल हैं।

वहीं आधी आबादी को राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में करने के लिए सरकार बताती है कि इसने उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं, जिनसे महिलाओं को अपनी रसोई में धुएँ से मुक्ति मिली

है। मुद्रा योजना में 27 करोड़ महिला लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराये गये। ये मोदी सरकार की ऐसी योजनाएँ हैं, जिनकी तुलना यूपीए के दौर से नहीं हो सकती। उज्ज्वला योजना का आरंभ ही मोदी सरकार के आने के बाद मई 2016 में हुआ। इसी तरह मुद्रा योजना का आरंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ।

इसी तरह किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ फरवरी 2019 में हुआ। मोदी सरकार नौ वर्षों में कृषि बजट को बढ़ा कर छह गुना करने के अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.33 लाख करोड़ रुपये के दावों के निपटान और नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, पीएम सिंचाई योजना, ई-नाम आदि के माध्यम से किसानों के हित के लिए काम करने के दावे करती है।

गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने दो योजनाएँ चला रखी हैं - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। शहरी योजना में अब तक 1.19 करोड़ आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 1.13 करोड़ आवासों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है और 77.1 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। ग्रामीण योजना में 2.95 करोड़ आवासों की स्वीकृति हो चुकी है और इनमें से 2.45 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

लोगों की जीवन-शैली में आने वाले बदलावों के कुछ अन्य संकेतकों को देखें तो वर्ष 2023 की आर्थिक समीक्षा (इकोनॉमिक सर्वे) के अनुसार, देश में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मनमोहन सिंह सरकार बनने से पहले 2003-04 में 9.9 किलोग्राम थी, जो उनकी सरकार के अंतिम वित्त-वर्ष 2013-14 में 16.8 किलोग्राम हो गयी और 2021-22 में इसकी अनुमानित मात्रा 21.5 किलोग्राम थी। कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2003-04 के 31 मीटर से बढ़ कर 2013-14 में 36.2 मीटर और 2021-22 में 48.1 मीटर पर पहुँची। चाय की उपलब्धता इन वर्षों में 662 ग्राम से बढ़ कर 744 ग्राम और फिर 872 ग्राम तक पहुँची है। घरेलू बिजली की उपलब्धता 2003-04 के 83.6 किलोवाट प्रति घंटे से बढ़ कर 2013-14 में 162.0 किलोवाट और 2020-21 में 244.1 किलोवाट रही है।

# 4 साल बाद भारत होगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 10 वर्षों में हुआ बुनियादी ढाँचे में अभूतपूर्व निवेश

**क्या यह कहना सही होगा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आया है?**

पिछले 10 वर्षों में भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास की ओर लंबे कदमों से बढ़ना परिवर्तनकारी रहा है और देश पाँच लाख करोड़ (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए तैयार है। मार्च 2023 तक के वास्तविक (ऐक्चुअल) जीडीपी आँकड़ों के आधार पर संभावना बनती है कि भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। वर्तमान विकास दर के अनुसार भारत को वर्ष 2027 में जापान और जर्मनी दोनों से आगे निकल जाना चाहिए। वर्ष 2047 तक हम एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होंगे, जो किसी भी मानक से एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।

**बीते दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना आप उससे पहले के 10 वर्षों से किस तरह करेंगे?**

वैश्विक बाधाओं और सख्त घरेलू मौद्रिक नीति के बाद भी यदि भारत की विकास दर 6.5% से 7% के बीच रहने के अनुमान हैं, वह भी बिना किसी आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) के, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में निहित दृढ़ता, वापस सँभल सकने की क्षमता और विकास को गति देने वाले कारकों में नयी ऊर्जा को दिखाता है।

इस दशक में भारत की वृद्धि मुख्यतः निजी खपत (प्राइवेट कंजप्शन) और पूँजी निर्माण पर आधारित रही है। निजी खपत 2022-23 में जीडीपी का 58.5% रही है, जो 2013-14 के बाद से अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है। इसे व्यापार (ट्रेड), होटल एवं परिवहन (ट्रांसपोर्ट) में फिर से मजबूती लौटने से सहारा मिला है।

**बीते दोनों दशक वैश्विक उथल-पुथल से भरे रहे हैं।**

**पिछले दशक में वैश्विक वित्तीय संकट आया था।**

**इस दशक में कोरोना के चलते विश्व अर्थव्यवस्था में सुस्ती आयी और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते चार दशकों की सबसे ऊँची वैश्विक महँगाई आयी। इन दोनों दशकों में वैश्विक घटनाओं को लेकर भारत की प्रतिक्रिया की तुलना आप किस तरह करेंगे?**

हाँ, बीते दो दशकों में भारत ने दो सबसे बड़े संकट झेले हैं - 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और 2020 में कोविड-19 की महामारी। लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े हैं और देश को ऐसे संकटों से सहजता से निपटने में मदद की है।

**यह मोदी सरकार का दसवाँ वर्ष चल रहा है। ऐसे में यह आकलन जरूरी लगता है कि बीते 10 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति कैसी रही है और इसकी तुलना अगर उससे पहले के दशक से करें तो कैसी तस्वीर बनती है। प्रस्तुत है इस बारे में कुछ अहम प्रश्नों पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के उत्तर।**

भारत ने बीते 20 वर्षों में 6% से अधिक की विकास दर से बढ़ते हुए अपनी दृढ़ता दिखायी है। पिछले दशक में भारत का बैंकिंग क्षेत्र अनियंत्रित एनपीए (फैंसे ऋणों) के जंजाल में फँसा था। इस क्षेत्र को एनपीए संकट से बाहर निकालने में किन बातों ने मदद की, और आगे इस तरह का संकट दोबारा आने से रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है?

वर्ष 2015 में स्वच्छ और पूरी तरह से प्रावधान (प्रोविजनिंग) की हुई बैंक बैलेंस शीट के लिए संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) शुरू की गयी थी। इसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के उच्च स्तरों का पता चला। एक्यूआर होने और उसके बाद बैंकों द्वारा पारदर्शी तरीके से एनपीए को पहचानने के चलते तनावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके पहले पुनर्गठित ऋणों के लिए उपलब्ध लचीलेपन के चलते उस समय तक तनावग्रस्त ऋणों पर अपेक्षित नुकसानों के प्रावधान नहीं किये गये थे। उनका एनपीए में वर्गीकरण होने के बाद उनके लिए प्रावधान किये गये। इसके अलावा, तनावग्रस्त ऋणों के पुनर्गठन की ऐसी सभी योजनाएँ वापस ले ली गयीं।

सरकार ने चार आर की एक व्यापक रणनीति लागू की। इसमें पारदर्शी ढंग से एनपीए की पहचान (रेकग्निशन), तनावग्रस्त खातों से वसूली और समाधान (रिजोल्यूशन), सरकारी बैंकों को नयी पूँजी (रीकैपिटलाइजेशन) और सरकारी बैंकों में सुधार (रिफॉर्म) किये गये। इन सुधारों में एक विस्तृत वित्तीय परितंत्र बनाने पर ध्यान दिया गया, जिससे एक उत्तरदायी एवं स्वच्छ प्रणाली बने। चार आर की रणनीति के तहत व्यापक कदम उठाये गये, जिससे सरकारी



बैंकों के एनपीए घटें। इन कदमों में आईबीसी लागू करना और सरकारी बैंकों में सुधार के कार्यक्रम के तहत बड़े सुधार करना शामिल थे। इन सबसे एनपीए मुद्दे को सुलझाने में मदद मिली।

**कहा जाता है कि इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) ने एनपीए समस्या सुलझाने की दिशा में एक बड़ी भूमिका निभायी। लेकिन कुछ लोग इस बात पर आईबीसी की आलोचना करते हैं कि इसमें वसूली (रिकवरी) की दर बीआईएफआर के समय की तुलना में कम रही है। क्या यह आलोचना सही है?**

वर्ष 2016 में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) लागू होने से भारत में तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के तौर-तरीकों का पूरा परिदृश्य बदल गया। हालाँकि हाल के वर्षों में इस तंत्र के माध्यम से किये गये दावों की तुलना में वसूली की दर में गिरावट आयी है। यह कमी ज्यादातर महामारी से संबंधित व्यवधानों को दर्शाती है। वसूली की दर कई कारकों पर निर्भर है, जैसे कि समग्र व्यापक आर्थिक वातावरण, उस इकाई (कर्जदार) और उसके क्षेत्र के लिए अनुमानित विकास संभावनाएँ और उस इकाई के आंतरिक मूल्य में कितनी गिरावट हुई है। जैसे-जैसे व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये कारक वित्तीय समाधान के लिए अनुकूल होते जायेंगे।

बैंकों के पास कई तरीके हैं, जिनके माध्यम से तनावग्रस्त संपत्तियों का समाधान किया जा सकता है। चूँकि कोविड-19 के दौरान एक साल के निलंबन के बाद ही नये दिवालियापन के मामलों को स्वीकार किया जा सकता था, इसलिए 2021-22 के दौरान आईबीसी के तहत नये मामलों में 65% की वृद्धि हुई। यद्यपि लोक

अदालतों और सरफेसी अधिनियम के तहत लाये जाने वाले मामलों की संख्या में क्रमशः 336% और 335% की वृद्धि हुई, लेकिन राशि के मामले में आईबीसी प्रक्रिया सबसे आगे रही।

आईबीसी में शामिल राशि 2021-22 में 1,99,250 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 23.8% (या 47,421 करोड़ रुपये) की बैंकों ने वसूली कर ली है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एससीबी) द्वारा आईबीसी के माध्यम से 2021-22 में वसूली गयी राशि 2020-21 में वसूले 27,311 करोड़ रुपये से काफी अधिक थी। इस बीच, सरफेसी अधिनियम के माध्यम से वसूली गयी राशि 2021-22 के दौरान 27,349 करोड़ रुपये रही, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 27,686 करोड़ रुपये थी।

**भारत की आर्थिक सेहत के विभिन्न मापदंडों, जैसे जीडीपी वृद्धि दर, महंगाई, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा (सीएडी), पूँजी निर्माण (कैपिटल फॉर्मेशन) आदि पर आप इस दशक की तुलना पिछले दशक से किस तरह करेंगे?**

हमने पिछले दशक में 2008 के वित्तीय संकट का सामना किया और इस दशक में 2020 की कोविड महामारी का। वर्ष 2004 से 2014 के बीच हमने ऊँची विकास दर के साथ महंगाई झेली, जिसमें विशाल पूँजी प्रवाह (कैपिटल इन्फ्लो) और सरकारी प्रोत्साहन का योगदान था। इस दशक 2013-2023 में हमने स्थिर विकास दर के साथ कम महंगाई और मजबूत वैदेशिक क्षेत्र (एक्सटर्नल सेक्टर) देखा है।

**क्या भारत ने बीते 10 वर्षों में बुनियादी ढाँचा विकास के क्षेत्र में एक बड़ी छलाँग लगायी है?**

सरकार ने आधुनिक बुनियादी ढाँचे में पिछले दशक में अभूतपूर्व निवेश करके देश को नयी ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। किसी देश के बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता उसके आर्थिक भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार ने बुनियादी ढाँचे को विकास के अपने एजेंडा में सबसे आगे और केंद्र में रखा है।

पिछले दशक में देश में सभी क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ है। 53,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) जोड़े गये। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्क लगभग 99% तक पहुँच गया है। राजमार्ग निर्माण की गति 37 किलोमीटर प्रतिदिन तक हो गयी है।

भारतीय रेलवे की क्षमता में भी लाइन दोहरीकरण और विद्युतीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस

‘मेक इन इंडिया’ की सफलता की एक प्रमुख कहानी है। इस समय 25 वंदे भारत ट्रेनें चालू हो चुकी हैं और अगले तीन वर्षों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण किया जाना है। पिछले 10 वर्षों में मेट्रो रेल परियोजनाएँ 20 शहरों तक पहुँच चुकी हैं। उड़ान परियोजना के माध्यम से विमानन क्षेत्र को किफायती और सुलभ बनाने के लिए कदम उठाये गये। पिछले 10 वर्षों में 74 नये हवाई अड्डे बना कर उनका संचालन आरंभ कर दिया गया है।

इसके अलावा, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इस अवधि के दौरान देश में चिनाब ब्रिज बना जो दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल है। अटल सुरंग बनी जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसके अलावा लंबे समय से लंबित कई परियोजनाओं को पूरा किया गया, जैसे सरयू नहर, पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आदि।

प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश में विकास गतिविधियों में तेजी लाना, एकल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से समग्र योजना निर्माण को संस्थागत बनाना और अंतर-विभागीय समन्वय बनाना है। हाल में जिन बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उनसे 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देश की यात्रा को गति मिल रही है।

**बीते 10 वर्षों में बड़े नीतिगत निर्णय और संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जैसे नोटबंदी, जीएसटी लागू करना। कुछ अर्थशास्त्री इनकी कड़ी आलोचना भी करते हैं। अब इन सुधारों से उड़ी धूल छँट जाने के बाद इनका आकलन आप किस तरह करते हैं?**

कभी-कभी सुधारों को लागू करना कठिन होता है, हालाँकि वे आवश्यक होते हैं। ये दोनों सुधार भी ऐसे ही थे, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। जीएसटी को जब लागू किया गया, उस समय इसकी आलोचना की गयी थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसका सफल क्रियान्वयन हुआ है। जीएसटी लागू होने के केवल छह वर्षों में देखें तो औसत मासिक जीएसटी राजस्व 2017-18 के 90,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्तमान वित्त-वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया है। इसने पारदर्शिता लाने का काम किया है और कर चोरी भी काफी हद तक रुकी है।

**यूपीए के शासनकाल की आलोचना रोजगारविहीन वृद्धि (जॉबलेस ग्रोथ) के लिए की जाती थी। क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में भी वही स्थिति रही है, या इसमें कुछ सुधार हुआ है?**

यदि हम दोनों सरकारों के नौ वर्षों, यानी 2024 से 2013 और 2014 से 2023 की तुलना करें, तो मोदी सरकार ने प्रभावशाली ढंग से नौ लाख सरकारी नौकरियाँ सृजित की हैं, जबकि यूपीए सरकार ने 6 लाख नौकरियाँ दी थीं। प्रधानमंत्री की रोजगार मेला पहल काफी सफल रही है, जिसमें ऐसे हर अभियान में 70,000 से अधिक नियुक्ति-पत्र जारी किये गये।

तीन प्रमुख सरकारी संस्थाओं में से यूपीएससी ने 2004-13 के दौरान 45,431 आवेदकों की तुलना में 2014-23 के बीच 50,906 आवेदकों की भर्ती की। एसएससी की भर्तियाँ इन अवधियों में 2,07,563 की तुलना में बढ़ कर 4,00,691 हो गयीं। आरआरबी की ओर से दी गयी नौकरियों की संख्या इस दौरान 3,47,251 से बढ़ कर 4,30,592 हो गयीं।

**क्या आपको लगता है कि आने वाला दशक (या अगली सदी भी) भारत के नाम है, या ऐसी बातें केवल मार्केटिंग का हिस्सा हैं?**

वैश्विक परिदृश्य को लेकर अभी भले ही कुछ संशय हो, लेकिन भारत एक स्वस्थ विकास दर हासिल करता रहेगा। वैश्विक एजेंसियाँ 2023-24 में भारत की विकास दर 6-6.5% के बीच रहने के अनुमान जता रही हैं और अगले दशक के लिए उनके अनुमान 5-7% के हैं। भारत अगले दशक में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनने वाला है।

यह अन्य उभरते बाजारों (इमर्जिंग मार्केट्स) और यहाँ तक कि मोटे तौर पर वैश्विक बाजारों को भी पीछे छोड़ देगा। इसका कारण है भारत में युवा और ऊर्जावान कार्यबल, मध्यम वर्ग का विस्तार और बढ़ती उपभोक्ता क्रय शक्ति के आधार पर मजबूत आर्थिक विकास। विकास को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए संरचनात्मक सुधार लाने की दिशा में सरकार के प्रयास मजबूत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

यूपीआई के सफल कार्यान्वयन के साथ डिजिटल परिवर्तन का भी यहाँ उल्लेख किया जाना चाहिए। देश की तकनीकी प्रगति के साथ बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र, अक्षय ऊर्जा (रीन्यूएबल एनर्जी), बिजली वाहनों (ईवी) और खास कर पीएलआई के चलते विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में बन रहे निवेश के अवसरों से उच्च विकास दर पाने के पर्याप्त संभावनाएँ दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट आय में मजबूत वृद्धि, मजबूत बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट प्रशासन (गवर्नेंस) में सुधार से निरंतर मूल्य निर्माण (वैल्यू क्रिएशन) का एक ठोस आधार तैयार हुआ है।



# बदलती तस्वीर में हैं भारत की तरक्की के साक्ष्य

वर्षा 2014-2024 में भारत का उत्थान भारत शाइनिंग 2004 के जैसा है, जो कुछ वर्षों के बाद टंडा पड़ गया था

1

पिछले नौ वर्षों में वैसा विकास किन कारणों से संभव हुआ, जो पिछले 60 साल वर्षों में देखे गये विकास के समतुल्य रहा

2

चीन में 20वीं सदी के अंतिम वर्षों और 21वीं सदी के आरंभिक वर्षों में तेजी से विकास हुआ, पर अब वह इस विकास की कीमत चुका रहा है। क्या भारत का भी ऐसा ही भविष्य होगा

3



वर्ष 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद से क्या भारत के विकास की कहानी में कोई नाटकीय मोड़ आया है, या शाइनिंग इंडिया की तरह विकास भी छलने वाला है? बीते एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था में आये बदलावों को रेखांकित कर रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ **सिद्धार्थ रस्तोगी**।

**वर्तमान** सरकार की नीयत, सोच एवं कार्यों और वर्तमान समय में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उन्हें संक्षेप में संस्कृत के दो सरल सूत्रों में समझा जा सकता है।

## निष्ठा धृति: सत्यम्

अर्थात् समर्पण, दृढ़ता और सच्चाई - जो दृढ़, निश्चल और अथक संकल्प के साथ अपने अंतिम लक्ष्य के प्रति समर्पित, प्रतिबद्ध और अविचलित रहता है, वही सफलता और सत्य की जीत का अनुभव करता है।

## लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

अर्थात् इस धरती पर सभी खुश और स्वतंत्र रहें, और हमारे जीवन से जुड़े विचार, शब्द और क्रियाएँ हमारे आस-पास सभी की खुशहाली और स्वतंत्रता में योगदान दें।

दृढ़ता और समाज के अंतिम छोर तक बदलाव लाना, सामाजिक-आर्थिक अनुक्रम की सबसे कमजोर कड़ी को ठीक करना ही मौजूदा सरकार का वह निर्णायक बिंदु है, जो इसे अभूतपूर्व और अद्वितीय बनाता है।

सबसे पहले कुछ साक्ष्यों का आकलन करते हैं, और तब इसके पीछे के कारणों को समझेंगे।

1. **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)** : आजादी के बाद 67 साल लगे भारत को दो लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, जबकि पिछले नौ साल में ही अर्थव्यवस्था ने

2.75 खरब डॉलर का स्तर पार कर लिया। यानी कोविड 19 के बावजूद इसमें नौ वर्षों में लगभग 38% की उछाल आयी है।

2. **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)** : इसके आँकड़े बताते हैं कि शेष विश्व का लंबे समय के निवेश के लिए हमारे देश पर भरोसा कितना है। भारत में आने वाला एफडीआई वर्ष 2013 में 22 अरब डॉलर से बढ़ कर 2023 में 46 अरब डॉलर हो गया है। यानी हमारे यहाँ निवेश की गयी उनकी पूँजी से कमाई होने का उनका भरोसा, आत्मविश्वास और आस्था दोगुनी हो गयी है।

3. **घरेलू गैस (एलपीजी)** : 2014 तक के 67 वर्षों में भारत में 14.52 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन थे। यह संख्या मार्च 2023 तक पिछले नौ साल में दोगुने से अधिक बढ़ कर 31.36 करोड़ पर पहुँच गयी। स्वच्छ ऊर्जा और इस्तेमाल में आसानी से न सिर्फ गृहलक्ष्मी की दिक्कतें कम हुईं, बल्कि इससे दमा, कंठ की सूजन (ब्रॉन्काइटिस) और धुआँ-जनित बीमारियों से मुक्ति के साथ ही उनकी संपूर्ण सेहत में सुधार हुआ।

4. **सड़कें और राजमार्ग** :

• वित्त-वर्ष 2013-14 तक भारत में कुल 18,371 किलोमीटर लंबाई के चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग थे। वित्त-वर्ष 2022-23 में चार लेन के राजमार्गों की लंबाई 44,654 किलोमीटर का हो गया है। इस तरह राजमार्गों

में नौ साल में ढाई गुना विस्तार हुआ है, जो अद्भुत है।

• देश में सड़कों का कुल नेटवर्क 67 साल में 91,287 किलोमीटर का था, जो इन नौ वर्षों में 60% बढ़ कर 145,240 किलोमीटर हो गया है। यह चीन समेत दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है

• सवाल है कि क्या बुनियादी ढाँचे पर यह खर्च वित्तीय रूप से तर्कसंगत लगता है?

यहाँ परिमाणीकरण भी कार्यान्वयन जितना ही महत्वपूर्ण है। वित्त-वर्ष 2013-14 तक फास्टैग+ (FASTag+) सहित सड़क टोल से राजस्व 4,770 करोड़ रुपये का था, जो वित्त-वर्ष 2022-23 तक यानी अगले 9 वर्षों में 10 गुना से अधिक बढ़ कर 41,342 करोड़ रुपये पर पहुँच गया।

• इसके अलावा, सार्वजनिक धन से बुनियादी ढाँचे के निर्माण से न केवल सरकार के राजस्व में इजाफा हुआ, बल्कि टोल प्लाजा पर इंतजार के समय को कम करके आम लोगों और व्यवसायों को बहुमूल्य बचत भी हुई।

वर्ष 2014 में टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए इंतजार का औसत समय 734 सेकेंड या 12 मिनट से ज्यादा था। वर्ष 2023 में यह घट कर मात्र 47 सेकेंड रह गया है, यानी इंतजार की अवधि में 94% कमी आयी है। सरकार इसे 30 सेकेंड पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंतजार की

अवधि में कमी से 70,000 करोड़ रुपये मूल्य का ईंधन बर्बाद होने से बचाया जा सका, जिसका लाभ देश के नागरिकों को मिला, जिनके धन का इस्तेमाल बुनियादी ढाँचा बनाने में किया गया था।

#### 5. बंदरगाह :

- 2014 में भारत में सरकार द्वारा संचालित 12 बड़े बंदरगाह थे और 200 छोटे बंदरगाह थे, जिनका संचालन राज्य सरकारें करती थीं। इनमें से ज्यादातर पुराने ढंग के थे और इनमें जाम लगने की समस्या थी। ये बंदरगाह खराब बुनियादी ढाँचे, कमजोर संचालन और तकनीक अपनाने में पीछे रहने की समस्या से जूझ रहे थे।
- समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने सबसे पहले संविधान संशोधन कर दशकों पुराने मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट 1958 को हटा कर उसके स्थान पर मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट 2020 और मेजर पोर्ट्स अधिनियम 2020 को लाने का काम किया। इन दोनों का मकसद देश के बंदरगाहों पर निर्णय लेने और इनके प्रशासन को आसान बनाना था।
- इसके बाद 6.6 अरब डॉलर के कुल खर्च से 68 बंदरगाह परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया गया और 6 नये विशाल बंदरगाह बनाये गये। सागरमाला के तहत अब तक 99,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 194 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 2.12 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 218 परियोजनाएँ 2025 तक पूरी हो जायेंगी।
- बंदरगाहों से संबंधित इन पहलों से पूरे तंत्र की क्षमता बढ़ी है। साथ ही, बंदरगाहों पर टर्नअराउंड का समय 2013-14 में 44.70 घंटे से 40% घट कर 2022-23 में 26.58 घंटे का हो गया है। बंदरगाहों पर आयातक या निर्यातक को जितना अधिक समय लगता है, उतना ही हर मिनट के हिसाब से उसका खर्च बढ़ता है। इसलिए उत्पादन और निर्यात करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने और व्यवसायों को लाभ पहुँचाने वाले विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए बंदरगाहों की अधिक दक्षता का अर्थ है अधिक बचत और कम लागत।

- इसके अतिरिक्त, 2013-14 में देश के प्रमुख 12 बंदरगाहों की माल ढुलाई क्षमता 80 करोड़ टन प्रति वर्ष थी, जो मार्च 2022 तक दोगुना बढ़ कर 159.8 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गयी है। इस अंतर्हीन सूची में रेलवे, रक्षा, दूरसंचार, ड्रोन उत्पादन और अनेक अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा सृजन शामिल है। पर जो मूल बदलाव

आया है, उसे पलटा नहीं जा सकता है और यह आने वाली पीढ़ियों को सक्षम बनायेगा।

अब इस न पलटे जा सकने वाले बदलाव के उस पहलू को समझते हैं, जिसे भारत ने अब तक देखा है और आगे भी देख रहा है।

### 1. पूँजी लागत में कमी और पूँजी का लोकतंत्रीकरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभदेयता में बढ़ोत्तरी और उनके शेयर भावों में शानदार तेजी के बारे में सभी पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सृजित पूँजीगत व्यय हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गया है।

**क्यों? किसने इस धन की व्यवस्था की है?**

मौजूदा सरकार की पहली वित्तीय पहल या सुधार हम कह सकते हैं जन धन योजना को। अब तक 50 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिससे व्यक्तियों से संस्थानों की ओर पैसे का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जा सका है। इससे भारत की बेहतरी के लिए सदैव के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या पूँजी की औसत लागत को घटाया जा सका है।

डेढ़ दशक पहले तक एक कंपनी या कारोबार शुरू करना चुनौतीपूर्ण अनुभव हुआ करता था, क्योंकि इसके अनगिनत अनुमतियाँ लेनी होती थी और सबसे अहम बात यह कि पूँजी तक पहुँच सीमित या न के बराबर थी। यह सहूलियत सिर्फ ऐसे लोगों को उपलब्ध होती थी, जिनकी पहुँच अच्छी थी या जिनके करीबी सत्ता के गलियारों में थे। अन्य लोगों को इस तरह से कतारबद्ध किया जाता था, जैसे वे ऋण नहीं दान माँग रहे हों।

वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) की लागत कम होने और जन धन खातों के चलते वैध वित्तीय प्रणाली में भरपूर धन का प्रवाह संभव हुआ है। इससे बड़े पैमाने पर पूँजी का लोकतंत्रीकरण हुआ, और इसके चलते उद्यमशीलता की प्रवृत्ति का पुनरुत्थान हुआ है।

भारत हमेशा से उद्यमशील राष्ट्र रहा है और ब्रिटिश हुकूमत समेत अन्य आक्रमणकारियों ने पूँजीपतियों की गुलामी को जन्म दिया है। मगर इस बदलाव ने अधिक उद्यमियों का सृजन किया है, जो अपने लिए रोजी-रोटी कमाने के साथ ही दूसरों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना चाहते हैं।

### 2.2. रिसाव को रोकना और डिजिटलीकरण से पारदर्शिता का बढ़ना

2013 वह साल था जब भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज ऊँची की, अपनी तकलीफ

और गुस्से को दिखाया था। जब 2014 में नयी सरकार आयी, तो उसका पहला कदम, पहला केंद्र बिंदु और पहला निर्देश भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था।

वर्ष 2016 में नोटबंदी और उसके बाद 2023 में आंशिक नोटबंदी ऐसी पहल का परिणाम थे। इसके अतिरिक्त, रिसाव को रोकने का काम तभी जारी रह सकता है, जब पारदर्शिता और स्पष्टता हो। सभी सरकारी कार्यालयों के डिजिटलीकरण से उच्चतम स्तर की पारदर्शिता आयी है।

इसके अलावा, डिजिटलीकरण से धन की गति बढ़ी है यानी वह ज्यादा तेजी से हाथ बदल रहा है और साथ बिचौलियों को भी कम किया जा सका है, जिससे उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएँ तेज गति के साथ ही सस्ती भी हुई हैं।

### 3.3. पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) न कि परिचालन व्यय (ऑपेक्स) + समावेश

वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 100 लाख करोड़ के राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा पाइपलाइन (एनआईपी) की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए बुनियादी ढाँचे का सृजन, और एक गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) पैदा करना था, जिसमें सोच यह थी कि इससे उपभोग (कंजंप्शन), पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) और निवेश की गति मिलेगी। बहुत-से लोगों ने इसका मजाक बनाया था, लेकिन आज जब दुनिया अपने वित्तीय तंत्र के धराशायी होने के डर से जूझ रही है तो एनआईपी की बदौलत भारत मरुद्धान के रूप में अलग पहचान बना चुका है। इसके अलावा, पूँजीगत व्यय से होने वाले खर्च का चक्रीय प्रभाव सभी क्षेत्रों पर आता है, जिससे अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी प्रभावित होता है। बीते आठ-नौ साल में गरीबी को दूर करने के जो प्रयास हुए हैं, उसमें यह नजर आता है।

डिजिटलीकरण, पूँजी के लोकतंत्रीकरण और घरेलू बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था को निर्यात-मुख अर्थव्यवस्था में बदलने के तीन स्थिर स्तंभों के साथ-साथ अद्वितीय सुधारों, अपरिवर्तनीय संकल्पों और असाधारण कार्यान्वयन का मेल होने से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। यह खुद को विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने और 2047 तक अपने तीन-चौथाई परिवारों को मध्यम वर्ग में शामिल करने की ओर बढ़ेगा। यह नैतिकता, शिक्षा और उद्यमशीलता की प्रवृत्ति रखते हुए सबके लिए आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करेगा।

**मो**दी सरकार को नौ साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब कुछ महीनों में तय हो जायेगा कि भाजपा को अगले पाँच वर्षों के लिए मौका मिलेगा या नहीं। बीएसई का सूचकांक



आलोक पुराणिक  
आर्थिक समीक्षक

संसेक्स 11 सितंबर 2023 को 67,127 पर बंद हुआ। मोदी सरकार जब बनी थी, तब 26 मई 2014 को संसेक्स 24,717 पर था। इस तरह नौ साल से कुछ अधिक समय में संसेक्स 2.71 गुना हो गया। निवेश

के किसी भी मानक से यह बेहतरीन प्रदर्शन है। निवेशकों को आम तौर पर शेयर बाजार ने निराश नहीं किया।

कोरोना-काल अपवाद है। वैसी आपदा शताब्दियों में एकाध बार आती है। उस असाधारण काल में जो हुआ, वह अपवाद का विषय है। पर मोटे तौर पर शेयर बाजार में निवेशक इन नौ सालों में स्वस्थ कमाई पर बैठे होंगे, अगर उन्होंने स्ट्रेबाजी में पैसा ना लगाया होगा, तो।

शेयर बाजार से जुड़े बड़े कारोबारी (मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन) रामदेव अग्रवाल के अनुसार वर्ष 2030 तक बीएसई का सूचकांक संसेक्स दो लाख तक पहुँच जायेगा, जो अभी 67,000 के आस-पास टहल रहा है। यानी अब के मुकाबले संसेक्स तीन गुना से भी ज्यादा हो जायेगा अगले छह सालों में। भारतीय शेयर बाजार का आकार भी लगातार बढ़ रहा है।

पर अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। और भी कई मसले होते हैं।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मई 2014 में करीब 311 अरब (बिलियन) डॉलर था, और 2023 में यह करीब 600 अरब डॉलर हो चुका है। नौ साल में विदेशी मुद्रा भंडार का करीब दोगुना हो जाना यह बताता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत में बढ़ा है। भारतीय पूँजी बाजारों में निवेश करने वाले भी जम कर पैसा लगा रहे हैं भारतीय पूँजी बाजारों में, और भारत के प्लांट और फैक्ट्रियों में भी विदेशी पैसा आ रहा है।

कोविड के दौरान चीन की जो हालत हुई, उसे देख कर दुनिया भर के उद्योगपतियों को पता लगा कि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के मामले में सिर्फ चीन पर निर्भर रह जाना ठीक नहीं है। इसलिए विदेशी पूँजी अब भारत से लेकर वियतनाम तक का रुख कर रही है, जो प्लांट और फैक्ट्रियों की शक्ति में दिखायी दे रही है।

# मोदी सरकार के नौ साल



# उपलब्धियों का पीछा करते सवाल

भारत की प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2014 में 1,573.9 डॉलर थी, अब 2023 में 2,601 डॉलर है। जीडीपी के मामले में भारत 2014 में 10वें स्थान पर था और अब यह पाँचवें स्थान पर है। दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है भारतीय अर्थव्यवस्था।

मोदी सरकार के तहत आधारभूत ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास बहुत तेजी से हुआ है। राजमार्गों (हाइवे) का निर्माण बहुत व्यापक रहा है। वर्ष 2014 में औसत दैनिक निर्माण दर 12 किलोमीटर की थी, जो अब करीब 37 किलोमीटर हो गयी है। वर्ष 2014 में देश में 74 हवाई अड्डे थे, जो अब दोगुने यानी 148 हो गये हैं। सरकार ने 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' और 'भारतमाला परियोजना' जैसी पहलों के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी है। मनमोहन सरकार के वक्त के कामों को भी गति मिली है मोदी सरकार में। राजमार्ग तो पहले भी बन रहे थे, बस गति तेज हो गयी मोदी सरकार के वक्त।

जीएसटी व्यवस्था मोदी सरकार लेकर आयी 2017 में। अभी अगस्त 2023 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,59,069 करोड़ है। अगस्त 2023 महीने का राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है। डेढ़ लाख करोड़ रुपये प्रति माह का जीएसटी संग्रह अब लगभग सामान्य हो गया है।

अमेरिका के वे उद्यमी भी अब भारत में निवेश की बात कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले तक निवेश में हिचक दिखा रहे थे। एलोन मस्क हों या अमेजन, सबको भारत में बेहतरीन भविष्य दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब वे पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका आये थे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज उसका नंबर पाँचवाँ है। जाहिर है दुनिया को भारत में संभावनाएँ दिख रही हैं। पर मसला सिर्फ आँकड़ों का नहीं है।

चीन से उठ कर तमाम अमेरिकन कंपनियाँ भारत आ रही हैं। एक वजह साफ है कि चीन अब उतना भरोसेमंद साझेदार न रहा अमेरिकी कंपनियों के लिए। चीन को लेकर कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाये वहाँ। भारत एक स्थिर लोकतंत्र है, यह बात दुनिया को समझ में आ रही है, अमेरिका को कुछ ज्यादा समझ में आ रही है। अमेरिका के सामने चुनौती है चीन के विस्तार से निपटने की। चीन से निपटने के लिए दुनिया भर में भारत से बेहतर साझेदार नहीं मिल सकता। बदलती



वैश्विक राजनीति में रूस और चीन करीब आ रहे हैं। भारत इस दुनिया का एकमात्र वह देश है, जो रूस और अमेरिका दोनों से कई मसलों पर खरी बात कर सकता है।

जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो यह बात कही जाती थी कि मोदी को विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं है। आज मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में विदेश नीति के मोर्चे की उपलब्धियाँ बतायी जाती हैं। इस विदेश नीति का एक आयाम यह भी है कि मध्य-पूर्व के वे देश - सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भारत में निवेश के लिए उत्सुक दिखायी दिये, जो एक समय लगभग हर मुद्दे पर पाकिस्तान के हितचिंतक और भारत की राह में रोड़े माने जाते थे।

ऐप्पल आईफोन के लिए कई कल-पुरजे बनाने वाली ताईवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने फैसला किया कि वह भारत में बिजली वाहन (इलेक्ट्रिकल व्हीकल या ईवी) बनायेगी। यह खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि एक विदेशी कंपनी ने भारत में विदेशी निवेश का फैसला किया। इसमें विदेशी निवेश तो आयेगा ही, और जाहिर है कि वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से आयेगा। पर इस निवेश के गहरे भूराजनीतिक अर्थ हैं।

ताईवान चीन के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझा हुआ है। ताईवान को लेकर चीन ने कई धमकियाँ दी हैं कि वह ताईवान पर आक्रमण भी कर सकता है। कोई भी कंपनी एक शांतिपूर्ण माहौल चाहती है। खास तौर पर उन कंपनियों के लिए तो स्थिर वातावरण अनिवार्य है, जो किसी दूसरे बहुराष्ट्रीय ब्रांड, जैसे ऐप्पल के लिए काम करती हैं।

बिजली वाहनों (ईवी) के क्षेत्र में फॉक्सकॉन के आने का मतलब है कि इन वाहनों में लागत और गुणवत्ता के स्तर पर नवाचार देखने में आयेगा। बिजली वाहनों को लेकर आम उपभोक्ता में बहुत भ्रम हैं और अभी इन्हें कंसेप्ट वाहनों के तौर पर ही देखा जा रहा है, ये मुख्यधारा में नहीं आये हैं। फॉक्सकॉन का भारत में व्यापक स्तर पर आना एक तरह से चीन के लिए संदेश है कि अगर चीन ने ताईवान को बहुत ज्यादा परेशान किया, तो चीन के प्रतिस्पर्धी भारत को मजबूत बनाने का काम ताईवान की कंपनियाँ करेंगी।

चीन की दिक्कत यह है कि उसे एक साथ दुनिया में विस्तारवादी झगड़े भी करने हैं और कारोबार भी करना है। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं। भारत की इस मामले में वैश्विक छवि ठीक है। भारत बेवजह झगड़ों में नहीं उलझता और यहाँ राजनीतिक स्थिरता है, लोकतंत्र है, न्यायिक व्यवस्था है। ये सब वजहें भारत को तमाम कंपनियों के लिए पसंदीदा देश बनाती हैं।

जन-धन योजना मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिये मोदी सरकार ने लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग पैदा किया है। 50 करोड़ से ज्यादा खाताधारक जन-धन योजना में हैं। खाताधारकों को कई लाभ देने वाली जन-धन योजना के खातों में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है। जन-धन योजना को मोदी सरकार अपनी एक ऐसी उपलब्धि मानती है, जिसका जिक्र राजनीतिक भाषणों में बखूबी किया जाता है।

कोरोना ने केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भीषण आघात किया। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर एक वक्त बुरी तरह

से नकारात्मक तौर पर प्रभावित हुई। पर वे बातें अब बहुत पुरानी लगती हैं। कोरोना काल में मनरेगा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वित्त-वर्ष 2022-23 यानी पिछले साल के बजट में मनरेगा के लिए 78,000 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी। इसे बाद में बढ़ाया गया था और 2022-23 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह राशि करीब 89,000 करोड़ रुपये हो गयी है। पर 2023-24 के लिए मनरेगा की मद में करीब 61,000 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं। मनरेगा राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील योजना है और कोरोना काल में इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत सहारा मिला था।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक विमर्श चलाया - रेवड़ी विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका आशय है कि कुछ राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ी बाँट कर राजनीतिक लाभांश लेने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। उनके बयान के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, उसका आशय है कि मुफ्त शिक्षा वगैरह देना तो जनता को सशक्तीकरण है। मुफ्तखोरी की राजनीति है, मुफ्तखोरी का अपना अर्थशास्त्र और नैतिकशास्त्र भी है। अरविंद केजरीवाल ने 'मुफ्त' को सफल राजनीतिक औजार बना दिया, हालाँकि दक्षिण भारतीय राज्यों में 'मुफ्त' का राजनीतिक इस्तेमाल कमोबेश पहले भी होता रहा है।

दिल्ली में इतनी बिजली मुफ्त और उतना पानी मुफ्त जैसी घोषणाओं ने केजरीवाल की राजनीतिक जमीन इतनी पुख्ता कर दी है कि उनके आगे अब विरोधी लगभग बेअसर दिखते हैं, कम-से-कम राज्य स्तर की राजनीति में। मुफ्त दरअसल कुछ होता नहीं है, कहीं से लेकर कहीं देने की बात होती है राजनीति में। जो राजनेता इस काम को जितने कौशलपूर्वक कर ले, वह उतना ही बड़ा कलाकार माना जाता है। मोदी से लेकर केजरीवाल तक सभी इस कला के पर्याप्त कुशल कलाकार हैं। सौभाग्य योजना से लेकर शौचालय तक ये मोदीजी बाँटते हैं, मुफ्तखोरी की विचारधारा के तहत। कोरोना काल में मुफ्त अनाज तो दिया ही जा रहा है। अब चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार दे दनादन रेवड़ियाँ बाँट रही है।

रूस-यूक्रेन युद्ध का संकट लगातार खिंच रहा है। दोनों पक्षों की तरफ ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि युद्ध के बादल छूट सकते हैं जल्दी। कोरोना और यूक्रेन का युद्ध - ये दोनों ऐसे असाधारण कारक हैं, जिनसे दुनिया को कोई देश नहीं बच सका। मगर इन कारकों पर कुछ असर डाल पाना भी दुनिया के ज्यादातर देशों के बस में नहीं है। कच्चे तेल के भाव लगातार ऊपर गये यूक्रेन युद्ध के बाद, इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी झेला।

महंगाई एक चुनौती के तौर पर हाल के सालों में मोदी सरकार के सामने रही है। मनमोहन सरकार के लिए भी महंगाई बहुत बड़ी चुनौती रही थी। मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी चुनौती महंगाई ही रही। यूपीए के चुनाव हारने का एक कारण महंगाई थी। औसतन देखें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मुद्रास्फीति दर 7.5% रही थी। अभी जुलाई 2023 में भी खुदरा महंगाई दर 7.44% पर जा पहुँची, वहाँ से थोड़ी घट कर यह अगस्त में 6.83% पर आयी है। वहीं जून 2023 में यह दर 4.87% पर थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतिगत आकांक्षा यह है कि महंगाई दर 4% के करीब रहे, इससे नीचे गिरे तो भी 2% से नीचे ना जाये

**विपक्ष ने चुनौतियाँ  
रेखांकित कर दी हैं। इन  
पर काम किया जाना बाकी है।  
उपलब्धियों का पीछा कर रही  
चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं, चुनावी  
वक्त में मोदी सरकार को यह  
बात साफ तौर पर समझ  
लेनी चाहिए।**

# टमाटर-प्याज के भाव और किसानों के हाल

किसानों का आंदोलन भी चला मोदी सरकार के दौर में। किसी भी चीज के भावों में तेज गिरावट और बढ़ोतरी के कारणों में आपूर्ति और माँग का संतुलन ही होता है। अगर किसी चीज की माँग तेजी से बढ़ जाये, तो भाव बढ़ जाते हैं और किसी चीज की आपूर्ति तेजी से गिर जाये, तो भी उसके भाव बढ़ जाते हैं। आपूर्ति गिरने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, बाढ़ सूखा या कोई भी प्राकृतिक आपदा के चलते किसी सामान की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसमें किसी सरकार का कोई दखल नहीं है। पर सरकारें एक दीर्घकालीन नीति पर काम कर सकती हैं, जिनसे किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित किया जा सके।

कभी तो ऐसी खबरें आती हैं कि सस्ती कीमतों से नाराज किसान अपना टमाटर या प्याज सड़क पर ही छोड़ कर चले गये। कई मामलों में यह भी देखने में आता है कि प्याज या किसी और कृषि उपज को खेत से बाजार तक लाने की लागत ज्यादा बैठती है, उससे मिलने वाली कीमत कम बैठती है। ऐसी सूरत में किसान अपनी फसल को सड़क पर छोड़ कर जाने में भलाई समझता है। विरोध के एक तरीके के रूप में भी ऐसा होता कई बार देखा जाता है।

पर किसान क्यों अंदाज नहीं लगा पाता कि उसकी फसल के भाव इस सीजन में उसे ठीक नहीं मिलेंगे? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसी व्यवस्थाएँ अभी बनी नहीं हैं, जो किसान को सलाह दे सकें कि प्याज-टमाटर की आवक ज्यादा होने की उम्मीद है, सो इस बार प्याज के बजाय कुछ और उपजा लो। छोटा किसान आँखें मूँद कर अपने बने-बनाये ढर्रे पर काम कर रहा है, माँग और आपूर्ति के पूर्वानुमान उसके पास नहीं हैं। इसके लिए संस्थागत इंतजाम भी नहीं हैं।

बड़े किसान और चतुर सुजान तो अपना हिसाब-किताब जमा लेते हैं। ज्ञान से हासिल चेतना से यह अंदाज कर लेते हैं कि भाव क्या होंगे और कब



ज्यादा होंगे। इसलिए यह लगातार देखने में आता है कि बिचौलिये सस्ते भाव पर प्याज को स्टॉक करते हैं और महँगे पर बेचते हैं। पर महँगे भाव का फायदा बिचौलियों को होता है, छोटे किसान के रोने वही रहते हैं कि इस बार प्याज बहुत ज्यादा हुआ, तो सस्ता बेचना पड़ा। या इस बार प्याज कम उगाया, तो भाव बहुत बढ़े हुए मिल रहे हैं बाजार में।

कुल मिला कर किसानों की ज्ञान चेतना का स्तर उन्नत करने के साथ-साथ ऐसे इंतजाम भी किये जाने जरूरी हैं कि छोटा किसान भी अपनी फसल का स्टॉक उस तरह से कर ले, जिस तरह से बिचौलिये ट्रेडर और बड़े किसान कर लेते हैं और जब भाव ज्यादा होते हैं, तब बेचते हैं। इस संबंध में क्या सहकारी संस्थाएँ बना कर काम किया जा सकता है? क्या अमूल का डेयरी मॉडल

छोटे किसानों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर गंभीर चिंतन और कर्म की जरूरत है। इन सवालों के जवाब देने के लिए संस्थागत इंतजामों की जरूरत है। उस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं जा रहा है। सस्ता प्याज-टमाटर बेच कर तात्कालिक राजनीति आपदा-नियंत्रण कर लेना ही तमाम सरकारों को सूझता है।

इसलिए कई दशकों के बाद भी प्याज से जुड़ी समस्याओं के पक्के इलाज नहीं हो पा रहे हैं। प्याज-टमाटर की राजनीति तात्कालिकता में फँसी रहती है, इसलिए इसका सर्वोहितकारी अर्थशास्त्र विकसित ही नहीं हो पा रहा है। फौरी इलाजों से समस्याओं के पक्के हल नहीं निकलते।

और बढ़े तो भी यह 6% से ऊपर ना जाये। पर महँगाई 6% से ऊपर जा चुकी है, 7% के आस-पास है। हालिया महँगाई की वजह टमाटरों की महँगाई है। टमाटर की महँगाई का असर समग्र होता है और ब्याज दर पर भी टमाटर की महँगाई असर डालती है। महँगाई दर से सरकार तो परेशान होती ही है, आरबीआई की परेशानी भी बढ़ जाती है।

सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों में सिर्फ महँगाई ही नहीं है। रोजगार के अवसरों और रोजगार की गुणवत्ता को लेकर भी विपक्ष सरकार की घेराबंदी करता है। जी-20 की बैठक के ठीक बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "अब जब जी-20 की बैठक खत्म हो गयी है, मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगस्त में

भोजन की एक आम थाली का दाम 24% बढ़ गया। देश में बेरोजगारी दर 8% है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय है।

विपक्ष ने चुनौतियाँ रेखांकित कर दी हैं। इन पर काम किया जाना बाकी है। उपलब्धियों का पीछा कर रही चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं, चुनावी वक्त में मोदी सरकार को यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए।

# देश, बैंक और कॉर्पोरेट : तीनों की बैलेंस शीट सुधरी

**मोदी सरकार के इन 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही?**

इन वर्षों में देश ने नेतृत्व की भूमिका हासिल की है। हम 3.5 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और तेजी से पाँच लाख करोड़ डॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को ताकतवर नेता मान रही है। जिस तरह जी20 में मोदी जी ने नेतृत्व दिखाया, उससे भारत की साख बढ़ी है।

मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में तीन बड़ी चीजें हुई हैं। पहला, हमने दुनिया को बताया कि हम डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ बना सकते हैं, बल्कि डिजिटल पब्लिक गुड्स को लाकर देश की अर्थव्यवस्था भी बदल सकते हैं। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी के मोर्चे पर भारत नेतृत्व कर रहा है। भारत पहला देश बना है, जिसकी 1,000 कंपनियों के बीआरएसआर रिकॉर्ड एनएसई और बीएसई की वेबसाइट पर होंगे। ऐसी कंपनियों में निवेश से निवेशकों को फायदा होगा। आज ऐसी 1,000 कंपनियाँ कल बढ़ कर 2,000 और 5,000 बन जायेंगी। आज लोग भारत में निवेश के लिए तैयार हैं। विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा है।

**डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कहें कि जन धन, आधार और मोबाइल (जैम ट्रिनिटी) का श्रेय मोदी सरकार को क्यों मिलना चाहिए? ये चीजें तो पहले से शुरू हो चुकी थीं।**

किसने कहा कि सरकार बदलने पर सब चीजें बदल जाती हैं? एक निरंतरता बनी रहती है। विकास का मतलब यह नहीं कि आप सब चीजों को नये सिरे से शुरू करें। आज हर परिवार के पास बैंक खाता है। छोटे-बड़े काम के लिए हर जगह डिजिटल भुगतान की सुविधा है।

**क्या यूपीए ने वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन) का नारा दिया, तो मोदी सरकार ने उस पर अमल किया?**

देश में सुधार और विकास बहुत तेजी से हो रहा है। दुनिया मान रही है, और क्या प्रमाणपत्र चाहिए? जो सुविधाएँ कभी सोची नहीं थी, वे मिल रही हैं। वंदे भारत में सफर करना गर्व की बात लगती है। देश में स्टेशन, सड़क सब जगह इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है।

**पिछले एक दशक और उससे पिछले दशक में आर्थिक प्रगति की तुलना आप कैसे करेंगे?**

देश की प्रगति में सभी का योगदान है। देश तेजी से सुधार के पथ पर चल रहा है। इससे

**कई बड़ी कंपनियों में निदेशक, शैलेष हरिभक्ति एंड एसोसिएट्स के चेयरमैन एवं जाने-माने चार्टर्ड एकाउंटेंट शैलेष हरिभक्ति से बातचीत।**



सबको कुछ-न-कुछ मिला है। ग्रामीण महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए अब लकड़ी की जरूरत नहीं। दो साल में हर घर में नल होगा, जल आयेगा। यूपीआई के जरिये जहाँ जो चाहें ले सकते हैं। यह भी होगा कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय अपने घरों में कम दरों पर पैसे भेज पायेंगे।

**देश की प्रगति में नेतृत्व, निरंतरता और समय में किसकी ज्यादा भूमिका है?**

इसका पहला श्रेय देशवासियों को है। दूसरा श्रेय नेतृत्व को, जो दुनिया भर से तमाम चीजें लेकर आया। देश में विकास का माहौल था। आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनता गया। इन्फ्रास्ट्रक्चर में जिस तेजी से बदलाव आया है, वैसा पहले कभी नहीं आया।

**क्या रोजगार के मोर्चे पर सरकार की आलोचना सही है?**

एक समय देश में सिर्फ 25-30 उद्योगपतियों का कारोबार था। आज देश एक लाख नये स्टार्टअप हैं। एक समय वह भी आयेगा जब लोग 10 से 5 की नौकरी के बारे में नहीं सोचेंगे। यह सोचेंगे कि कैसे एक लाख से 10 लाख और 10 लाख से 1 करोड़ उद्यमी बन जायें, जो जन भागीदारी से दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें।

**अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या उतनी रही है, जितनी अपेक्षित थी?**

जब देश की विकास दर सबसे ज्यादा थी, तब उसका आधार (बेस) एक लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर का था, इसलिए 10% की विकास दर दिखी। आज यह आधार 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है, जिस पर 6-7% की वृद्धि है। पहले महंगाई दर भी ज्यादा थी। आज महंगाई दर कभी-कभी शून्य तक भी आ गयी है। हमारे देश, वित्तीय क्षेत्र और कॉर्पोरेट जगत – तीनों की बैलेंस शीट सुधरी है। कभी व्यापक अर्थव्यवस्था

(मैक्रो) में हालात ठीक नहीं थे। बैंकों में एनपीए बहुत बढ़ गये थे। कॉर्पोरेट क्षेत्र की लाभदायकता ठीक नहीं थी। आज तीनों चीजें सुधर गयी हैं।

**पर खुदरा महंगाई दर कुछ समय से लगभग 6-7% की चल रही है।**

आपूर्ति (सप्लाई) व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। क्षमता उपयोग का स्तर 80% तक पहुँचने लगा है। ऐसे में नया निवेश जरूरी हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र निवेश कर रहा है, निजी क्षेत्र को भी निवेश करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से भी निवेश आ रहा है। यूपीआई, डीबीटी से लोगों को फायदा मिल रहा है। भुगतान का निपटारा (सेटलमेंट) साफ तरीके से हो रहा है। शेयर बाजार में भी जल्दी ही तीन घंटे में सेटलमेंट होगा।

**क्या काले धन पर सरकार को कोई सफलता मिली? देश में कितना काला धन वापस आया?**

आज लोगों के वित्तीय पदचिह्न (फाइनेंशियल फुटप्रिंट) साफ दिखते हैं। इसलिए काले धन को लेकर लोगों में डर है। डिजिटल फुटप्रिंट से सरकार पकड़ लेगी। देश में नियमों के अनुपालन (कंप्लायंस) पर ध्यान काफी बढ़ गया है और तकनीक की मदद से गलत करने वालों की पहचान जल्दी हो जाती है।

**तो इससे नया काला धन बनने में कमी आयेगी, मगर क्या पुराने काले धन को भूल जायें?**

उस धन को भी खर्च तो करना पड़ेगा। लोग निवेश करेंगे तो और बढ़िया है।

शैलेष हरिभक्ति से इस बातचीत को पूरे विस्तार से निवेश मंथन के यूट्यूब चैनल youtube.com/niveshmanthan पर देखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।





# पब्लिक डिजिटल इन्फ्रा और बैंकों में सुधार बड़ी उपलब्धियाँ

बीते दशक में अर्थव्यवस्था में आये बदलावों पर इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा से बातचीत।

**बीते एक दशक में आये सबसे बड़े बदलाव आपकी नजर में क्या हैं?**

इन 10 सालों में कई तरह की चुनौतियाँ भी आयी हैं। सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 को लेकर थी। इसके अलावा, कई चीजें ऐसी हुई हैं जिन्हें आगे बढ़ते हुए कदम की तरह देखा जाना चाहिए। हर सरकार के सामने एक विरासत भी होती है कि पिछली सरकारों ने क्या किया। अब तक सभी सरकारों ने पिछली सरकारों के काम को पलटने के बदले उस पर आगे काम करने की कोशिश की है।

वर्तमान सरकार ने बीते नौ-दस वर्षों में कई ऐसे कदम उठाये, उसे मैं अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का सतत प्रयास कहूँगा। जन-धन ने काफी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ दिया है, जो एक उपलब्धि है। पर यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पिछली सरकार ने आधार और डिजिटलीकरण की तरफ कदम उठाये थे।

**ये चीजें पहले आयी थीं, पर पहले काफी हद तक पायलट परियोजना की तरह थीं। क्या इस सरकार ने मिशन मोड में आकर इन चीजों को बढ़ाया?**

बिल्कुल। अगर नींव नहीं डली होती तो इस सरकार के लिए जन धन, आधार, मोबाइल की तिकड़ी (जैम ट्रिनिटी) को इस रूप में लाना आसान नहीं होता। वहीं सरकार में दूरदर्शिता और तैयार चीजों का लाभ उठाने की क्षमता नहीं हो तो वह चीजों को आगे नहीं ले जा सकती। इस सरकार ने नींव को समझा और उसके लाभ को कई दिशाओं में ले जाने का काम किया, जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और बैंकिंग सुविधाएँ लोगों तक ले जाना वगैरह। पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में इस सरकार ने पिछली सरकारों के काम को बहुत आगे बढ़ाया है।

दूसरे, बैंकों की हालत खराब थी और बहुत एनपीए था। इस पर पहल पिछली सरकार ने भी की थी, पर वह उसे एक मुकाम तक नहीं पहुँचा सकी। इस सरकार ने वह काम किया। आईबीसी आने से बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र में हमने पुनर्गठन होता देखा। इसके चलते आज बैंकों और कॉर्पोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट पहले से काफी चुस्त-दुरुस्त है।

तीसरे, इस सरकार ने सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट (एसडीजी) की तरफ कदम उठाये। इसी संदर्भ में सरकार ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया और हम सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा में काफी आगे बढ़े हैं। चौथी चीज है कि कोविड के टीके (वैक्सीन) को जिस तरह लोगों तक पहुँचाया गया, वह काफी बड़ी उपलब्धि है।

इस संदर्भ में सरकार ने जिस तरह राजकोषीय (फिस्कल) पहलू को संभालने की कोशिश की, उसे हम मुड़ कर देखें तो वह एक अच्छा कदम था। उस समय मुझे लगता था कि सरकार को गरीबों के हाथ में पैसे रखने जैसे काम भी करने चाहिए थे, जो नहीं किया गया। हालाँकि तब सरकार ने राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) को बढ़ाया, पर उसका इस तरह उपयोग किया कि अब देखने पर लगता है कि लोगों के हाथ में सीधे पैसा नहीं रखना सकारात्मक ही रहा। इससे पहले 2008-2009 के संकट के बाद (यूपीए) सरकार ने राजस्व व्यय (रेवेन्यू एक्सपेंडिचर)

पर ध्यान दिया था, न कि पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) पर। वहीं इस सरकार ने पूँजीगत व्यय पर जोर दिया, राजस्व व्यय की दिशा में उतना नहीं किया। मुफ्त अनाज वितरण जैसी चीजें जरूर हुईं।

एक सवाल रहेगा कि जैसा विकास पिछले दशक में हुआ, क्या यह इससे बेहतर हो सकता था? कुछ ऐसे कदम उठाये गये, जिनका बहुत सकारात्मक असर नहीं पड़ा, जैसे नोटबंदी हुई और जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया। फिर भी कुल मिला कर भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे बिंदु पर है, जहाँ हम सही मुद्दों पर ध्यान दें तो विकास की गति को और बढ़ाया जा सकता है। **लेकिन जीएसटी लागू तो होना ही था। अगर यह 2017 के बदले चाहे कुछ पहले हुआ होता या दो-चार साल बाद भी होता, तो जो लोग टैक्स प्रणाली से बाहर रह कर काम करने के आदी थे, उन्हें वैसा ही झटका लगता।**

कुछ हद तक आपकी बात सही है। पर पिछले कुछ महीनों में जीएसटी संग्रह को देखें तो यह 1.60 लाख करोड़ रुपये के आस-पास स्थिर हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में जीएसटी संग्रह की जो सच्ची क्षमता थी, शुरु में भी आकलन था कि वह 1.20 लाख करोड़ रुपये के आस-पास है, जबकि शुरुआत में इसका संग्रह इससे काफी कम रहा और काफी कोशिशों के बाद भी बढ़ नहीं रहा था। दूसरे, हाल में जीएसटी संग्रह में जो वृद्धि दिखती है, उसमें वैश्विक कमोडिटी कीमतें बढ़ने के चलते आईजीएसटी संग्रह में हुई वृद्धि का भी योगदान है। जीएसटी जब लागू किया गया, वह सही समय था या नहीं, इसे लेकर बहस आगे भी चलती रहेगी।

**2014 से पहले नीतिगत पक्षाघात (पॉलिसी पैरालिसिस) की चर्चा होती थी। आपने कहा कि हर सरकार के पास एक विरासत होती है। मोदी सरकार को मिली विरासत नींव का काम कर रही थी या बोझ का?**

तब विरासत में मिले मुद्दे तो थे, लेकिन राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) का बोझ वैश्विक कमोडिटी कीमतें एकदम टूटने के चलते अचानक बहुत कम हो गया था। उससे मिली जगह का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था, जैसे आज पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। पूँजीगत व्यय पर यह ध्यान उस समय भी दिया जा सकता था। पर उसके बदले जो काम हुए, उससे विकास के चलते कर संग्रह में तेजी आने के बदले उसकी चाल अचानक रुक-सी गयी।

पर यूपीए-2 में जो नीतिगत पक्षाघात दिखा, उसे इस सरकार ने धीरे-धीरे हटाने की कोशिश की। इसका सबसे बेहतर उदाहरण सड़क क्षेत्र है, जिसमें इन्होंने तमाम परियोजनाओं के सामने आयी बाधाएँ दूर करने की कोशिश की और अटका हुआ सड़क क्षेत्र दो-ढाई साल में फिर से चल पड़ा।

सुनील सिन्हा से इस बातचीत को पूरे विस्तार से निवेश मंथन के यूट्यूब चैनल [youtube.com/niveshmanthan](https://youtube.com/niveshmanthan) पर देखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।



# नतीजों से पहले सीमेंट और फार्मा में हैं अवसर

तिमाही नतीजों का मौसम अब सामने है। वहीं शेयर बाजार में एफआईआई बिकवाली के बीच थोड़ी डगमगाहट और ऊपरी स्तरों पर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में इस समय निवेशकों को क्या करना चाहिए? प्रस्तुत है एलिविसर इक्विटीज के निदेशक दीपन मेहता से यह बातचीत।

**बाजार में एक अनिश्चितता है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार की दिशा ऊपर ही है, या यह नीचे आने लगा है। अति-उत्साह बनाम सावधानी के बीच बाजार में आप क्या देख रहे हैं?**

बाजार न पूछ कर ऊपर जाता है, न पूछ कर नीचे आता है। लेकिन अच्छा है कि कई हफ्तों से जिस सुधार (करेक्शन) की प्रतीक्षा थी, अंततः वह सुधार दिख रहा है, जो हल्का ही है। कीमतों से अधिक हम मूल्य के हिसाब से सुधार देख रहे हैं, जो तेजी के बाजार में काफी सकारात्मक है। तेजी के बाजार की खासियत है कि इसमें हल्की गिरावटें आती हैं और उसके बाद फिर से ऊपरी स्तर दिखते हैं। अभी जो रुझान है, उसमें मेरी आशा है कि आगे ऊपर की ही चाल बनेगी।

**इस नरमी में बाजार के किन स्तरों से नीचे नहीं जाने की आशा है?**

मैं छोटी अवधि में बाजार के उतार-चढ़ाव पर बहुत ध्यान नहीं देता। भारत की लंबी अवधि की कहानी काफी ठीक-ठाक है। तिमाही नतीजों का आने वाला मौसम अगर अच्छा निकलेगा, तो बाजार और ऊपर के स्तरों पर जा सकता है। अगले हफ्ते या अगले महीने की बात कहना मुश्किल है, पर भारतीय बाजार बुनियादी रूप से मजबूत है और कंपनियों की आय वृद्धि (अर्निंग ग्रोथ) दर भी अच्छी है। नकदी प्रवाह (लिविडिटी फ्लो) भी आ रहा है।

केवल एक-दो नकारात्मक बातें हैं। एक तो वैश्विक बाजारों में कुछ घबराहट है और विदेशी निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली अभी भी जारी है। निवेशकों को धैर्य और बाजार में विश्वास रखना चाहिए। यह बाजार के लिए अच्छा समय है और अगले 3-4 सालों में बहुत बढ़िया लाभ (रिटर्न) मिल सकते हैं। यदि निवेशक पूरी तरह निवेशित हैं, तो अपने निवेश को बनाये रखें। लेकिन यदि आपके पास नकदी आ रही है, बचत हो रही है, तो ये अच्छे स्तर हैं जहाँ से निवेश की शुरुआत की जा सकती है।

अभी ऐसी बड़ी (लार्जकैप) कंपनियों के शेयर लें, जो बाजार की तुलना में धीमे चले हैं। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल – ये सब सेंसेक्स वाले शेयर हैं जो धीमे चले हैं। जब तेजी वाले बाजार का अगला चरण आयेगा, तो वह इस बात से



आयेगा कि विदेशी निवेश प्रवाह फिर से आने लगे। जैसे-जैसे वैश्विक बाजार थोड़े सकारात्मक होंगे, तब हमारा बाजार सकारात्मक एफआईआई निवेश प्रवाह से उछलेगा।

**पर अभी तो सितंबर में जिस तरह एफआईआई की बड़ी बिकवाली हुई है, उसे लेकर बाजार में चिंता है।**

वे अभी बेच रहे हैं, क्योंकि उनको मूल्यांकन थोड़े महँगे लग रहे हैं। वे क्यों खरीदते हैं, क्यों बेचते हैं, यह बहुत जटिल कहानी है। उनका गणित समझना मुश्किल है। भारत पर उनका भी नजरिया सकारात्मक है, और शायद वे बाजार में पैसा लगाने का सही अवसर देख रहे हैं। उनके इंडेक्स फंडों में पैसा निकल रहा है, जिस वजह से उनकी बिकवाली आ रही है।

उनकी खरीदारी कब लौटेगी, यह कहना मुश्किल है। आपको धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहला संकेत तब मिलेगा, जब डॉव जॉस और नैस्डैक ऊपर चलने लगेंगे। अभी तेल की कीमतों को लेकर भी वैश्विक बाजारों में काफी घबराहट है। अगर तेल के दाम कुछ घटते हैं, तो अपने-आप ही धारणा सुधर जायेगी। उनके यहाँ महँगाई दर भी कम होनी चाहिए, और विदेशी निवेशकों में यह भरोसा बनना चाहिए कि ब्याज दरें अब बढ़ेंगी नहीं और कुछ महीनों बाद दरें घट सकती हैं।

**आने वाले तिमाही नतीजों को लेकर आपके अनुमान क्या हैं?**

नतीजे अच्छे आने चाहिए और दो क्षेत्रों में सौदों (ट्रेडिंग) के अवसर भी दिख रहे हैं – सीमेंट और फार्मा। सीमेंट पर मध्यम और लंबी

अवधि में हमारा नजरिया नकारात्मक है। पर ये शेयर हाल में नीचे आये हैं और काफी तिमाहियों के बाद इनमें एक उछाल दिख सकती है। बिक्री की मात्राएँ (वॉल्यूम) अच्छी रही हैं, लागत भी कुछ घटी है और हाल में सीमेंट के दाम भी कुछ बढ़े हैं। फार्मा क्षेत्र में काफी निवेशक अभी पूरी तरह निवेशित नहीं हैं और इसमें एक अच्छी बढ़त आ सकती है। पारंपरिक क्षेत्रों, जैसे बैंक, कैपिटल गुड्स, ऑटो ने अच्छा किया है और उनकी अच्छी चाल बनी रह सकती है। पर उनकी सकारात्मक बातें काफी हद तक भावों में जुड़ चुकी हैं।

**इस समय एक निवेशक के पोर्टफोलिओ के मुख्य हिस्से (कोर) की संरचना कैसी होनी चाहिए? किन क्षेत्रों को कितनी हिस्सेदारी देनी चाहिए?**

बहुत कम निवेशक इस पर विचार करते हैं। सेंसेक्स-निफ्टी में क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी (वेटेज) है, उसका सम्मान करना चाहिए। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र पर सकारात्मक रह कर इसमें अधिक हिस्सेदारी (ओवरवेट) रख सकते हैं। ऑटो, कैपिटल गुड्स, फार्मा पर सकारात्मक नजरिया है। कुछ हद तक सीमेंट ले सकते हैं। धातु (मेटल) पर कुछ नकारात्मक रुख है। जिन क्षेत्रों पर लंबी अवधि के लिए काफी सकारात्मक रहना चाहिए, वे हैं बैंक, ऑटो और कैपिटल गुड्स।

**एक्सचेंज के नतीजों के बाद आईटी शेयरों को लेकर बाजार में थोड़ा डर बना है।**

हाँ, लेकिन एक्सचेंज भारत के आईटी क्षेत्र का ध्वजवाहक नहीं है। लेकिन बड़ी आईटी कंपनियों को लेकर अभी सावधान रहना चाहिए। उन्हें बेचने का समय भी निकल चुका है। अभी मैं कुछ मिडकैप आईटी शेयरों को पसंद कर रहा हूँ। वहाँ अभी भी वृद्धि दर अच्छी है। इनमें टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी और कोफोर्ज की संभावनाएँ अच्छी दिख रही हैं। ये अभी महँगे हैं, पर थोड़ी गिरावट में लेंगे तो सुरक्षा मार्जिन बढ़ जायेगा।

दीपन मेहता ने इस बातचीत में और भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी राय रखी है। इस बातचीत को पूरे विस्तार से निवेश मंथन के यूट्यूब चैनल

youtube.com/niveshmanthan पर देखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।





# आज तो दूसरे देशों से और अच्छा है भारत



हिलियस कैपिटल के संस्थापक और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा वैसे तो हमेशा ही भारतीय शेयर बाजार को लेकर आशावादी रहते हैं। पर इस समय वे भारतीय बाजार को वैश्विक बाजारों की तुलना में पहले से भी अधिक आकर्षक मान रहे हैं। तो अभी वे क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? समीर अरोड़ा अपना म्यूचुअल फंड भी शुरू करने जा रहे हैं। इस बारे में क्या हैं उनकी योजनाएँ? ऐसे तमाम सवालों पर प्रस्तुत है **समीर अरोड़ा** के साथ निवेश मंथन के संपादक राजीव रंजन झा की यह बातचीत।

**क्या अभी दूसरे देशों से आकर्षक है भारत का शेयर बाजार?**

भारत का बाजार अब पहले से भी ज्यादा आकर्षक हो गया है। पहले भी हमारे बाजार ने अच्छे नतीजे दिये थे, लेकिन अभी दो कारणों से यह और भी आकर्षक हो गया है। पहला, भारत में कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, जो इस समय बाकी दुनिया में लोगों को परेशान कर रही हैं। जैसे कि हमारी जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी), हमारा डिजिटलीकरण, और हमारी विकास दर बाकी देशों से बहुत आगे है। दूसरे, निवेशक अब चीन से हताश हो गये हैं। चीन में शेयर बाजार वाले और सप्लाई चेन से जुड़े निवेशक, दोनों इस समय परेशान हैं। सप्लाई चेन वाले परेशान नहीं भी हों तो उन्हें सब कुछ एक ही बाजार में रखने में जोखिम लग रहा है। इस लिहाज से भारत का तुलनात्मक आकर्षण बहुत बढ़ गया है।

**चीन में अभी मंदी है, वहाँ चीजें ठीक होती नहीं दिख रही हैं। दूसरी तरफ, अमेरिका में विकास की दिक्कत उतनी नहीं दिख रही है, पर वहाँ महंगाई की समस्या है। इसका कुल असर वैश्विक बाजारों पर और हमारे लिए किस तरह का है?**

अगर आप पिछले 15 साल में देखें तो अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, वे भारत से भी आगे हैं, जबकि 20-25 सालों में भारत आगे था। तो मुझे लगता है कि आगे 10-15 साल में अमेरिकी बाजारों का फिर से सबसे ऊपर

रह पाना बहुत मुश्किल है। अगर 15 साल से कोई बाजार बाकी बाजारों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ चल रहा हो तो कुछ-न-कुछ अतिरिक्त हो जाता है, जिसको ठीक (करेक्ट) होना होता है। दूसरे, वहाँ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच काफी बँटा हुआ है सब। उनकी जो नैतिक श्रेष्ठता और धाक थी, वह भी कम हो गयी है।

इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच इतना तनाव है कि लगता है किसी भी दिन जंग छिड़ सकती है। युद्ध का तो पता नहीं, भगवान करे न हो, लेकिन उस तनाव में तीसरे देश को फायदा हो सकता है। इस लिहाज से भारत की स्थिति अच्छी हो गयी है। अमेरिका हमें सहयोग कर रहा है, भले ही वह चीन का विरोध करने के लिए हमारा सहयोग कर रहा है। चीन से असल में निवेशकों का काफी नुकसान हुआ है। इन दोनों वजहों से भारत के प्रति आकर्षण पहले से और बढ़ गया है।

**कोरोना महामारी के बाद से चीन प्लस वन की बात चलती रही है। क्या अब इसमें कोई नयी चीज रह गयी है या वही कहानी घूम-घूम कर आ रही है ?**

दिसंबर 2022 से पहले के डेढ़ साल देखें तो भारत में विदेशी निवेशकों ने 36 अरब डॉलर की बिक्री की। उस दौरान हम यह नहीं कह सकते थे, कि वे चीन से दुखी हो कर भारत आये थे। उन्हें भी समझने में समय लगा कि कोरोना का असर है। चीन ने उसे और आगे बढ़ा दिया कि

अब जीरो कोविड होगा। लेकिन इससे ज्यादा, वहाँ की सरकार के फैसलों से वहाँ के शेयर बाजार नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए, जैसे अलीपे का मामला हुआ, जैकमा चीन छोड़ कर टोक्यो चले गये। ये सब चीजें तो अभी हुई हैं। तो इसका जवाब हमारे यहाँ विदेशी निवेश के रुख से मिलेगा। पहले निवेश प्रवाह (फ्लो) ही नहीं था। तो यह नया इसलिए है, क्योंकि यह कई सालों तक दोनों तरह से चल सकता है - पोर्टफोलियो निवेश में भी और सप्लाई चेन के लिहाज से भारत में रुचि होने के चलते भी।

**चीन प्लस वन को लेकर तब जो सबसे पहला क्षेत्र उभरा था, वह केमिकल क्षेत्र था। लेकिन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में न तो शेयर बाजार की रुचि दिख रही है और न वहाँ विकास दिख रहा है।**

हर जगह ऐसा होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, असेम्बलिंग और मैनुफैक्चरिंग में आ गया। चीन प्लस वन में हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप वही वाले शेयर ले लें। चीन प्लस वन का मतलब ये है कि भारत में पोर्टफोलियो निवेशकों का वह निवेश आ रहा है, जो पहले चीन जाता था। अब यहाँ आकर चाहे वे एचडीएफसी बैंक ही ले लें! यह जरूरी नहीं है कि वे चीन प्लस वन वाले शेयर लें। और चीन प्लस वन के अधिकांश शेयर भी प्राइवेट रहेंगे। अगर ऐपल के सप्लायर आयेंगे, फॉक्सकॉन आयेगा, तो हमें उसके शेयर नहीं मिलने हैं। पर इसका फायदा यह है कि भारत



में नौकरियाँ आ रही हैं, विनिर्माण हो रहा है, तो उससे शायद हमारे साबुन-तेल वाले सामान्य शेयर ही चल जायें!

**तो इस समय भारत के लिए जोखिम के मुकाबले अवसर का संतुलन किधर है?**

मेरा मानना है कि अभी तो झुकाव अवसर की तरफ ज्यादा है। अभी सबसे बड़ा अवसर यही है कि भारत को इस लायक बनना है कि ज्यादा-से-ज्यादा कंपनियाँ यहाँ आयें। चीन को छोड़ कर कोई नहीं आयेगा, लेकिन लोग वहाँ जो विस्तार कर रहे थे, उसका थोड़ा या ज्यादा हिस्सा यहाँ भी ला सकते हैं। दो कारण से अतिरिक्त निवेश की दिशा भारत और वियतनाम की तरफ हो सकती है। एक तो वे खुद विविधीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में सिर्फ एक देश में बने रहने का असर देखा है।

दूसरे, भारत ने अपनी तरफ से या तो पीएलआई योजना पेश की या कहीं टैक्स बढ़ा दिये। भारत अपनी तरफ से प्रोत्साहन दे रहा है, मगर विदेशी निवेशक भी उसी अनुपात में अपनी एक या दो और देशों में रहने की रणनीति पर चल रहे हैं। भारत का अपना बाजार भी अब बड़ा हो रहा है।

**बाजार में जोखिम क्या दिख रहा है?**

एक होता है राजनीतिक जोखिम, क्योंकि अभी सब मान कर चल रहे हैं कि आगामी आम चुनाव में भाजपा जीतेगी। भाजपा ने इतना कुछ किया है। अब चुनाव में अगर भाजपा पर खतरा हुआ तो इस आधार पर आपके 5-10% तक जा सकते हैं कि नयी सरकार की क्या नीतियाँ होंगी। मगर मुझे इसका खतरा कम लगता है।

दूसरा खतरा यह है कि चीन और अमेरिका के बीच थोड़ा तनाव और बढ़ जाये। उससे हम भी नहीं बच पायेंगे। मतलब घरेलू राजनीतिक जोखिम के मुकाबले वैश्विक अनिश्चितता से ज्यादा खतरा है। लेकिन इस मामले में हम पहले से कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हैं कि जंग होगी या नहीं होगी, या किस स्तर पर जाकर कोई पीछे हटेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी देश और बाजार दोनों आगे चल सकते हैं।

**आर्थिक मोर्चे पर आप दोनों समयावधि की किस तरह तुलना करेंगे?**

दोनों दौर में हमारे लिए चीजें ठीक रही हैं। शेयर बाजार ने अच्छे लाभ (रिटर्न) दिये तो हमारे लिए सब अच्छा ही रहा।

**इस समय आप शेयर बाजार में क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं?**

पिछले एक साल में मैंने टेक्नोलॉजी शेयर बिल्कुल शून्य कर दिये थे। यह पूँजी मैंने कंज्यूमर

**यह मोदी सरकार का दसवाँ साल है। तो भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार इन 10 वर्षों में और इससे पहले यूपीए सरकार के 10 साल में कैसे रहे?**

आप अगर पाँच, 10, 15 या 20 साल के प्रतिफल (रिटर्न) देखें, तो इसमें बहुत अंतर नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार ने पिछले 10 साल में भी ठीक प्रदर्शन किया है। अब कुछ और ऐसी चीजें हो गयी हैं, जिससे विदेशी निवेशक और भारतीय निवेशक दोनों एक साथ खरीदारी करने लगे हैं। ऐसा पिछले पाँच-सात



साल में हुआ है, मुख्य तौर से नोटबंदी के बाद। भारतीय निवेशकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ और अब वे विदेशी निवेशकों से बराबरी कर सकते हैं। दूसरा बदलाव यह है कि भारत अब अपनी स्थिति ऐसी बना पाया है कि वह चीन और अन्य देशों से मुकाबला कर सकता है। इससे ओवरफ्लो का फायदा होगा।

ड्यूरेबल, न्यू एज और वित्तीय क्षेत्र में लगायी थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इन्हें बेच कर वापस आईटी में जाऊँ। अभी कुछ समय तक आईटी से दूर रहेंगे, क्योंकि दूसरे भी चल रहे हैं। आने वाली दो-तीन तिमाहियों में हो सकता है कि आईटी क्षेत्र तलहटी बना ले। लेकिन इतनी जल्दी उनके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि अगले एक साल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छे चल जायें, इन दोनों को छोड़ कर हमारे बाकी शेयर तो चल ही गये हैं।

**आपने पेटीएम या जोमैटो जैसी कंपनियों में क्या अपना निवेश बढ़ाया है?**

मैंने इनमें निवेश अभी नहीं बढ़ाया है। मैं दिसंबर 2022 तक ही ये दोनों शेयर काफी अच्छे भाव पर ले चुका था। ये मेरी इस साल की सफलताओं में रहे हैं और दोनों बढ़िया चल भी गये हैं।

**ये अब काफी चल चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इनमें अभी तेजी बची हुई है?**

इसमें उस स्तर की बड़ी तेजी तो नहीं बची है, लेकिन फिर भी कुछ बचा है, 10-20% मुनाफा कमाने का अवसर हो सकता है।

**अक्टूबर में आप अपना म्यूचुअल फंड लाने जा रहे हैं। उसमें पहले क्या होगा?**

हम इसे 23 अक्टूबर को शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड लायेंगे। इसके बाद एक से डेढ़ साल के दौरान मिड कैप या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे तीन-चार और फंड शुरू हो सकते हैं।

**तो आपका यह फंड हाउस क्या इक्विटी फंड हाउस ही होगा?**

जी बिल्कुल। इसमें भी ऐक्टिव इक्विटी फंड ही होंगे। इसमें ईटीएफ या इंडेक्स फंड वगैरह नहीं होंगे।

**बाजार में कई दूसरे बड़े खिलाड़ी पैसिव फंड की तरफ आ रहे हैं। इसे लेकर बड़ी रोचक बहस चल रही है।**

इसमें कोई बहस नहीं है। जिन लोगों को फंड प्रबंधन नहीं आता है, वे ऐक्टिव फंड नहीं कर सकते हैं, वे ईटीएफ ही करेंगे। हम फंड मैनेजर हैं और हमारी कंपनी की स्थापना भी फंड मैनेजरों ने की है। कोई यह कहे कि आपको सस्ते में ईटीएफ देगा, लेकिन यह कौन तय करेगा कि कौन-सा ईटीएफ लेना है?

**म्यूचुअल फंड बाजार में जियो जैसा बड़ा खिलाड़ी भी आने की तैयारी कर रहा है। इस प्रतिस्पर्धा को कैसे देखते हैं आप?**

नहीं जी, हम सोच भी नहीं रहे इतनी, नहीं तो हमसे शुरू ही नहीं हो पायेगा! इस कारोबार में फायदा यह है कि सब लोग अलग-अलग चीजें करते हैं। वे क्या करेंगे पता नहीं, पर अभी जियो को म्यूचुअल फंड बाजार में उतरने में एक-दो साल का समय तो लगेगा।

समीर अरोड़ा से इस बातचीत को पूरे विस्तार से निवेश मंथन के यूट्यूब चैनल youtube.com/niveshmanthan पर देखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।



## भारतीय शेयर बाजार के 50 दिग्गज

कंपनी	भाव (31.8.23)	52 हफ्ते का शिखर	शिखर से नीचे (%)	52 हफ्ते की तलहटी	तलहटी से ऊपर (%)	बाजार पूँजी (करोड़ रु.)
रिलायंस	2,406.90	2,855.00	-15.70	2,180.00	10.41	1,628,475
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	3,357.05	3,575.00	-6.10	2,926.00	14.73	1,228,362
एचडीएफसी बैंक	1,571.95	1,757.80	-10.57	1,365.05	15.16	1,190,556
आईसीआईसीआई बैंक	962.40	1,008.70	-4.59	796.10	20.89	673,713
इन्फोसिस	1,434.10	1,672.45	-14.25	1,215.45	17.99	595,203
हिंदुस्तान यूनिलीवर	2,504.20	2,768.50	-9.55	2,393.00	4.65	588,385
आईटीसी	439.65	499.60	-12.00	316.00	39.13	548,219
भारतीय स्टेट बैंक	561.30	629.65	-10.86	499.35	12.41	500,938
भारती एयरटेल	856.80	901.55	-4.96	720.05	18.99	487,581
बजाज फाइनेंस	7,165.20	7,999.90	-10.43	5,487.25	30.58	434,153
एलआईसी इंडिया	645.25	754.40	-14.47	530.20	21.70	408,120
लार्सन एंड टुब्रो	2,706.00	2,767.00	-2.20	1,798.00	50.50	380,348
कोटक महिंद्रा बैंक	1,759.60	2,063.00	-14.71	1,644.20	7.02	349,706
एचसीएल टेक	1,175.00	1,202.70	-2.30	882.20	33.19	318,856
एशियन पेंट्स	3,250.65	3,590.00	-9.45	2,686.15	21.02	311,802
मारुति सुजुकी	9,981.05	10,064.80	-0.83	8,076.65	23.58	301,508
एक्सिस बैंक	974.00	997.85	-2.39	706.00	37.96	300,080
टाइटन कंपनी	3,112.00	3,211.10	-3.09	2,268.90	37.16	276,279
अदाणी एंटरप्राइजेज	2,418.80	4,189.55	-42.27	1,017.10	137.81	275,743
सन फार्मा	1,112.25	1,169.90	-4.93	856.85	29.81	266,866
एवेन्यु सुपरमार्ट्स	3,716.10	4,606.00	-19.32	3,292.65	12.86	241,819
अल्ट्राटेक सीमेंट	8,345.00	8,501.00	-1.84	6,005.00	38.97	240,909
बजाज फिनसर्व	1,488.25	1,846.00	-19.38	1,216.10	22.38	237,051
ओएनजीसी	174.25	180.25	-3.33	121.50	43.42	219,211
एनटीपीसी	219.95	226.60	-2.93	155.05	41.86	213,278
विप्रो	408.45	425.95	-4.11	351.85	16.09	213,259
नेस्ले इंडिया	21,965.00	23,390.00	-6.09	17,888.00	22.79	211,777
टाटा मोटर्स	601.10	665.30	-9.65	375.50	60.08	199,677
महिंद्रा एंड महिंद्रा	1,576.10	1,594.85	-1.18	1,124.00	40.22	195,993
जेएसडब्ल्यू स्टील	779.90	835.00	-6.60	614.05	27.01	190,721
अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड	791.40	987.90	-19.89	394.95	100.38	170,953
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन	244.60	266.85	-8.34	186.35	31.26	170,620
एलटीआई माइंडट्री	5,206.00	5,425.00	-4.04	4,120.00	26.36	154,048
टाटा स्टील	123.00	124.30	-1.05	95.00	29.47	150,325
जियो फाइनेशियल	233.65	278.20	-16.01	205.15	13.89	148,444
अदाणी ग्रीन एनर्जी	928.05	2,465.00	-62.35	439.35	111.23	147,006
कोल इंडिया	230.10	263.30	-12.61	207.70	10.78	141,804
सीमेंस	3,921.40	4,066.10	-3.56	2,670.35	46.85	139,649
एचडीएफसी लाइफ	644.55	690.90	-6.71	457.95	40.75	138,576
हिंदुस्तान जिंक	318.00	383.00	-16.97	262.95	20.94	134,365
एचएएल	3,910.00	4,138.80	-5.53	2,242.00	74.40	130,746
बजाज ऑटो	4,613.05	4,988.55	-7.53	3,462.05	33.25	130,530
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	1,293.75	1,374.85	-5.90	1,039.25	24.49	129,510
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज	2,518.40	2,916.85	-13.66	2,250.85	11.89	128,049
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन	89.16	101.44	-12.11	65.20	36.75	125,905
डीएलएफ	503.75	521.70	-3.44	336.55	49.68	124,694
अदाणी पावर	321.05	420.00	-23.56	132.55	142.21	123,827
ग्रासिम	1,800.00	1,867.00	-3.59	1,528.00	17.80	118,521
टेक महिंद्रा	1,201.75	1,270.35	-5.40	982.95	22.26	117,164
वरुण बेवरेजेज	900.10	934.50	-3.68	481.68	86.87	116,935

## सबसे ज्यादा/कम पीई अनुपात वाले शेयर

नाम	मौजूदा भाव (31.8.23)	सीईपीएस	ईपीएस	ज्यादा पीई
जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स	485.60	0.08	0.07	6,937
लिरवामि कंसल्टिंग	131.00	0.02	0.02	6,550
पीबी फिनटेक	773.00	0.22	0.13	5,946
मेडप्लस हेल्थ	808.30	1.45	0.17	4,755
कॉफी डे	46.79	0.04	0.01	4,679
ओसियाजी	45.09	0.02	0.01	4,509
मैक्स फाइनेंशियल	931.30	0.37	0.28	3,326
एचजी इंडस्ट्रीज	199.50	0.29	0.06	3,325
सस्ता सुंदर	288.55	0.15	0.10	2,886
इंडिया फिनसेक	27.30	0.01	0.01	2,730
रियल इको-एनर्जी	27.30	0.02	0.01	2,730
अतुल ऑटो	592.05	5.46	0.24	2,467
कैसर कॉर्प	21.00	0.01	0.01	2,100
कृष्णा वेंचर	82.00	0.13	0.04	2,050
आर्चिडप्लाई डेकॉर	77.06	2.37	0.04	1,927
स्वान एनर्जी	304.95	0.47	0.16	1,906
मीडिया मैट्रिक्स	18.82	0.01	0.01	1,882
रूपाइस आइलैंड	18.25	0.11	0.01	1,825
चॉइस इंटरनेशनल	363.15	0.28	0.23	1,579
जीनस प्राइम	14.90	0.01	0.01	1,490
कैलिफोर्निया सॉफ्ट	14.21	0.59	0.01	1,421
इजमो	197.00	1.17	0.14	1,407
किनटेक रीन्युएबल्स	3954.05	3.14	3.14	1,259
बॉम्बे बर्मा	993.40	1.92	0.90	1,104
ब्लैक बॉक्स	215.00	0.59	0.20	1,075
आरआर फाइनेंस	10.59	0.01	0.01	1,059
ईएफसी	229.50	0.49	0.22	1,043
भारती एयरटेल	856.80	47.26	0.94	911
एमएसआर इंडिया	9.00	0.23	0.01	900
हिंदवेयर होम	589.90	3.16	0.66	894
जीएमआर एयरपोर्ट्स	61.78	0.07	0.07	883
आदर्श प्लांट प्रोटेक्ट	26.42	0.11	0.03	881
अवेलेबल फाइनेंस	137.80	0.16	0.16	861
पार्श्व एंटरप्राइजेज	185.00	0.26	0.22	841
सिंधिको फॉइल्स	106.20	1.34	0.13	817
जयप्रकाश पावर वेंचर्स	8.01	0.69	0.01	801
अबांस होलिंग्स	271.05	0.34	0.34	797
मैक्सिमस इंटरनेशनल	15.83	0.04	0.02	792
एचएमटी	31.25	0.06	0.04	781
रेटगेन ट्रेवल	606.75	1.10	0.80	758
स्क्वायर फोर	7.50	0.01	0.01	750
वेस्ट लीजर	159.55	0.23	0.22	725
सार ऑटो प्रोडक्ट्स	1184.65	4.30	1.67	709
लवबल लिंजरी	137.55	1.52	0.20	688
ओरिएंटल आरआई	75.53	0.31	0.11	687
एफएसएन ई-कॉमर्स नायिका	133.55	0.22	0.20	668
निंबस प्रोजेक्ट्स	39.80	0.28	0.06	663
प्रिवी स्पेशल	1163.00	28.70	1.78	653
फ्रेसर एंड कंपनी	5.78	0.16	0.01	578
पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल	40.15	0.08	0.07	574

नाम	मौजूदा भाव (31.8.23)	सीईपीएस	ईपीएस	कम पीई
रिलायंस होम फाइनेंस	2.00	114.77	114.73	0.02
एल्स्टोन टेक्स्टाइल्स	0.66	7.22	7.22	0.09
एस्सार शिपिंग	14.35	86.03	86.02	0.17
गोलाडा टेलीकॉम	2.83	16.81	15.99	0.18
एवंस टेक	1.41	5.12	5.12	0.28
डिलिजेंट मीडिया	3.02	10.86	10.86	0.28
राधे डेवलपर	3.07	10.16	10.02	0.31
सिद्ध वेंचर	6.60	21.51	21.51	0.31
जीएफएल	84.50	211.58	211.58	0.40
तुल्स्थान एनईसी	62.50	167.16	149.89	0.42
सोमा टेक्स्टाइल	20.43	48.61	48.45	0.42
बिलकेयर	75.00	164.12	162.20	0.46
टाटा स्टील	123.00	293.11	248.39	0.50
कावेरी टेलीकॉम	8.09	16.24	16.15	0.50
ग्लोबल ऑफशोर	43.16	90.35	80.59	0.54
चंद्र प्रभु	24.59	44.63	44.08	0.56
वापी पेपर	94.81	170.07	169.50	0.56
मिवेन मशीन	15.06	25.37	25.21	0.60
साईआनंद कमर्शियल	0.45	0.63	0.63	0.71
ऑयल कंट्री	19.64	29.39	22.65	0.87
स्विचिंग टेक	45.45	49.37	49.10	0.93
जेआईएसएल	34.34	114.77	36.80	0.93
स्टारलॉग एंटरप्राइजेज	29.72	34.80	31.09	0.96
कर्णावती फाइनेंस	2.62	2.75	2.74	0.96
आंध्र सीमेंट	102.60	111.58	106.51	0.96
शक्ति शुगर्स	27.75	30.47	27.34	1.01
इनोकॉर्प	5.37	4.94	4.78	1.12
शारदा एनर्जी	227.90	201.82	183.12	1.24
आनंद लक्ष्मी	12.15	9.74	9.74	1.25
ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स	0.75	0.58	0.56	1.34
जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट	479.95	351.12	351.12	1.37
लीडिंग लीडिंग	2.60	1.88	1.83	1.42
टाइन एग्रो	21.11	14.01	14.01	1.51
कंपर्ट फिनकैप	6.80	4.20	4.20	1.62
मॉडर्न स्टील्स	15.47	9.49	9.49	1.63
जैन इरिगेशन	62.95	114.77	36.80	1.71
सविता ऑयल टेक	325.50	202.89	188.26	1.73
गायत्री शुगर्स	15.65	10.62	8.79	1.78
दीप डायमंड	5.65	3.02	3.02	1.87
मान एल्युमीनियम	69.54	40.26	36.96	1.88
जिंदल पॉलीफिल्म	682.25	374.21	354.45	1.92
कामत होटल्स	207.50	107.97	103.88	2.00
विशाका इंडस्ट्रीज	93.00	68.01	46.24	2.01
कंपर्ट	4.60	2.19	2.15	2.14
इडेलवाइज फाइनेंशियल	54.49	25.32	25.32	2.15
निखिल एडहेसिव	121.25	64.07	55.12	2.20
आशीर्वाद स्टील	28.94	13.12	13.05	2.22
बीएसईएल इन्फ्रा	11.87	5.31	5.30	2.24
बीएनआर उद्योग	40.01	17.95	17.76	2.25
की कॉर्पोरेशन	58.00	25.74	25.66	2.26



## 52 हफ्ते के शिखर/तलहटी के सबसे पास

नाम	मौजूदा भाव (31.8.23)	52 हफ्ते का शिखर	शिखर के पास (%)
इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स	243.90	243.95	-0.02
फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज	28.98	28.99	-0.03
एलेकॉन इंजीनियरिंग	885.60	886.00	-0.05
टिनलेट कंपनी	385.95	386.15	-0.05
आरटेक सोलोनिकस	164.00	164.10	-0.06
आदर्श प्लांट	26.42	26.44	-0.08
लाडम एफोर्डेबल हाउसिंग	6.73	6.74	-0.15
बीसीसी फ्यूबा	58.15	58.24	-0.15
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज	240.80	241.25	-0.19
अहमदाबाद स्टीलक्राफ्ट	25.20	25.25	-0.20
बिड़लासॉफ्ट	509.85	511.10	-0.24
बामर इन्वेस्ट	444.45	445.70	-0.28
एस्सार सिक्वोरिटीज	10.41	10.44	-0.29
श्रीराम फाइनेंस	1931.50	1937.40	-0.30
लिंडे इंडिया	6280.55	6300.00	-0.31
पिकैडिली एग्रो	121.62	122.00	-0.31
सुप्रीम पेट्रो	495.45	497.00	-0.31
श्री पेसट्रोनिक्स	284.80	285.70	-0.32
सुंदरम फास्टनर्स	1275.90	1280.00	-0.32
टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स	781.10	783.70	-0.33
मौर्य उद्योग	14.20	14.25	-0.35
अल्ट्राग्रीन	436.35	438.00	-0.38
परसिस्टेंट सिस्टम्स	5368.35	5389.15	-0.39
कोफोर्ज	5467.25	5493.45	-0.48
एंजेल वन	1867.95	1877.00	-0.48
मफतलाल इंड.	119.69	120.31	-0.52
मास्टेक	2373.65	2387.10	-0.56
बीएचईएल	121.30	122.00	-0.57
एमओआईएल	238.60	240.00	-0.58
सेरा सैनिटरी	9535.20	9592.40	-0.60
बौडाडा इंजीनियरिंग	156.15	157.10	-0.60
आरएमसी स्विचगियर्स	735.00	739.50	-0.61
एआईए इंजीनियरिंग	3693.00	3716.40	-0.63
नैटको फार्मा	914.00	920.00	-0.65
फीनिक्स मिल्स	1796.90	1809.80	-0.71
केफिन टेक	446.80	450.10	-0.73
रेलटेल	209.35	210.90	-0.73
एस्ट्रा माइक्रोवेव	395.75	398.70	-0.74
सीजी पावर	431.75	435.00	-0.75
विंडसर	65.55	66.05	-0.76
केयर रेंटिंग्स	831.45	837.90	-0.77
टीवीएस मोटर	1424.45	1436.00	-0.80
पल्ट ग्लोबल	799.25	805.85	-0.82
पॉलीकैब	5120.50	5162.90	-0.82
केपीआईएल	661.45	667.00	-0.83
मारुति सुजुकी	9981.05	10064.80	-0.83
गैलेंट इस्पात	93.80	94.60	-0.85
गुजरात पेट्रोसिंथेस	45.71	46.10	-0.85
मणपुरमफाइनेंस	154.30	155.65	-0.87
हॉकिंस कुकर	6934.00	6999.00	-0.93

नाम	मौजूदा भाव (31.8.23)	52 हफ्ते की तलहटी	तलहटी के पास (%)
वेदांत	232.35	231.60	0.32
मिशका एक्जिम	29.10	29.00	0.34
सिकोजी रियल्टर्स	0.81	0.80	1.25
हिंदुजा ग्लोबल	1009.00	994.55	1.45
टीसीएनएस क्लोदिंग	380.00	374.55	1.46
टीसीआई एक्सप्रेस	1406.60	1383.75	1.65
सिबली इंड.	4.48	4.40	1.82
ईरुम फार्मा	1.02	1.00	2.00
कॉन्टिनेंटल केमिकल्स	60.09	58.90	2.02
टारसंस प्रोडक्ट	512.95	501.50	2.28
गुजरात गैस	449.45	439.00	2.38
राजपुताना इन्वेस्टमेंट	16.55	16.15	2.48
अदाणी टोटल गैस	635.60	620.15	2.49
यूपीएल	591.60	577.00	2.53
ओरिएंट बेल	468.00	456.00	2.63
लीड फाइनेंशियल	10.38	10.10	2.77
आर्नोल्ड होल्डिंग्स	17.39	16.92	2.78
इंडोको रेमेडीज	315.55	307.00	2.79
पर्पल एंटरटेनमेंट	2.56	2.49	2.81
रितेश इंटरनेशनल	35.51	34.50	2.93
गोलकुंडा एल्युमीनियम	13.50	13.10	3.05
इरोस इंटरनेशनल	18.09	17.54	3.14
टीवीएस सप्लाय	200.25	193.95	3.25
सिटी यूनिन बैंक	123.40	119.50	3.26
एसएमएस लाइफसाइंसेज	510.00	493.00	3.45
वीजेटीएफ	51.02	49.31	3.47
ऑर्टेल कम्युनिकेशंस	0.86	0.83	3.61
राजेश एक्सपोर्ट्स	500.00	482.50	3.63
सुमेधा फिस्कल	37.95	36.56	3.80
शेखावटी पॉली	0.52	0.50	4.00
गोल्डएम इंटरनेशनल	126.05	121.20	4.00
ऑचल इस्पात	11.23	10.79	4.08
डेल्टा कॉर्प	180.95	173.75	4.14
हेमांग रिसोर्सेज	37.50	36.00	4.17
पिरामिड टेक्नो	166.70	160.00	4.19
रीजेंसी ट्रस्ट	1.74	1.67	4.19
कम-ऑन कम्युनिकेशंस	2.03	1.94	4.64
प्रतीक्षा केमिकल्स	21.19	20.25	4.64
एचयूएल	2504.20	2393.00	4.65
क्रिएटिव आई	3.26	3.11	4.82
वोल्टेयर लीजिंग	11.87	11.32	4.86
कंपर्ट फिनकैप	6.80	6.47	5.10
टोयम स्पोर्ट्स	9.46	9.00	5.11
एनआईआईटी	81.01	77.06	5.13
राजस्थान पेट्रो	0.82	0.78	5.13
एस.एम. गोल्ड	14.14	13.45	5.13
अक्षिता कॉटन	25.98	24.70	5.18
एनबी फुटवीयर	2.81	2.67	5.24
श्री सिक्वोरिटीज	0.39	0.37	5.41
एनपीआर फाइनेंस	12.87	12.20	5.49

सभी चित्र : सुनील सक्सेना

# कूटनीतिक और आर्थिक रूप से बड़ी सफलता जी20 ने भारत का मान बढ़ाया

नयी दिल्ली में संपन्न हुए जी20 सम्मेलन की सफलता ने इस बात को तो इंगित किया ही कि भारत ऐसे सम्मेलन कुशलता से करा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बहुत अच्छे-से संपन्न हुआ। अतीत में अगर जायें तो पायेंगे कि 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) के सम्मेलन को इतने ही सुंदर और सुरक्षित तरीके से करवाया था। उसमें 101 देशों के 60 राष्ट्राध्यक्ष आये थे। लेकिन उसमें तब के सबसे बड़े मुद्दे - कंप्यूचिया संकट पर कोई सहमति नहीं हो पायी थी।



मधुरेंद्र सिन्हा  
वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने जी20 पर अपने एक बयान में यह नहीं बताया कि 1983 के नैम शिखर सम्मेलन में भी दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे प्रगति मैदान, केंद्रीय सचिवालय, कर्नाट प्लेस, हवाई अड्डे वगैरह में इंदिरा गांधी के बड़े-बड़े कटआउट लगाये गये थे। अखबारों में उस सम्मेलन की खूब खबरें छपी थीं। रेडियो

और टीवी में उनकी प्रशंसा के कार्यक्रम खूब चले। इस बार भी ऐसा ही हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर हर जगह दिखे, और भाजपा के प्रवक्ता-गण इसे उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि बता रहे हैं।

## जी20 का घोषणा पत्र

वसुधैव कुटुम्बकम् इस बार जी20 सम्मेलन का मुख्य विषय (थीम) था, जो प्रधानमंत्री मोदी का प्रिय विषय रहा है। इस विषय पर ही सारी चर्चाएँ केंद्रित रहीं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, पर्यावरण के मुद्दों पर पहल, सभी तरह की एजेंसियों से देशों की वित्तीय मदद, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कराधान (टैक्सेशन) जैसे विषय भी थे।

इस शिखर सम्मेलन के घोषणा-पत्र पर सभी उपस्थित देशों की सहमति प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत सफलता रही है। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। उनके विदेश मंत्री एस. जयशंकर और जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने सैकड़ों बैठकें कीं। इन दोनों के प्रयासों तथा

प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत पहल से बर्फ पिघली और यह घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से पारित हुआ।

यहाँ पर यह भी देखने वाली बात थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त समर्थन मिला। इन दोनों ने भारत का बहुत साथ दिया और घोषणा-पत्र के शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होने दी।

यह घोषणा-पत्र बहुत समझदारी से बनाया गया था, जिसमें यूक्रेन युद्ध की चर्चा तो थी लेकिन रूस को इसके लिए अपराधी बनाने जैसी कोई बात नहीं थी जैसा कि यूरोपीय देश चाहते थे। फिर भी उन्होंने इस पर सहमति दी, क्योंकि ये सभी देश, खास कर फ्रांस और जर्मनी भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं। भारत से इनके व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं और इनसे भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है।

इस सम्मेलन का फायदा उठाते हुए इसकी अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में बदलाव की बात की, जिसका अमेरिका ने खुल कर साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि आज दुनिया के हालात में





जबरदस्त बदलाव हुआ है और ऐसे में सुरक्षा परिषद को भी बदलना होगा। यह मामला भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को नहीं मिल पा रही है। चीन जैसे देश के विरोध के कारण ही भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है।

बहरहाल इस बार का सम्मेलन अल्पावधि का था और दो दिनों में ही संपन्न हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जी20 के विदेश मंत्रियों, खास कर एस. जयशंकर ने पूर्ण सहमति के लिए बहुत मेहनत की और उसका ही परिणाम था कि इसका घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से पारित हो गया।

इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है, क्योंकि इस समय दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे रूस-यूक्रेन युद्ध को इससे लगभग बाहर कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के न आने से इस सम्मेलन में भारत के लिए काम आसान हो गया, क्योंकि यूरोपीय देश यह चाहते थे कि रूस की लानत-मलानत हो। अगर वे आते तो माहौल गर्म हो जाता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से बात बन गयी।

जो यूरोपीय देश रूस के यूक्रेन पर हमले को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे, उन्हें समझाया गया कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में गरीबी कम करने और सदस्य देशों द्वारा आपस में मिल कर एक-दूसरे को ऊपर उठाने जैसे मुद्दे होते हैं। यूरोपीय देशों और खास कर उनके मीडिया में इस बात से काफी नाराजगी थी कि भारत ने चतुराई से राष्ट्रपति पुतिन को निंदा से बचा लिया।

इतना ही नहीं, भारत ने अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता दिला कर 55 देशों का दिल जीत लिया। यूरोपीय संघ हमेशा से शोषण की नीति पर चलता रहा है। मगर अफ्रीकी संघ के जी20 का सदस्य बनने से अफ्रीकी देशों की आवाज सारी दुनिया में सुनाई देगी। यह सभी जानते हैं कि अफ्रीकी देशों के कीमती संसाधनों को यूरोपीय देशों ने किस तरह से लूटा है और इसके लिए कई बार विद्रोहियों को हथियार वगैरह देकर उनकी मदद की। पूर्ण स्थायित्व और नयी तकनीक के अभाव में ये देश बुरी तरह पिछड़ गये।

यूरोप के बाद चीन ने भी उन्हें बुरी तरह से लूटा और उनके खदानों से भारी मात्रा में कीमती खनिजों की लूट मचायी। भारत ने उन्हें जी20 की सदस्यता दिला कर उनके लिए एक रास्ता खोला है। ये देश हमेशा से भारत के साथ थे और उसके सहयोग के कारण आगे भी उसके साथी बने रहेंगे। इस सम्मेलन की यह बड़ी उपलब्धि है। अब यूरोपीय देश इस मंच पर अपने गलत कामों के लिए जवाबदेह होंगे। भारत ने अपने मित्र देशों - मिस्र, नाइजीरिया और मॉरीशस के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया। इन देशों से आपसी संबंध की पुष्टि करने वाला यह एक बड़ा कदम है।

चीन के राष्ट्रपति का इस सम्मेलन में न आना कई तरह के कयासों को जन्म दे गया। आलोचक कहने लगे कि शी जिनपिंग भारत के प्रति अपनी नाराजगी दिखाना चाह रहे थे, इसलिए नहीं आये। दूसरी बात यह निकल कर आयी कि चीन में उनकी पार्टी के बड़े नेता उनके कार्यों से नाराज हैं और वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।

दरअसल चीन ने दुनिया भर के देशों को मोटे ब्याज पर ऋण देकर वहाँ बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ लगावा दीं। ये परियोजनाएँ यह कह कर लगायी गयीं कि इनसे उन देशों के लोगों को रोजगार मिलेगा तथा भविष्य में आर्थिक लाभ होगा। किंतु ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और उल्टे ये देश कर्ज के जाल में फँस गये। उनकी हालत इतनी खराब हो गयी कि उन्होंने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। अंततः चीन को उनका कहीं पर ब्याज तो कहीं पर मूल धन माफ करना पड़ा।

चीन की यह मक्कारी वाली योजना अब धराशायी हो गयी है और सभी देश इस बात को समझ गये हैं कि चीन उन्हें कर्ज के जाल में फँसा कर खुद मोटी कमाई कर रहा है। शी जिनपिंग पर दबाव इतना है कि इस समय वे चीन छोड़ना नहीं चाहते। बहरहाल उनकी अनुपस्थिति से किसी को सिरदर्द नहीं हुआ। उनके देश के प्रधानमंत्री ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इसमें भाग लिया और घोषणा-पत्र को पारित करने पर सहमति भी दी।

## सम्मेलन की भव्यता

इस जी20 सम्मेलन को इस बात के लिए भी याद रखा जायेगा कि यह अब तक का सबसे भव्य कार्यक्रम रहा। आज तक दुनिया के किसी भी देश में जी20 का इतना भव्य आयोजन नहीं हुआ था। इसके मुख्य कार्यक्रम का हॉल भारत मंडपम अतुलनीय है। रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया यह आयोजन-स्थल अपने-आप में एक उदाहरण है। इस अपूर्व सुंदर मंडपम को देखने के लिए सम्मेलन के बाद भी देश-विदेश से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अपनी खूबसूरती और



आर्किटेक्चर के कारण लोगों को यह खूब भा रहा है। इस कारण से यह न केवल भारत से जलने वाले कुछ विदेशियों के लिए, बल्कि भारत के विपक्षी दलों के लिए भी आँखों की किरकरी बन गया। इनमें कांग्रेस का नया गठबंधन भी है।

विदेशी मीडिया में इसकी आलोचना में कई लेख छपे हैं। उन्हें तकलीफ है कि 'गरीब भारत' ने इस आयोजन पर इतनी भारी रकम कैसे खर्च कर दी। जापानी और फ्रांसीसी मीडिया के एक वर्ग ने तो कह दिया कि इस आयोजन की भव्यता के पीछे अगले साल होने वाले लोक सभा चुनाव हैं। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार को इससे लाभ होगा, जिसका असर अगले साल होने वाले लोक सभा चुनाव में साफ दिखायी देगा। यानी भाजपा इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को दिखाने में करेगी।

कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारा श्रेय खुद ही ले लिया। लेकिन इसमें गलत ही क्या है? यह कहावत उन लोगों ने शायद नहीं सुनी है कि 'लड़ती है फौज, नाम होता है कप्तान का'। इस कार्यक्रम की भव्यता ने निश्चित रूप से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। यह मंडपम इतना विशाल है कि इसमें हजारों लोग आसानी से बैठ सकते हैं और खा-पी सकते हैं। कई किचन वहाँ बकायदा एक साथ काम कर रहे थे, जिनमें भारत के नामी-गिरामी शेफ भी कार्यरत थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाज (मिलेट) पर जोर दिया। मिलेट से बने व्यंजन और पकवान इस सम्मेलन में छाये रहे। भारत जिस तरह से मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहा है, वह सराहनीय है। देश में लोगों में इससे जागरूकता बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं है कि मोटे अनाज गेहूँ-चावल को पीछे छोड़ देंगे, जिनकी खेती में बड़े पैमाने पर उर्वरकों तथा जल की जरूरत होती है। एक और बात थी कि सारा भोजन शाकाहारी था और लोगों को पसंद आया। इसकी खूब प्रशंसा भी हुई। विदेशी मेहमानों के लिए ये नये प्रयोग थे, जो पसंद किये गये।

## वृत्त व्यवस्था

वहाँ जिस तरह से मिनट-मिनट का एजेंडा बनाये रखा गया और उसे बरकरार रखा गया, वह काबिले-तारीफ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने कोई कोताही नहीं छोड़ी और दिन-रात चौकसी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सहित इतने सारे मेहमान सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील थे। उनके शत्रुओं की संख्या कोई कम नहीं है और वे घात लगाये बैठे रहते हैं।



स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि खालिस्तानियों ने इस आयोजन में खलल डालने की धमकी दी थी।

लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बता दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं और अपने मेहमानों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प हैं। आयोजन के पहले दिन जिस तरह से 20 विदेशी मेहमानों का काफिला एक के बाद एक प्रगति मैदान पहुँचा, वह भी देखने लायक था। सिर्फ 40 मिनट में अपने-अपने होटलों से निकल कर ये अपने काफिलों के साथ प्रगति मैदान जा पहुँचे। तेज रफ्तार से दौड़ते मेहमानों के काफिलों में एक-दूसरे के बीच महज दो मिनट की दूरी थी। इतने सटीक ढंग से यह सब हुआ कि देखने वाले हैरान रह गये।

कार्यक्रम स्थल पर तो ऐसी सख्ती थी कि परिंदा भी पर न मार सके। मीडिया के लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में बढ़िया बसों का इंतजाम किया गया था, जहाँ से उन्हें प्रगति मैदान ले जाया गया। वहाँ उनके लिए तमाम सुविधाएँ थीं। मंडपम में हर ओर साइनेज थे और होस्ट भी थे, जो मेहमानों और मीडिया के लोगों की मदद कर रहे थे। इससे सबको बहुत सुविधा हुई।

## बांग्लादेश की बल्ले-बल्ले

प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बांग्लादेश को तबज्जो देकर एक तीर से दो शिकार किये। पहला तो यह कि इस पड़ोसी देश में भारत के प्रति मित्रता की भावना बनी रहे और दूसरी ओर पाकिस्तान को गैर-महत्वपूर्ण देश घोषित कर दिया जाये। भारत इसमें सफल रहा और पाकिस्तानी मीडिया का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पाकिस्तान में इस समय कामचलाऊ सरकार चल रही है। इसलिए वहाँ सत्ता में बैठे

लोगों का इस महत्वपूर्ण घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। वहाँ की सरकार वैसे ही महँगाई और गरीबी से जूझ रही है। भारत ने बहुत सफाई से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच से थोड़ा अलग-थलग कर दिया।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की यहाँ बहुत आवभगत हुई और बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी बांग्लादेश गये। इससे अंतरराष्ट्रीय जगत में बांग्लादेश की प्रतिष्ठा बढ़ी और दूसरी ओर भारत से प्रेम रखने वाली शेख हसीना के पाँव अपने देश में मजबूत हुए। आर्थिक दृष्टि से यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था।

## भारत मध्य-पूर्व आर्थिक कॉरीडोर

इसी सम्मेलन में भारत ने सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ मिल कर भारत मध्य-पूर्व आर्थिक गलियारे (कॉरीडोर) की घोषणा की, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का असर कम करेगा। इस कॉरीडोर में रेल, सड़क और समुद्र मार्ग से सामानों का परिवहन (ट्रांसपोर्ट) किया जायेगा। इससे भारत, अरब और यूरोप को अपने सामानों को लाने ले जाने में आसानी होगी। इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था होगी, ताकि बंदरगाह, सड़कें, पुल और संचार व्यवस्था स्थापित की जा सके। यह मुक्त और अबाध व्यापार के मार्ग में एक बड़ी सहमति है और अगर इस पर निष्ठा से काम हुआ तो सभी देशों को इससे फायदा होगा।

कुल मिला कर यह सम्मेलन हर दृष्टि से बेहद सफल रहा। एक ओर तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहमति बनी तो दूसरी ओर इससे भारत का नाम रोशन हुआ। भारत ने इसके जरिये दुनिया को अपनी सॉफ्ट पॉवर दिखा दी।

# म्यूचुअल फंडों ने क्या खरीदा, क्या बेचा : अगस्त 2023

म्यूचुअल फंडों की सबसे ज्यादा खरीदारी वाले लार्जकैप शेयर	बाजार मूल्य (क.रु.)		शेयर (लाख में)	
	अगस्त	जुलाई	अगस्त	जुलाई
	2023	2023	2023	2023
अदाणी पावर	194	46	61	17
वेदांत	581	391	250	142
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस	178	127	22	16
इंटरग्लोब एविएशन	10339	8493	425	328
डाबर इंडिया	4153	3626	751	630
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	6150	5716	138	119
टाटा पावर कंपनी	3024	2566	1234	1084
जोमैटो	8048	6195	8246	7367
यूपीएल	2952	2812	499	450
आईआरसीटीसी	570	491	85	77

म्यूचुअल फंडों की सबसे ज्यादा बिकवाली वाले लार्जकैप शेयर	बाजार मूल्य (क.रु.)		शेयर (लाख में)	
	अगस्त	जुलाई	अगस्त	जुलाई
	2023	2023	2023	2023
सीमेंस	4287	4757	109	119
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज	4855	5489	193	210
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया	5376	6142	185	199
इंडियन ऑयल	2653	3001	2977	3200
मैरिको	2283	2404	401	429
ट्रेंट	6243	5705	305	325
बर्जर पेट्रोल	722	723	100	106
टोरेट फार्मा	3164	3618	172	181
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स	4752	5112	569	595
डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज	8067	8459	144	150

म्यूचुअल फंडों की सबसे ज्यादा खरीदारी वाले मिडकैप शेयर	बाजार मूल्य (क.रु.)		शेयर (लाख में)	
	अगस्त	जुलाई	अगस्त	जुलाई
	2023	2023	2023	2023
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1705	1121	1985	1259
कोफोर्ज	14365	8106	263	172
आदित्य बिड़ला कैपिटल	662	527	366	269
स्टार हेल्थ ऐंड एलायड इन्व्हेस्टमेंट्स	1339	1089	211	171
आईआईएफएल फाइनेंस	942	782	155	133
सन टीवी नेटवर्क	737	561	119	104
एसीसी	4210	3702	210	183
एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स	3886	3831	2910	2662
पेट्रोनेट एलएनजी	1431	1423	665	609
डिक्सन टेक्नोलॉजीज	4618	3494	92	85

म्यूचुअल फंडों की सबसे ज्यादा बिकवाली वाले मिडकैप शेयर	बाजार मूल्य (क.रु.)		शेयर (लाख में)	
	अगस्त	जुलाई	अगस्त	जुलाई
	2023	2023	2023	2023
जीएमआर एयरपोर्ट्स	362	505	587	980
अशोक लेलैंड	5552	6980	3020	3793
सुप्रीम इंडस्ट्रीज	6546	6546	147	184
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स	1941	2013	1601	1935
पिरामल एंटरप्राइजेज	1167	1323	111	131
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस	3712	4195	877	1005
एस्ट्रल	4159	4782	213	243
एस्कॉर्ट्स कुबोटा	2560	2346	81	92
टाटा केमिकल्स	1958	2172	184	205
एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट	5995	6629	238	262

म्यूचुअल फंडों की सबसे ज्यादा खरीदारी वाले स्मॉलकैप शेयर	बाजार मूल्य (क.रु.)		शेयर (लाख में)	
	अगस्त	जुलाई	अगस्त	जुलाई
	2023	2023	2023	2023
आइनोंक्स विंड	395	1	193	0
सुजलॉन एनर्जी	1589	267	6471	1410
बीएसई	433	94	41	12
एसजेएस एंटरप्राइजेज	546	186	80	28
पिरामल फार्मा	476	180	464	173
जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक	224	64	249	96
गोदरेज इंडस्ट्रीज	61	24	11	5
विष्णु केमिकल्स	87	48	27	13
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स	73	36	42	22
प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स	85	40	7	4

म्यूचुअल फंडों की सबसे ज्यादा बिकवाली वाले स्मॉलकैप शेयर	बाजार मूल्य (क.रु.)		शेयर (लाख में)	
	अगस्त	जुलाई	अगस्त	जुलाई
	2023	2023	2023	2023
अनुपम रसायन	172	301	17	31
कैंपस ऐक्टिविटीयर	293	527	97	174
कैमलिन फाइन साइंसेज	127	192	77	123
ग्लोबल स्पिरिट्स	73	123	8	13
महानगर गैस	140	236	14	21
ड्रीमफॉक्स सर्विसेज	78	182	15	23
द्वारिकेश शुगर	39	57	44	62
तानला प्लेटफॉर्मर्स	87	151	9	13
जुपिटर वैगन्स	121	95	35	46
एसआईएस	205	236	43	54



**SBI MUTUAL FUND**  
A PARTNER FOR LIFE

# निवेश के नुस्खे

An investor education initiative

पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि बाजार में इस समय स्मॉलकैप को लेकर बने अति-उत्साह के बीच यदि आप इस क्षेत्र में निवेश के लिए उत्सुक हैं, तो आपको किन बातों के बारे में सोचना-समझना चाहिए। उसमें यह भी बात शामिल थी कि यदि स्मॉलकैप शेयरों की तेजी का लाभ उठाना है, तो अधिकांश निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड ही इसका सही रास्ता है। इस बात को यहाँ थोड़े और विस्तार से समझते हैं।

पहले आप यह समझें कि स्मॉलकैप श्रेणी में कितने शेयर हैं? बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध कुल शेयरों की संख्या लगभग पाँच-छह हजार है। इनमें से लाजकैप में सबसे बड़े 100 शेयर और मिडकैप में उनके बाद वाले 150 शेयर आते हैं, बाकी सब स्मॉलकैप हैं। मतलब स्मॉलकैप शेयरों की संख्या पाँच हजार से अधिक है। क्या आप इतने अधिक शेयरों के बीच में से अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक अच्छे शेयर चुनने की योग्यता एवं समझ रखते हैं? इस तरह के रिसर्च में अच्छा-खासा समय लगता है, तो क्या आपके पास उतना समय है?

इसके बाद, ये जो पाँच हजार से अधिक स्मॉलकैप शेयर हैं, उनमें से अधिकांश के बारे में आपको सामान्य रूप से मीडिया पर या इंटरनेट पर खोजने से बहुत जानकारी नहीं मिल पाती है। बेशक, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर आपको इनके बारे में उतनी न्यूनतम जानकारियाँ मिल जायेंगी, जितनी लिस्टिंग नियमों के अनुसार कंपनियों को एक्सचेंजों के सामने रखनी अनिवार्य होती है। फिर भी, इनके बारे में पर्याप्त विश्लेषण करने लायक सामग्री की कमी महसूस होती है।

आप इन पाँच हजार से अधिक स्मॉलकैप शेयरों में से निवेश लायक अच्छे शेयरों को चुनने को कुछ इस तरह समझ लें कि आपके सामने एक टोकरी में 100 सेब रखे हैं और उनमें से शायद पाँच-दस ही सेब खाने लायक अच्छे हैं,

## स्मॉलकैप में निवेश के लिए और अधिक सही है म्यूचुअल फंड



बाकी बहुत सारे कच्चे हैं और कुछ सड़े हुए हैं। और कुछ सेब ऐसे भी हैं जो अंदर से सड़े हैं, पर बाहर से देखने पर इसका नहीं पता चलता और कोई अनुभवी व्यक्ति ही इस बात को परख सकता है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसी टोकरी से सेब चुन कर खरीदना हो तो आपको कितने सेब अच्छे मिलेंगे और कितने कच्चे या सड़े हुए।

एक और बात समझने की यह है कि अपने पोर्टफोलियो में आप कितने स्मॉलकैप शेयर रख सकते हैं? यदि आप बहुत ज्यादा, जैसे 50-100 स्मॉलकैप शेयर रखने लेंगे तो एक व्यक्तिगत निवेशक के रूप में इन सब पर नजर रखना संभव नहीं रह जायेगा। और यदि आप बहुत कम स्मॉलकैप शेयरों का पोर्टफोलियो बनायें तो उनमें संकेंद्रित जोखिम (कंसंट्रेशन रिस्क) की स्थिति बन जायेगी। मतलब यह कि आपके चुने हुए स्मॉलकैप शेयरों में से अगर दो-चार ने भी बहुत खराब प्रदर्शन किया तो पूरे पोर्टफोलियो

का प्रदर्शन बिगड़ जायेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि स्मॉलकैप शेयरों में उतार-चढ़ाव बहुत बड़े स्तर का भी हो सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 स्मॉलकैप शेयरों में बराबर-बराबर पैसा लगाया, मतलब 100 में से 10-10 रुपया, और इनमें से दो शेयर भी 80% पिट गये, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में 16% का नुकसान हो जायेगा। यह केवल एक काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि स्मॉलकैप शेयरों में गलत चुनाव से ऐसी स्थिति बन जाने के काफी उदाहरण मिलते हैं।

वहीं यदि आप एक स्मॉलकैप फंड के जरिये निवेश करें, तो आपका निवेश एक बड़ी संख्या में स्मॉलकैप शेयरों में बँट जाता है और वे शेयर भी बहुत सावधानी के साथ एक पेशेवर विशेषज्ञ टीम के द्वारा चुने हुए होते हैं। ऐसे में स्वयं स्मॉलकैप शेयरों का पोर्टफोलियो बनाने की तुलना में वहाँ जोखिम घट जाता है। वहीं यदि आप एक स्मॉलकैप इंडेक्स फंड में निवेश करें, तो यहाँ आपका निवेश 100 से लेकर 250 शेयरों तक में बँटा हो सकता है, जो निर्भर करता है कि आपने किस स्मॉलकैप इंडेक्स फंड को चुना है। यहाँ किसी एक शेयर के उतार-चढ़ाव से बनने वाला जोखिम और भी कम होता है।

फिर भी, याद रखें कि अपने-आप में स्मॉलकैप श्रेणी तुलनात्मक रूप से ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली और अधिक जोखिम वाली है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि आपको अपने पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो में सीधे या फंडों के माध्यम से स्मॉलकैप निवेश 10-15% से अधिक नहीं रखना चाहिए।

### निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए एक पहल

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) : निवेशकों को केवल पंजीकृत म्यूचुअल फंडों के साथ लेन-देन करना चाहिए, जिनके विवरणों की पुष्टि सेबी की वेबसाइट (<https://www.sebi.gov.in>) पर Intermediaries/Market Infrastructure Institutions वाले भाग में की जा सकती है। कृपया एक बार केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करने और पते, फोन नंबर, बैंक विवरण आदि में बदलाव के लिए म्यूचुअल फंडों की वेबसाइट देखें। निवेशक पंजीकृत इंटरमीडियरी के विरुद्ध शिकायतें <https://www.scores.gov.in> पर दर्ज करा सकते हैं, यदि वे उनके उत्तरों से असंतुष्ट हों। स्कोर्स आपको सेबी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने और बाद में उसकी स्थिति देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी से पढ़ें।



## म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रदर्शन

	एयूएम (करोड़ रु)*	एनएवी (रु.) (31.8.2023)	1 माह (%)	6 माह (%)	1 साल (%)	3 साल (%)	5 साल (%)	10 साल (%)
<b>फ्लेक्सिकैप</b>								
जेएम फ्लेक्सि कैप फंड	475.25	67.08	1.76	24.30	24.87	28.89	15.39	19.55
एचडीएफसी फ्लेक्सि कैप फंड	38266.03	1310.43	0.04	17.57	19.59	30.54	14.49	18.37
पराग पारिख फ्लेक्सि कैप फंड	39848.26	56.95	-0.19	17.35	18.33	21.65	17.16	19.44
व्हाइटओक कैपिटल फ्लेक्सि कैप फंड	1635.24	12.16	1.30	22.33	18.02			
महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सि कैप फंड	1033.59	12.16	1.16	20.56	16.89			
फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सि कैप फंड	11698.55	1144.35	0.63	19.02	16.81	27.07	12.99	17.73
डीएसपी फ्लेक्सि कैप फंड	8827.32	75.34	1.70	19.29	16.71	22.30	13.38	17.73
क्वांट फ्लेक्सि कैप फंड	1782.48	69.79	-0.61	19.83	16.69	34.68	21.14	24.36
इन्व्हेस्को इंडिया फ्लेक्सि कैप फंड	1071.43	12.07	1.17	18.33	16.17			
एचएसबीसी फ्लेक्सि कैप फंड	3553.95	149.73	0.26	17.69	15.99	21.95	10.08	16.22
<b>मल्टीकैप इक्विटी</b>								
निप्पोन इंडिया मल्टीकैप फंड	18974.37	208.61	3.01	28.76	29.80	35.94	16.44	18.78
महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड	1987.76	25.04	3.63	26.15	21.11	29.71	17.49	
आईटीआई मल्टीकैप फंड	623.97	16.66	2.09	23.28	20.42	20.66		
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड	8421.59	545.49	0.47	19.90	19.52	26.32	12.32	17.43
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टीकैप फंड	4308.74	14.39	1.55	20.42	16.90			
बडौदा बीएनपी परिवार मल्टीकैप फंड	1871.82	198.02	0.72	17.74	16.83	26.72	13.90	16.15
इन्व्हेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड	2695.29	90.98	0.60	19.18	16.73	24.73	11.55	19.80
क्वांट ऐक्टिव फंड	5348.92	499.68	1.14	21.41	15.53	32.71	21.48	24.03
सुंदरम मल्टीकैप फंड	2068.38	272.23	1.63	18.58	12.05	25.95	12.60	18.50
एसबीआई मल्टीकैप फंड	12888.36	11.99	1.82	18.47	11.14			
<b>लाजिकैप इक्विटी</b>								
निप्पोन इंडिया लाजिकैप फंड	15583.03	64.45	-0.19	20.16	20.13	27.08	12.85	17.74
एचडीएफसी टॉप 100 फंड	25775.56	841.30	-1.63	14.88	15.10	23.94	11.48	15.89
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड	40285.71	77.20	-0.23	14.76	14.44	21.67	12.29	15.96
इडेलवाइज लाजिकैप फंड	530.52	62.87	-0.90	14.50	14.18	19.16	10.99	15.18
डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड	3010.49	331.34	-0.95	15.21	13.80	18.75	9.20	12.83
जेएम लाजिकैप फंड	48.73	113.02	-0.79	14.06	13.69	17.20	11.07	13.52
एसबीआई ब्लू चिप फंड	39301.06	70.42	-1.67	13.67	12.38	21.77	11.90	16.69
बडौदा बीएनपी परिवार लाजिकैप फंड	1517.48	158.75	-1.38	13.60	11.57	19.05	12.30	15.29
आदित्य बिड़ला सन लाइफ फंटलाइन इक्विटी फंड	23758.17	386.35	-1.03	14.32	11.48	21.09	10.81	15.44
टाटा लाजिकैप फंड	1613.33	373.30	-1.66	13.69	11.43	21.37	10.81	13.80
<b>लाज एंड मिडकैप इक्विटी</b>								
मोतीलाल ओसवाल लाज एंड मिडकैप फंड	1952.85	20.62	3.16	22.49	26.09	28.47		
एचडीएफसी लाज एंड मिडकैप फंड	10679.64	239.40	1.46	24.31	22.13	29.88	15.49	14.82
बंधन कोर इक्विटी फंड	2802.06	86.03	1.24	20.13	21.33	25.93	12.62	15.55
यूटीआई कोर इक्विटी फंड	1887.32	120.65	0.62	21.59	19.29	27.33	12.93	15.36
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाज एंड मिडकैप फंड	9123.49	665.54	-0.31	16.95	17.76	28.83	14.94	16.40
कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड	14654.79	240.99	0.45	18.89	17.61	24.99	14.98	18.07
डीएसपी इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड	8690.55	420.74	1.37	18.86	17.24	23.56	13.12	17.74
एचएसबीसी लाज एंड मिडकैप फंड	2301.98	18.47	2.13	20.72	17.19	23.57		
एसबीआई लाज एंड मिडकैप फंड	13871.46	450.15	0.43	17.40	16.89	27.71	14.91	19.16
महिंद्रा मनुलाइफ लाज एंड मिडकैप फंड	1341.09	20.08	1.69	22.78	16.55	27.11		
<b>मिडकैप</b>								
एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड	45449.36	129.08	2.72	29.33	31.42	33.75	16.90	23.38
टॉरस डिस्कवरी मिडकैप फंड	93.86	97.19	5.25	31.77	30.16	28.03	15.49	21.96
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड	5236.88	62.50	5.58	23.92	26.43	36.72	17.62	
निप्पोन इंडिया ग्रोथ फंड	17349.69	2689.46	4.08	28.10	25.12	32.56	18.58	20.84
महिंद्रा मनुलाइफ मिडकैप फंड	1385.23	22.27	4.58	29.38	24.42	31.15	17.17	
टाटा मिडकैप ग्रोथ फंड	2315.18	307.18	3.55	27.84	23.15	29.35	16.82	22.34
इन्व्हेस्को इंडिया मिडकैप फंड	3292.97	106.63	2.97	24.09	21.71	27.12	15.40	22.37
क्वांट मिडकैप फंड	2531.32	157.25	0.82	23.04	21.09	37.57	21.15	17.49
फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड	8650.53	1823.22	2.68	22.53	20.79	25.62	12.72	20.48
बंधन मिडकैप फंड	811.51	12.04	4.53	24.34	20.12			

## म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रदर्शन

	एयूएम (करोड़ रु)*	एनएवी (रु.) (31.8.2023)	1 माह (%)	6 माह (%)	1 साल (%)	3 साल (%)	5 साल (%)	10 साल (%)
<b>स्मॉलकैप</b>								
क्वांट स्मॉलकैप फंड	6779.64	181.02	4.05	30.67	37.76	48.72	28.39	17.75
एचडीएफसी स्मॉलकैप फंड	21066.57	104.11	3.45	32.25	37.63	40.58	17.61	21.98
फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड	9103.82	125.20	4.99	29.94	37.58	39.55	16.58	23.80
निप्पोन इंडिया स्मॉलकैप फंड	34468.92	121.16	4.73	33.68	35.23	43.99	21.91	30.21
एचएसबीसी स्मॉलकैप फंड	10766.46	61.68	6.44	31.59	31.78	42.90	17.66	
टाटा स्मॉलकैप फंड	5683.23	28.99	2.53	24.46	29.44	39.31		
डीएसपी स्मॉलकैप फंड	11651.12	144.40	2.95	31.52	28.68	35.84	19.00	26.63
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉलकैप फंड	4159.84	66.24	4.58	31.78	26.89	31.66	10.94	19.89
आईटीआई स्मॉलकैप फंड	1383.50	17.94	3.12	28.06	26.58	24.28		
सुंदरम स्मॉलकैप फंड	2464.48	187.37	4.22	28.45	26.31	35.77	15.67	22.39
<b>ईएलएसएस</b>								
एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड	15374.28	284.65	0.26	22.57	23.47	26.22	14.02	16.96
मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड	2499.96	32.10	2.14	20.26	21.01	24.66	12.19	
टॉरस टैक्सशील्ड	64.92	134.86	1.37	14.13	19.84	20.20	10.21	15.51
जेएम टैक्स गेन फंड	87.30	33.97	1.75	21.03	19.46	25.38	14.23	18.99
बंधन टैक्स एडवांटेज (ईएलएसएस) फंड	5014.01	118.12	0.53	20.63	19.19	30.26	14.81	19.18
एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड	11296.28	932.73	0.29	17.67	18.22	25.69	11.56	16.27
फ्रैंकलिन इंडिया टैक्सशील्ड फंड	5249.73	1030.60	0.56	18.90	17.00	25.93	11.90	16.90
पराग पारिख टैक्स सेवर फंड	1849.01	22.35	0.75	12.65	16.92	23.98		
आईटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड	195.17	16.25	1.05	17.99	16.74	18.15		
बैक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड	840.87	114.53	-0.38	18.41	16.03	24.99	15.13	18.21
<b>वैल्यू ऐड कॉन्ट्रा</b>								
जेएम वैल्यू फंड	205.23	69.28	3.50	28.81	35.67	31.18	15.75	20.48
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड	4571.97	90.76	2.88	28.12	25.28	26.75	9.07	19.34
एचएसबीसी वैल्यू फंड	9077.27	72.75	2.10	22.08	24.99	28.33	13.81	20.88
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड	13460.88	271.89	1.29	20.85	24.53	35.81	18.73	18.56
आईसीआईआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड	32659.44	318.76	0.75	16.47	21.26	27.93	15.69	20.52
बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड	6542.73	110.30	0.55	21.35	21.08	35.76	14.64	19.59
आईटीआई वैल्यू फंड	138.50	11.97	-0.59	19.34	21.04			
कैनरा रोबेको वैल्यू फंड	913.93	13.20	0.00	17.75	19.57			
टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड	1228.94	517.56	0.63	17.91	19.35	31.67	13.69	17.53
यूनियन वैल्यू डिस्कवरी फंड	171.97	20.41	1.24	20.77	18.25	24.25		
<b>फोकस फंड</b>								
जेएम फोकस फंड	50.85	14.52	2.95	22.00	22.75	21.92	9.10	17.30
एचडीएफसी फोकस 30 फंड	5828.07	151.64	0.45	16.30	19.57	30.33	13.67	17.40
360 वन फोकस इक्विटी फंड	4336.64	35.15	0.57	18.06	18.20	24.79	16.36	
आईसीआईआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड	4839.89	59.42	-1.52	17.80	16.88	24.31	13.18	15.62
महिंद्रा मनुलाइफ फोकस फंड	824.56	18.13	-0.72	16.04	15.92			
फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड	9386.80	79.20	-0.04	17.09	15.25	27.92	14.34	19.82
एचएसबीसी फोकस फंड	1456.98	18.17	-0.52	17.70	13.87	21.81		
टाटा फोकस इक्विटी फंड	1381.84	17.30	-0.05	16.59	13.81	22.74		
इडेलवाइज फोकस इक्विटी फंड	592.96	11.72	-0.64	15.98	13.69			
डीएसपी फोकस फंड	1975.05	38.36	1.04	18.74	13.16	18.56	9.81	15.27
<b>इंटरनेशनल इक्विटी</b>								
इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को पैन यूरोपियन इक्विटी फंड ऑफ फंड	36.72	15.51	-1.94	3.34	31.51	15.16	5.77	
मोतीलाल ओसवाल नैसडैक 100 ईटीएफ	6616.36	124.93	-1.19	28.14	28.04	13.15	18.77	19.76
इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी इन्कम फंड ऑफ फंड	18.25	20.94	-1.47	8.98	26.37	16.43	9.40	
इडेलवाइज यूरोप डायनैमिक इक्विटी ऑफशोर फंड	81.76	16.45	-1.34	2.48	24.56	11.38	6.53	
पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड	1494.76	32.70	-0.18	19.47	24.52	2.19	13.13	7.52
आदित्य बिड़ला एसएल ग्लोबल एक्सिलेंस इक्विटी एफओएफ - रिटेल	164.07	25.17	-0.61	18.31	24.14	11.63	5.53	4.81
सुंदरम ग्लोबल ब्रांड फंड	123.72	26.94	-2.17	13.91	24.09	10.19	9.66	6.02
आईसीआईआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लूचिप इक्विटी फंड	2910.79	52.82	-3.14	12.72	23.67	14.87	14.49	13.17
फ्रैंकलिन इंडिया फोडर - टेम्पल्टन यूरोपियन अपॉर्च्युनिटीज फंड	19.00	10.07	-0.74	6.71	22.67	7.65	-1.04	
निप्पोन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड	587.27	8.98	-0.30	18.38	21.92			

## म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रदर्शन

	एयूएम (करोड़ रु)*	एनएवी (रु.) (31.8.2023)	1 माह (%)	6 माह (%)	1 साल (%)	3 साल (%)	5 साल (%)	10 साल (%)
<b>मल्टी एसेट एलोकेशन</b>								
आईसीआईआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड	21705.11	538.87	0.76	13.84	19.01	24.86	15.44	16.97
यूटीआई मल्टी एसेट फंड	858.04	51.61	-0.14	14.43	15.98	12.72	8.44	9.25
एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड	1246.31	44.22	1.57	14.73	14.93	12.83	11.21	10.80
मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड	113.15	12.30	4.06	14.07	14.77	7.10		
निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड	1413.27	15.19	0.10	13.04	14.29	14.90		
क्वांट मल्टी एसेट फंड	936.86	94.00	-1.19	12.14	13.33	27.50	22.05	13.92
टाटा मल्टी एसेट ऑर्पोरुनिटीज फंड	1756.60	17.80	-0.04	11.04	12.17	17.23		
एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड	1912.65	54.15	-0.55	10.30	10.94	15.04	10.84	11.09
ऐक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड	1432.45	30.90	-1.01	9.38	3.21	12.64	9.49	9.84
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड	2433.82	11.12	0.10	12.96				
<b>डायनामिक एसेट एलोकेशन</b>								
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	60640.94	370.62	0.71	15.92	19.50	26.20	13.74	17.37
मोतीलाल ओसवाल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	684.57	18.34	4.94	21.84	18.34	11.11	8.40	
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	23537.15	11.98	0.12	11.72	14.13			
बडौदा बीएनपी परिबा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	3310.64	18.53	-0.25	11.55	12.31	14.36		
मिरेड एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	1179.20	11.22	0.01	12.32	11.88			
महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	590.26	11.26	1.36	13.94	11.47			
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	6817.95	82.38	-0.08	10.50	10.64	13.66	9.68	12.32
एचएसबीसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	1414.94	34.41	0.66	10.06	10.35	8.92	7.63	11.97
टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	7412.26	16.60	-0.56	9.93	10.17	13.91		
आईसीआईआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	48720.65	56.90	0.39	8.73	10.02	14.37	10.61	13.24
<b>इंडेक्स फंड एवं ईटीएफ</b>								
मिरेड एसेट एनवाईएसई फैंग+ ईटीएफ	1642.91	64.26	-1.85	42.29	53.83			
निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक बीज	1341.62	49.65	-3.35	22.57	48.98	43.71	6.18	8.70
कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ	1102.73	444.85	-3.35	22.55	48.94	43.59	6.05	8.64
मोतीलाल ओसवाल एसएंडपी बीएसई एनहेंस्ड वैल्यू ईटीएफ	8.63	58.69	-0.86	25.35	37.48			
मोतीलाल ओसवाल एसएंडपी बीएसई एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड	19.43	14.30	-0.94	24.81	35.93			
भारत 22 ईटीएफ	11403.99	70.18	-1.66	21.64	31.73	37.47	12.88	
कोटक निफ्टी मिडकैप 50 ईटीएफ	12.52	112.97	3.45	32.58	30.92			
ऐक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स फंड	82.08	13.42	3.30	31.78	29.52			
सीपीएसई ईटीएफ	22536.56	47.81	0.11	22.10	28.69	37.23	11.46	
मोतीलाल ओसवाल नैसडैक 100 ईटीएफ	6616.36	124.93	-1.19	28.14	28.04	13.15	18.77	19.76
<b>गोल्ड ईटीएफ</b>								
डीएसपी सिल्वर ईटीएफ	39.64	73.73	1.23	17.78	34.86			
एलआईसी एमएफ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	107.41	5441.75	-0.20	6.73	15.23	3.95	13.69	5.27
यूटीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	793.78	50.70	-0.22	6.50	14.74	3.21	13.25	4.96
आईसीआईआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ	3220.21	52.01	-0.07	6.72	14.69	3.60	13.42	4.91
इन्व्हेस्को इंडिया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	96.37	5278.83	-0.22	6.42	14.68	3.64	13.64	4.92
आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ	636.22	53.44	-0.14	6.49	14.63	3.59	13.59	5.00
निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज	7858.54	50.58	-0.10	6.60	14.57	3.37	13.33	4.99
ऐक्सिस गोल्ड ईटीएफ फंड	820.39	50.69	-0.22	6.03	14.56	3.66	13.55	4.79
एसबीआई गोल्ड ईटीएफ	3108.68	52.08	-0.23	6.35	14.54	3.55	13.51	5.02
क्वांटम गोल्ड फंड	167.31	50.32	-0.26	6.31	14.52	3.27	13.34	4.92
<b>रिटायरमेंट फंड</b>								
एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - इक्विटी	3570.07	37.44	0.24	20.43	23.15	29.98	16.84	
एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - हाइब्रिड - इक्विटी	1126.60	30.32	0.24	15.97	18.22	20.98	12.73	
आईसीआईआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड - प्योर इक्विटी	330.84	20.65	0.49	24.55	18.00	28.64		
निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड - वेल्थ क्रिएशन स्कीम	2601.26	20.90	0.89	21.08	16.88	23.19	8.23	
आईसीआईआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड - हाइब्रिड एग्रेसिव	206.77	17.54	0.46	21.38	15.24	19.46		
एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड - एग्रेसिव प्लान	1657.48	15.91	0.47	16.55	15.23			
एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड - एग्रेसिव हाइब्रिड	1080.49	15.08	0.85	14.36	14.03			
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - प्रोग्रेसिव प्लान	1491.78	48.49	1.89	19.21	13.41	17.10	9.59	16.35
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड - मॉडरेट प्लान	1741.29	48.89	1.67	17.28	13.10	16.08	9.46	16.21
यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड	4011.01	39.31	0.27	10.22	11.12	14.41	8.11	10.58





## Explore country's First Women Oriented Financial Education and Awareness Platform!

for her  
FINANCIAL EDUCATION



Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully

All investors have to go through a one-time KYC (Know Your Customer) process. Investors to invest only with SEBI registered Mutual Funds. For further information on KYC, list of SEBI registered Mutual Funds and redressal of complaints including details about SEBI SCORES portal, visit link - <https://mutualfund.adityabirlacapital.com/investor-education/education/kyc-and-redressal-for-further-details>

संपदा-सृजन की राह : निवेशक शिक्षा के लिए आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की पहल

# ऐक्टिव और पैसिव फंडों के बीच कैसे बनायें संतुलन

पिछले कई अंकों में हमने निष्क्रिय (पैसिव) फंडों में निवेश के संबंध में चर्चा की है और यह समझा है कि पैसिव फंड क्या होते हैं और किस तरह के निवेशकों को इनमें किस तरह से निवेश करना चाहिए। मोटी बात यह है कि गहन रिसर्च में उलझे बिना आराम से अपने निवेश पर एक अच्छा प्रतिफल (रिटर्न) पाने के लिए ये निष्क्रिय या पैसिव फंड अच्छा विकल्प हैं। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि सक्रिय (ऐक्टिव) फंड से एकदम दूर हो लिया जाये। हर निवेशक को दोनों में अपने निवेश का कुछ हिस्सा रखना चाहिए। यह जरूर है कि उनका अनुपात निवेशक की जोखिम क्षमता और निवेश अवधि जैसी बातों पर निर्भर करेगा।

अपने पोर्टफोलियो में सक्रिय (ऐक्टिव) और निष्क्रिय (पैसिव) दोनों तरह के फंडों को रख कर विविधता लाने से एक अच्छा संतुलन मिल सकता है। सक्रिय फंड कुछ बाजार स्थितियों या परिसंपत्ति वर्गों (एसेट क्लास) में उत्कृष्ट लाभ दिला सकते हैं, जबकि निष्क्रिय फंड व्यापक रूप से बाजार में निवेश का लाभ दे सकते हैं। इस तरह का मिश्रण बनाना जोखिम को कम करने और आपके पोर्टफोलियो के लचीलेपन को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सक्रिय और निष्क्रिय फंडों के मिश्रण का अनुपात कैसा रखा जाये, यह निर्णय आपके निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहने की क्षमता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के फंडों के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए यह निर्णय लेते समय अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सक्रिय फंडों का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजर्स द्वारा किया जाता है, जिनका लक्ष्य

बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना होता है। चूंकि यहाँ सक्रिय प्रबंधन है, तो इससे जुड़ी लागतों के कारण इनका व्यय अनुपात (एक्सपेंस रेश्यो) अधिक होता है। लेकिन जब सक्रिय फंड लगातार अपने मानक (बेंचमार्क) से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनके उच्च शुल्क की भरपाई भी हो जाती है।

ऐसे में अच्छा सक्रिय फंड चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो प्रतिफल (रिटर्न) के मामले में अपने मानक को पीछे छोड़ सके। इस चयन के



लिए भी एक तरह की विशेषज्ञता की जरूरत है। जब आप निवेश के लिए एक सक्रिय फंड चुनते हैं, तो फंड मैनेजर या प्रबंधन टीम के पिछले प्रदर्शन (ट्रैक रिकॉर्ड) पर ध्यान देना होता है और खास कर कई बाजार चक्रों यानी कई दौर की तेजी-मंदी में लगातार बेहतर प्रदर्शन वाले फंडों को लेना बेहतर होता है।

दूसरी ओर, निष्क्रिय फंडों का लक्ष्य किसी सूचकांक या परिसंपत्ति वर्ग (एसेट क्लास), जैसे सोना आदि के प्रदर्शन को दोहराना है, और वे कम शुल्क के साथ बाजार में निवेश का जरिया तलाशने वाले निवेशकों के लिए

उपयुक्त हैं। इसलिए निष्क्रिय (पैसिव) फंडों में फंड मैनेजर या प्रबंधन टीम का इतना असर नहीं होता। किसी एक सूचकांक, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी का अनुसरण करने वाले अलग-अलग पैसिव फंडों का प्रदर्शन कमोबेश एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि वे सभी अपने निवेश में पूरी तरह से उस सूचकांक में शामिल शेयरों को बिल्कुल उसी अनुपात में रखेंगे।

निष्क्रिय फंडों में आम तौर पर सक्रिय फंडों की तुलना में कम व्यय अनुपात होता है, मतलब प्रबंधन शुल्क कम होता है, क्योंकि उन्हें कम सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लागत कम रहने के चलते ऐसे फंडों में समय के साथ आपके समग्र प्रतिफल (रिटर्न) में सुधार हो सकता है।

तो अब अपने लिए सक्रिय और निष्क्रिय फंडों का सही संतुलन कैसे चुनें? इसके लिए आप स्वयं से ये सवाल पूछें :

1. क्या आप सक्रिय फंडों को स्वयं चुनने की योग्यता रखते हैं और उसके लिए जरूरी समय दे सकते हैं, या फिर क्या आप इसके लिए पेशेवर सलाहकार की मदद लेंगे? यदि हाँ, तो आप अपने पोर्टफोलियो में सक्रिय फंडों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि नहीं, तो निष्क्रिय फंडों को अधिक रखें।
2. आप बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कितना सह सकते हैं? सक्रिय फंड जहाँ निष्क्रिय फंडों की तुलना में ऊँचा लाभ देने की क्षमता रखते हैं, वहीं कई अवसरों पर इनमें आने वाली गिरावटें मानक सूचकांक से अधिक हो सकती हैं। निष्क्रिय फंड में उतार-चढ़ाव मानक सूचकांक के आसपास ही रहेगा। मतलब आपकी जोखिम सहनशीलता अधिक हो, तो सक्रिय फंडों को अधिक रखें और कम ही जोखिम लेना चाहते हैं तो निष्क्रिय फंडों में अधिक निवेश करें।

### An Investor education and Awareness initiative of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund.

All investors have to go through a one-time KYC (Know Your Customer) process. Investors to invest only with SEBI registered Mutual Funds. For further information on KYC, list of SEBI registered Mutual Funds and redressal of complaints including details about SEBI SCORES portal, visit link : <https://mutualfund.adityabirlacapital.com/Investor-Education/education/kyc-and-redressal-for-further-details>  
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

# महंगाई कब तक? जब तक समोसे में आलू!



राग बाजारी  
राजीव रंजन झा

एक मित्र सुबह-सुबह बरस पड़े, खाक अच्छे दिन आये हैं! ठीक है कि आलू-प्याज सस्ते हो गये, लेकिन समोसा कब सस्ता होगा? गाड़ी में डालने का तेल ही नहीं, खाने का तेल भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो चला है। फिर यहाँ समोसा सस्ता क्यों नहीं हुआ?

मैंने उन्हें समझाना चाहा कि भाई, थोक महंगाई दर शून्य पर भले आ गयी है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ही है कि कीमतें शून्य हो जायेंगी और सब चीजें मुफ्त मिलने लगेंगी। महंगाई दर शून्य होने का मतलब बस यह है कि दाम बढ़े नहीं हैं, जितने थे उतने ही हैं। और शून्य महंगाई दर का यह आँकड़ा थोक का है, खुदरा बाजार में थोड़े-बहुत दाम अब भी बढ़ ही रहे हैं, भले ही बहुत हल्की दर से।

महंगाई का एक सामान्य नियम यह है कि जिस चीज के दाम एक बार बढ़ गये, वो बढ़ गये। फिर वे अमूमन लौट कर पुराने स्टेसन पर नहीं आते। यह गाड़ी केवल एक तरफ जाती है। इसका कोई टर्मिनल नहीं है जहाँ से यह पलट कर वापस उस ओर चलने लगे जहाँ से आयी थी। खुदरा कीमतों पर यह नियम पूरी तरह लागू होता है।

भले ही अखबार में पढ़ने को मिले कि मंडी में सब्जियाँ सस्ती हो गयी हैं, लेकिन ठेले वाला आपको उसी पुराने भाव पर सब्जियाँ देता रहेगा। ज्यादातर लोगों को मंडी के भावों का पता ही नहीं होगा। जिन्हें पता होगा, उनमें ज्यादातर लोग टोकने की हिम्मत नहीं करेंगे और किसी ने टोक दिया तो ठेले वाला उसे एक राजनीतिक किस्म का बयान पकड़ा देगा। शायद अंत में एहसान करके 5 रुपये कम कर दे।

अगर आप टीवी पर विज्ञापनों को खबरों से ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो आप हमेशा इस खुशफहमी में रहेंगे कि कीमतें तो हमेशा घटती हैं। कौन-सी चीज ऐसी है जिस पर कुछ-न-कुछ छूट नहीं मिलती।

टूथपेस्ट के दाम हमेशा घट ही जाते हैं! च्यवनप्राश भी टीवी के विज्ञापन में हमेशा पहले से सस्ता ही होता जाता है। गाड़ियों की हमेशा

बंपर सेल ही चलती है। कपड़े हमेशा मेगा-सेल में मिलते हैं। लेकिन बाजार जाते ही पता नहीं कैसे आपकी जेब पहले से ज्यादा हल्की हो जाती है!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी पीठ ठोक सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और महंगाई घटा दी। आखिर अब थोक महंगाई दर नवंबर 2014 के महीने में शून्य पर आ गयी। साल भर पहले नवंबर 2013 में यह 7.52% और महीने भर पहले अक्टूबर 2014 में 1.77% पर थी। अब और क्या चाहिए! खुदरा महंगाई दर भी कुछ खास नहीं रही। यह नवंबर 2014 में 4.38% के न्यूनतम स्तर पर आ गयी है।

थोक महंगाई के आँकड़े बता रहे हैं कि प्याज 56.28% सस्ता हो गया है। सब्जियाँ औसतन 28.57% सस्ती हो गयी हैं। अगली बार सब्जी

यह लेख मूल रूप से दिसंबर 2014 में एक दैनिक समाचार पत्र के लिए लिखा गया था। इसकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं, इसलिए इसमें बिना किसी बदलाव के, केवल थोड़ा छोटा करके पुनः आपके सामने रखा जा रहा है।



लेने जायें तो कैलकुलेटर साथ ले जायें और अखबार की कतरन भी। ठेले वाले को दिखा कर बतायें कि भई दाम 28.57% कम करो। लेकिन हो सकता है कि वह भी अखबार की ताजा कतरन दिखा कर आपको बता दे कि नहीं जी, आलू की महंगाई तो नवंबर में 34.10% बढ़ी है।

कितना मजेदार दृश्य होगा कि एक खरीदार और एक ठेले वाला सब्जियों की कीमतों पर मोलभाव कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए एक गणितज्ञ, एक सांख्यिकीविद और एक अर्थशास्त्री साथ में खड़े हैं!

लेकिन आलू का पारितंत्र केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यह पारितंत्र जहाँ से शुरू होता है, उसकी तो हमने अब तक बात ही नहीं की।

बेचारा किसान। आपको अपने समोसे की पड़ी है, उधर वह किसान रो रहा है कि उसे अपनी फसल की लागत भी ठीक से वापस मिलेगी या नहीं। समय और मेहनत की कीमत तो जाने दीजिए, कम-से-कम खाद-बीज-कीटनाशक पर लगे पैसे तो वापस आ जायें।

चंडीगढ़ से बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर बता रही है कि नयी फसल आने पर इस दिसंबर में किसानों को आलू 5-7 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना पड़ रहा है। पिछले दिसंबर में उन्हें 16-20 रुपये तक के भाव मिल गये थे। पिछले साल के ऊँचे दाम देख कर देश भर के किसानों ने इस बार आलू की जम कर खेती कर ली, अब मंडी में देश के हर कोने से आलू आने को तैयार बैठा है।

अब सरकार किसके अच्छे दिनों की चिंता करे? किसान के अच्छे दिन आते हैं तो देश भर के उपभोक्ता रोने लगते हैं। उपभोक्ता की चिंता करें तो किसान कर्ज में डूब जाता है। पूरी श्रृंखला में प्रतिशत के हिसाब से ठेले वाला सबसे ज्यादा हिस्सा ले जाता है, मगर वह पिछले साल भी गरीब था और इस साल भी गरीब है। पूरी श्रृंखला में अगर कोई है, जिसके हमेशा अच्छे दिन रहते हैं, तो वह है बीच का आदमी।

खुदरा महंगाई पर नियंत्रण पाने की यह एक ऐसी पहेली है, जिसका समाधान अब तक किसी सरकार के पास नहीं रहा है। थोक महंगाई तो फिर भी माँग-आपूर्ति के नियमों पर कुछ हद

तक चलती है, मगर खुदरा महंगाई की इकतरफा चलने वाली रेल को कैसे किसी टर्मिनल पर रोक कर फिर से उल्टी दिशा में चलाया जाये? लेकिन अगर यह उल्टी दिशा में न भी चले, तो इसकी रफ्तार धीमी हो जाने से भी लोग राहत महसूस करने लगते हैं।

आखिर जो समोसा आपके देखते-देखते बस दो साल में 5 रुपये से 10 रुपये का हो गया, वह अगर अगले साल-डेढ़ साल तक 10 रुपये का ही मिलता रहे तो आप खुश रहेंगे। अर्थशास्त्रियों की भाषा में महंगाई दर धीमी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि दाम पहले से घट जायेंगे। बस इतना होगा कि दाम बढ़ने की रफ्तार पहले से कम हो जायेगी।

# नये डीमैट खातों की संख्या 19 महीनों के शिखर पर

अगस्त 2023 में मुख्य सूचकांकों में गिरावट के बावजूद डीमैट खाते खोलने वाले नये निवेशकों में काफी अधिक वृद्धि दर्ज की गयी। अगस्त में खुलने वाले डीमैट खातों की संख्या 19 महीनों में सबसे अधिक रही। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस और नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी की तरफ से जारी किये गये आँकड़ों के अनुसार अगस्त में खोले गये डीमैट खातों की संख्या 31 लाख से अधिक रही, जो जनवरी 2022 के बाद से सबसे अधिक है।

इसकी तुलना में जुलाई 2023 में 29.7 लाख और अगस्त 2022 में 21 लाख डीमैट खाते खोले गये थे। जुलाई 2023 के मुकाबले 2.51%

और अगस्त 2022 के मुकाबले 25.83% की वृद्धि हुई है। अगस्त में खोले गये 31 लाख से अधिक डीमैट खातों के साथ ही कुल डीमैट खातों की संख्या 12.66 करोड़ से ऊपर हो गयी है। हालाँकि सेंसेक्स और निफ्टी में अगस्त में लगभग 2.5% की गिरावट आयी है, जबकि व्यापक बाजार सूचकांकों को देखें तो बीएसई मिडकैप में 2.6% और स्मॉलकैप में 6.1% की तेजी रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप में बढ़ोतरी को रिकॉर्ड संख्या में नये डीमैट खाते खोले जाने का

एक कारण माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन से शेयर बाजार सर्वकालिक शिखर पर पहुँच गया और इसके चलते नये निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। इसे लंबी अवधि के लिहाज से भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जा रहा है।

वहीं सरकार की छोटी और लंबी अवधि की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और निजी क्षेत्र की ओर से किये गये पूँजीगत खर्च के चलते माँग में वृद्धि भी शेयर बाजार के लिए अच्छा संकेत है, जिसने नये निवेशकों को आकर्षित किया है। खास कर युवा वर्ग में ऐसे लोग शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं, जिन्होंने हाल-फिलहाल में कमाना शुरू किया है।

## एनएसई पर पंजीकृत निवेशकों की संख्या 8 करोड़ के पार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के अनुसार इसके विशिष्ट (यूनीक) पंजीकृत निवेशकों की संख्या आठ करोड़ को पार कर गयी है। एक्सचेंज के साथ पंजीकृत ग्राहक कोड की कुल संख्या 14.9

करोड़ तक पहुँच गयी है। दरअसल ग्राहक एक से अधिक ट्रेडिंग सदस्यों के साथ पंजीकरण कर सकते हैं, इसलिए पंजीकृत ग्राहक कोड की कुल संख्या विशिष्ट पंजीकृत निवेशकों

की संख्या से अधिक होती है। एनएसई के मुताबिक आठ करोड़ विशिष्ट पैनधारक निवेशक भारत में लगभग 5 करोड़ परिवारों से हैं। ये वास्तव में एनएसई के ट्रेडिंग सदस्यों के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में सीधे निवेश करने वाले लगभग 17% परिवार हैं।

बीते आठ महीनों में एनएसई के मंच पर लगभग एक करोड़ नये निवेशकों ने पंजीकरण कराया है। एनएसई ने कहा कि नये एक करोड़ यूनीक पैनधारक निवेशकों में से 45% लोग शीर्ष 100 शहरों से इतर के हैं। इस तरह शीर्ष 100 शहरों का हिस्सा 55% है। इन एक करोड़ नये निवेशक पंजीकरणों में से भारत के उत्तरी भाग के राज्यों की हिस्सेदारी 43% रही। इसके बाद पश्चिम की 27%, दक्षिण की 17% और पूर्व की 13% हिस्सेदारी रही।

एनएसई ने बताया है कि शीर्ष शहरों में दिल्ली (एनसीआर सहित) की हिस्सेदारी 7% रही। इसके बाद मुंबई (ठाणे/रायगढ़ सहित) में 4.6% और पुणे में 1.7% नये निवेशक आये। चालू वित्त-वर्ष के पहले छह महीनों में 76 लाख नये निवेशक पंजीकरण हुए। इससे पहले, नये निवेशक पंजीकरणों की संख्या वित्त-वर्ष 2022-23 में 1.3 करोड़, वित्त-वर्ष 2021-22 में 1.9 करोड़ और वित्त वर्ष 2020-21 में 90 लाख रही थी।

## 2023 की तीसरी तिमाही में नयी ऊँचाई पर पहुँची आवास बिक्री

मानसून की तिमाही में आम तौर पर भूसंपदा बाजार की गति धीमी रहती है। मगर इसके बावजूद 2023 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में देश के शीर्ष-7 शहरों में आवासीय बिक्री एक और नये शिखर पर पहुँच गयी। इन

सात शहरों में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं। तीसरी तिमाही में लगभग 1,20,280 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गयी, जबकि पिछले साल समान तिमाही में 88,230 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गयी थी। संपत्ति सलाहकार फर्म एनारॉक के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर तिमाही में आवासीय बिक्री में 36% की आश्चर्यजनक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी है। वहीं तिमाही-दर-

तिमाही आधार पर भी 5% की वृद्धि देखने को मिली है।

शीर्ष-7 शहरों में एमएमआर ने सबसे अधिक आवासीय बिक्री दर्ज की, जहाँ 38,500 इकाइयों की बिक्री हुई। इसके बाद लगभग 22,880 इकाइयों के साथ पुणे का स्थान रहा। 2023 की तीसरी तिमाही में शीर्ष-7 शहरों में रही कुल बिक्री में इन दो पश्चिमी शहरों, यानी एमएमआर और पुणे, की हिस्सेदारी 51% रही। एमएमआर में आवासीय बिक्री में 46% की वार्षिक वृद्धि देखी गयी, जबकि पुणे में 63% की और भी अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी। इन दो शहरों की बिक्री को बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ मिलाया जाये तो सातों शहरों की बिक्री में 91% हिस्सेदारी इन्हीं चार शहरों की रही। इसके बाद एनसीआर में 6% की धीमी वृद्धि के साथ 15,865 इकाइयों की बिक्री दर्ज हुई। शीर्ष-7 शहरों में ही अप्रैल-जून तिमाही में 1,16,220 से अधिक नयी इकाइयों की आपूर्ति दर्ज की गयी, जो 2022 की इसी तिमाही में 93,490 इकाइयों के मुकाबले 24% अधिक है।



# निवेश मंथन



यूट्यूब पर भी जुड़ें  
**निवेश मंथन** से  
[www.youtube.com/niveshmanthan](http://www.youtube.com/niveshmanthan)



क्यूआर कोड स्कैन करें



# महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष का कसमसाता समर्थन

**म**हिला आरक्षण विधेयक पर तमाम विपक्षी दलों की मजबूरी देखिए। विधेयक आने के अगले दिन पास भी हो गया। इसका समय ही ऐसा चुना गया कि दिन-रात आग उगलने वाले दल समर्थन-समर्थन कहते नजर आये। दिल बुझे हुए थे, पर होठों पर मुस्कान थी। उन्हें 1996 से लेकर 2013 तक केवल



कौशल सिखौला  
वरिष्ठ पत्रकार

2010 में एक बार महिला आरक्षण की याद आयी थी।

यूपीए-2 ने राज्यसभा में इस पर विधेयक पारित कराया था, परंतु लोकसभा में बहुमत होते हुए और भाजपा का समर्थन होते हुए भी मनमोहन सरकार इसे पारित नहीं करा पाये। तब इसके खिलाफ मुलायम, लालू और शरद पवार ने अपनी ही सरकार से बगावत की और लोकसभा में बिल पास न हो पाया। संसद के कार्यकाल के साथ ही बिल समाप्त हो गया। मोदी सरकार भी यदि पहले यह विधेयक लाती तो विपक्ष आसमान सिर पर उठा लेता।

लेकिन सरकार ने जी20 के बाद पाँच दिनों का विशेष सत्र अचानक बुलाया और बड़ी चतुराई से वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी जैसे कई विषय हवा में उड़ा दिये। पर सत्र शुरू होते ही नारी शक्ति वंदन विधेयक लाकर विपक्ष को खासी परेशानी में डाल दिया। ऐसी स्थिति कि बात बताये न बने, छुपाये न बने। परिणाम सामने है, दो ही दिनों में महिलाओं को वह सब कुछ मिल गया, जो राजनीति पिछले 76 वर्षों तक नहीं दे पायी।

कमाल देखिए कि संसद चल रही थी, दोनों सदनों में काफी गंभीर चर्चा हो रही थी, और “भावी प्रधानमंत्री” राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर कुली जैकेट पहन कर पहियों वाला सूटकेस सिर पर उठाकर फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करा रहे थे। पहियों वाला सूटकेस तो कुली भी नहीं उठाते, वे भी उसे हाथ में पकड़कर चलाते हैं।

लेकिन वीडियो शूट था, दुनिया भर में अपलोड भी करना था, सो शूटिंग संपन्न हुई। खैर, राहुल विपक्ष का संभावित पीएम चेहरा हैं या काल्पनिक, किसी को नहीं पता। पर राहुल को लगता है कि वोट संसद की बहस में भाग लेने से नहीं, टोटकों से मिलता है। तो संसद में बैठना है तो डॉट इंडिया वाले बैठें। राहुल तो स्वयंभू फेस



हैं विपक्ष का। इस फेस का जितना मन हो, सदन में उतना ही जायेंगे। बाकी समय वोट कमाऊ जुमलों में लगायेंगे।

विधेयक पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। ओवैसी के दो वोट न पड़े, न पड़ने थे। चैनलों की बदौलत ओवैसी देश की राजनीति का मुस्लिम मुखौटा बन गये हैं। उन्हें अपनी राजनीति करनी थी और कर भी ली। आने वाले समय में महिलाओं के शिखर राजनीति में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया। यह महिला विधेयक पहले से ही प्रगति के पथ पर चल पड़ी भारतीय नारी को उड़ान के नये पंख प्रदान करेगा, यह निश्चित है।

## एमपी, राजस्थान में सब ठीक है?

क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के लिए सब ठीक है? यही सवाल छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लिए भी पूछा जा सकता है। एमपी और राजस्थान में चुनाव पहले होने वाले हैं। ये दोनों राज्य आरंभ से ही कांग्रेस और भाजपा की दो-दलीय राजनीति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ और कोई प्रभावशाली पार्टी मुकाबले में नहीं है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान का दबदबा कायम है।

लेकिन इस बार भाजपा आलाकमान ने दिल्ली से बहुत वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा का टिकट देकर सबको हैरत में डाला है। शिवराज सिंह तो खैर सकते में हैं ही, सिंधिया भी कम परेशान नहीं। इसी तरह भाजपा ने राजस्थान में यदि राज्य से आये अर्जुनराम मेघवाल जैसे मंत्रियों को विधानसभा में भेज दिया तो वसुंधरा राजे के भी होश उड़ जाना निश्चित है।

मध्य प्रदेश में तीन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और सात सांसदों को भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। उससे भी बड़ी बात यह कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े स्टार नेता

को विधानसभा का टिकट दे दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में उनका बेटा अभी विधायक है। पर केंद्र के इस फैसले से विजयवर्गीय बेहद नाखुश हैं। वे बंगाल के विधानसभा चुनाव में पूरे बंगाल के केंद्रीय प्रभारी थे। अब खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए विधानसभा लड़ना मुश्किल काम है। वे पार्टी के लिए वोट माँगते आये हैं, अब अपने लिए कैसे माँगें?

कुछ लोग इसे भाजपा की घबराहट मान रहे हैं। वैसे इतने मंत्रियों को उतारने से लगता भी है कि केवल मोदी मोदी करके चुनाव नहीं जीते जा सकते - यह बात भाजपा के नीति नियंताओं ने मान ली है। कर्नाटक और हिमाचल में केवल मोदी का चेहरा था और भाजपा औंधे मुँह नीचे जा गिरी। मध्य प्रदेश में भाजपा की हड़बड़ाहट बता रही है कि राजस्थान में वहाँ के केंद्रीय मंत्रियों को ही नहीं, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तक को दाँव पर लगाने की बात भाजपा थिंक टैंक न सोच ले?

मध्य प्रदेश में पहले ही शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती पर राजनीतिक बिसात बिछ गयी थी, कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल और विजयवर्गीय के आने से सबके जायके बिगड़ गये हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल विपक्ष की ओर से काफी विश्वास के साथ पूछा गया कि क्या भाजपा संभावित पराजय से सचमुच डर गयी है?

दूसरा सवाल यह कि क्या शिवराज सिंह के दिन अब लद गये? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल और विजयवर्गीय यदि जीते तो वे केवल विधायक या शिवराज कैबिनेट के मंत्री बनने के लिए तो नहीं जीतेगे। तो क्या राज्य में भाजपा की जीत हो जाने पर केंद्रीय मंत्री विधायक पद छोड़ कर दिल्ली लौट जायेंगे? या फिर शिवराज अब लोकसभा जायेंगे?

# ‘होंडा एलिवेट ने दिल खुश कर दिया’

होंडा एलिवेट ने हमारा उत्साह ‘एलिवेट’ कर दिया (बढ़ा दिया) है! होंडा ने काफी समय के बाद कोई नयी गाड़ी पेश की है, लेकिन इसने दिल खुश कर दिया है। इस वाहन ने बाजार पर काफी प्रभाव डाला है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यह मूल्य-श्रेणी काफी लोकप्रिय रही है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकाऊ मॉडल 8 लाख से 20 लाख रुपये के बीच में आते हैं।

निर्माता अपने किसी सफल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बार-बार करना चाहते हैं। होंडा के लिए एलिवेट भी उसी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, जिस पर इन्होंने पहले सिटी बनायी थी। एलिवेट ने गाड़ी के अंदर जो आराम का स्तर पेश किया है, उस मामले में यह अपनी श्रेणी के अन्य वाहनों से आगे है।

## 11 लाख से 16 लाख रुपये मूल्य

मूल्य के इस दायरे में किया और ह्यूंदे जैसे कई प्रमुख नाम हैं। होंडा एलिवेट इन सभी को जबरदस्त टक्कर देने के लिए आयी है। बाजार में इस समय बिक रही गाड़ियों में से यह सबसे अधिक जगह देने वाली गाड़ियों में से एक है, अगर आप पिछली सीट पर मिलने वाले आराम के नजरिये से बात करें।

इस गाड़ी का प्रदर्शन बिल्कुल होंडा सिटी के जैसा ही है। हालाँकि कंपनी 17-18 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन औसत का दावा करती है। लेकिन जितनी भी एसयूवी गाड़ियाँ हैं, वे शहर के अंदर 12 से 14 किमी से ज्यादा का औसत नहीं दे सकती हैं। शहर के अंदर यातायात इतना सघन हो गया है कि किसी भी वाहन के लिए इससे ज्यादा औसत देना पाना संभव नहीं है। एलिवेट के मामले में भी यही स्थिति है। वहीं बिक्री के बाद की सेवाओं के मामले में होंडा की गिनती अच्छी कंपनियों में होती है।

## 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड सीवीटी

होंडा का दावा है कि सीवीटी का ईंधन औसत मैनुअल ट्रांसमिशन से बेहतर है और यही इनका प्रतिष्ठित ट्रांसमिशन रहा है। इस बात को उन्होंने साबित भी किया है। हालाँकि मैनुअल ट्रांसमिशन से जहाँ 16-17 किमी का औसत मिलेगा, वहीं ऑटोमैटिक का औसत एक-डेढ़ किमी अधिक ही रहेगा। सीवीटी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें गियर बदलने का बिल्कुल अहसास



होंडा कार्स इंडिया ने अपनी नयी एसयूवी एलिवेट बाजार में उतार दी है, जो मिड-एसयूवी श्रेणी का वाहन है। इस एसयूवी के बारे में हर पहलू को समझा रहे हैं ऑटो विशेषज्ञ **टूटू धवन**।

नहीं होता है। गाड़ी में बैठने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब वह पहले गियर से तीसरे और पाँचवें गियर में पहुँच गयी। इसी हिसाब से आरपीएम घटते-बढ़ते रहते हैं और ईंधन औसत में इसी का फायदा मिलता है।

खास तौर से युवा पीढ़ी जो मैनुअल चलाने की कोशिश करती है। लेकिन दिल्ली-मुंबई जैसे मेट्रो शहरों के अंदर अब मैनुअल गाड़ी चला पाना काफी मुश्किल हो गया है। कोई व्यक्ति पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब गाड़ी चला कर घर पहुँचता है तो शाम तक उसका बायाँ पैर काफी थक जाता है। इसलिए हम मेट्रो शहरों में लोगों को ऑटोमैटिक श्रेणी का विकल्प चुनने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि इससे आपके आराम का स्तर काफी बढ़ जाता है और थकान नहीं आती।

## टक्कर रोधी तकनीक एडीएस

इस वाहन में होंडा सेंसिंग एडीएस तकनीक के जरिये टक्कर रोधी ब्रेक प्रणाली कॉलिजन मिटिगेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम) है। गाड़ियों में जो इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ये ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हैं। इनके बारे में मेरी सलाह है कि इसे आजमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इनका परीक्षण

विशेष परिस्थितियों में किया जाता है और इसके लिए सभी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाये जाते हैं। किसी अप्रिय परिस्थिति में यह चीज अपने-आप काम करती है और आपको बचाती है। पर सबसे पहले अहम है कि आपने सीट बेल्ट पहन रखी होनी चाहिए। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो तो ऐसी कोई भी सुरक्षा तकनीक काम नहीं आयेगी, एडीएस तकनीक भी नहीं चलेगी और न एयर बैग काम करेगा।

इसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर भी है, जो आम तौर से हाईवे पर ही काम आता है और शहर के अंदर तो इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है। जहाँ तक लेन कीप जैसी सुविधाओं का सवाल है तो ये सभी कामयाब होती हैं, जब सड़कों पर लेन के निशान सही से लगे हों। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में कहीं भी यह सुविधा काम करेगा।

त्योहारी मौसम से पहले होंडा ने एलिवेट को उतार कर बिल्कुल एक नयी हलचल पैदा कर दी है। मेरा मानना है कि होंडा एलिवेट से मारुति, ह्यूंदे और टोयोटा जैसी सभी प्रमुख खिलाड़ियों को काफी तगड़ा मुकाबला मिलेगा। इसकी एक प्रमुख वजह है कि इसके मूल्य का दायरा बहुत बढ़िया है और दूसरे, इसके अंदर आराम का स्तर सबकी आशाओं से कहीं बेहतर है।



अपने निवेश को सुरक्षित कैसे रखें

सतर्क रहें। अपने निवेश पर  
बारीकी से नजर रखें और अपने  
पोर्टफोलियो का पर्यवेक्षण करें।

आप अपने निवेश ध्येय अनुसार करें।  
बिना आवश्यकता उसमें बारबार बदलाव न करें।



इन्वेस्ट राईट तो फ्यूचर ब्राईट

सुरक्षित निवेश व्यवहार के लिए देखें: <https://bseipf.com/doandonts.html>

नियमित ग्राहक बनें **70%** तक छूट पायें



यूपीआई से डिजिटल भुगतान



पेटीएम, भीम ऐप्प या किसी भी अन्य यूपीआई ऐप्प से भुगतान के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें।

### ग्राहक शुल्क (प्रिंट + डिजिटल)

अंक :	नियमित शुल्क	छूट	देय राशि	
12	: 600 रु.	25.0%	450 रु.	<input type="checkbox"/>
24	: 1200 रु.	30.0%	840 रु.	<input type="checkbox"/>
36	: 1800 रु.	33.3%	1200 रु.	<input type="checkbox"/>

मैंने ग्राहक बनने के लिए यह विकल्प चुना है (✓निशान लगायें)

### ग्राहक शुल्क (डिजिटल)

अंक :	नियमित शुल्क	छूट	देय राशि	
12	: 600 रु.	50.0%	300 रु.	<input type="checkbox"/>
24	: 1200 रु.	60.0%	480 रु.	<input type="checkbox"/>
36	: 1800 रु.	70.0%	540 रु.	<input type="checkbox"/>

मैंने ग्राहक बनने के लिए यह विकल्प चुना है (✓निशान लगायें)

### चेक/ड्राफ्ट से भुगतान

NARADVANI SANCHAR MADHYAM PVT. LTD. के नाम से दिल्ली में ऐट पार पर देय चेक (या डिमांड ड्राफ्ट) देना है। चेक के पीछे ग्राहक का पूरा नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। नीचे दिया गया फॉर्म पूरा भरें और चेक के साथ लगा कर इस पते पर भेजें :

**निवेश मंथन, 138 ई. पॉकेट-1, मयूर विहार-1, दिल्ली-110091**  
**दूरभाष : 011-79633546, 47529834**

नियमित ग्राहकों को पत्रिका सामान्य डाक से भेजी जायेगी। कोई अंक नहीं मिलने की शिकायत पर उसकी एक और प्रति भेज दी जायेगी।

## निवेश मंथन ग्राहक आवेदन फॉर्म

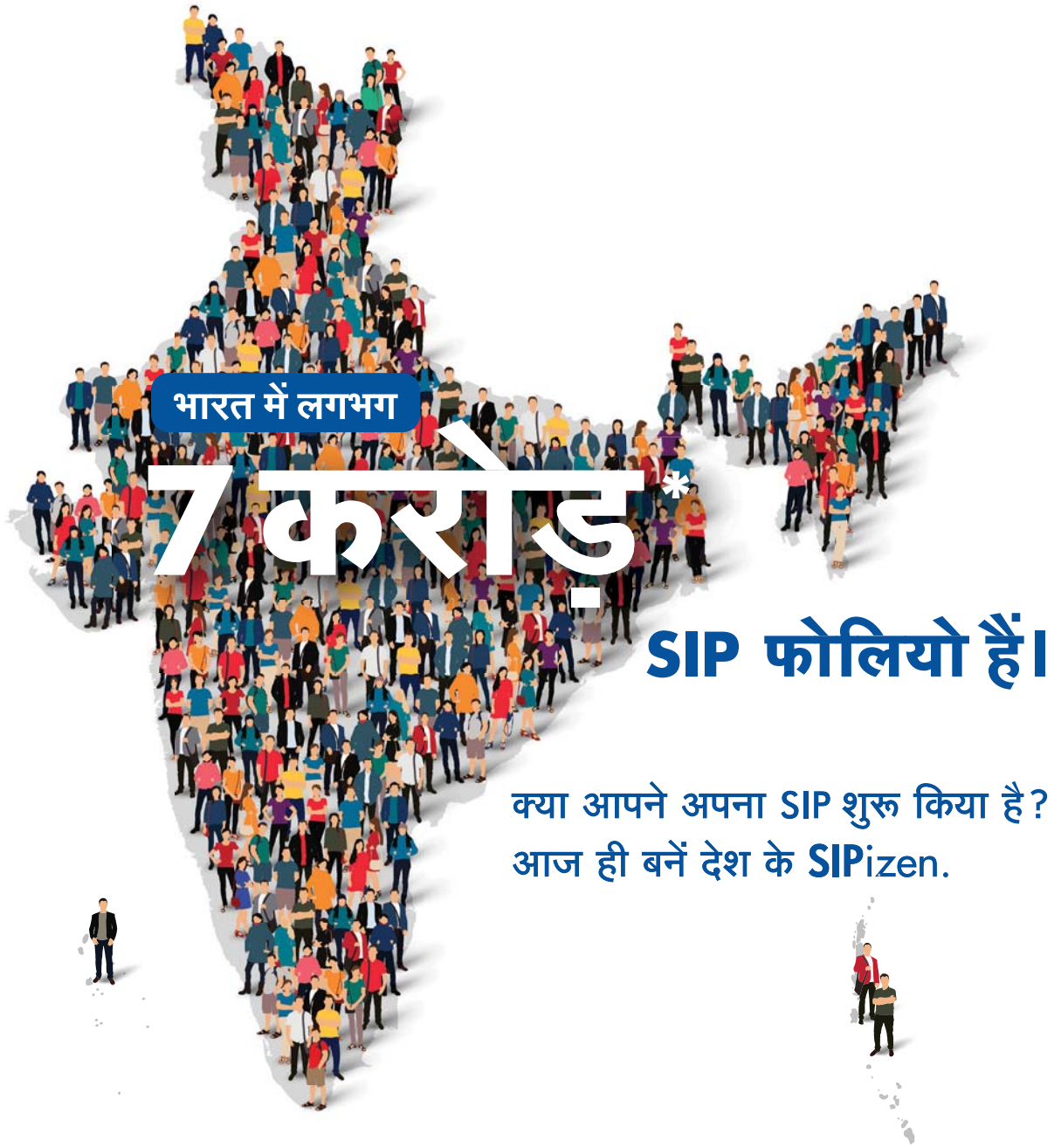
नाम : .....  
 उम्र : ..... स्त्री / पुरुष  
 मोबाइल : .....  
 फोन नंबर : .....  
 ईमेल : .....  
 पूरा पता : .....

प्रिंट + डिजिटल 12 अंक : 450 रुपये ☐  
 प्रिंट + डिजिटल 24 अंक : 840 रुपये ☐  
 प्रिंट + डिजिटल 36 अंक : 1200 रुपये ☐  
 डिजिटल 12 अंक : 300 रुपये ☐  
 डिजिटल 24 अंक : 480 रुपये ☐  
 डिजिटल 36 अंक : 540 रुपये ☐

हस्ताक्षर

..... पिन : .....  
 चेक संख्या : .....  
 बैंक : .....  
 मैंने इस ग्राहक योजना की सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

(ग्राहक योजना के बारे में किसी भी जानकारी के लिए [nivesh@sharemanthan.com](mailto:nivesh@sharemanthan.com) पर ई-मेल करें या +911147529834 पर व्हाट्सऐप से संदेश भेजें)



क्या आपने अपना SIP शुरू किया है?  
आज ही बनें देश के SIPizen.

सिस्टेमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) एक निश्चित अवधि में नियमित रूप से एक विशिष्ट म्यूचुअल फंड योजना में पूर्व-निर्धारित तिथि पर एक निश्चित राशि के अनुशासित निवेश के लिए दी जाने वाली सुविधा है।

**UTI SWATANTRA®**  
India Invest Karo®

An Investor education & awareness initiative of UTI Mutual Fund. To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc., please visit <https://www.utimf.com/servicerequest/kyc>. Please deal with only registered Mutual Funds, details of which can be verified on the SEBI website under "Intermediaries/ market Infrastructure Institutions". All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards [service@uti.co.in](mailto:service@uti.co.in) and/or visit [www.scores.gov.in](http://www.scores.gov.in) (SEBI SCORES portal) or to escalate investor may visit <https://smartodr.in/> Online Dispute Resolution Portal (ODR Portal).

\*बकाया SIP खातों का कुल टर्नओवर अगस्त, 2023 तक 6.96 करोड़ है।  
स्रोत: एनएफआई, म्यूचुअल फंड उद्योग डाटा अगस्त 31, 2023 तक।

**195** BRANCHES  
ACROSS INDIA

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।



**MUTUAL  
FUNDS**  
*Sahi Hai*

**CANARA ROBECO**  
Mutual Fund

अपने इन्वेस्टमेंट को  
फ्लेक्सिबिलिटी दें

3S

के साथ



### SIP

सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स द्वारा दी जानेवाली एक ऐसी सुविधा है जिसकी मदद से निवेशक एक खास फंड में एक सुनिश्चित रकम को एक निर्धारित अवधि के लिए निवेश कर सकता है।

### STP

सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान एक ऐसी सुविधा है जहां निवेशक पहले से निर्धारित फ्रिक्वेंसी पर एक सुनिश्चित रकम को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करने का विकल्प चुन सकता है।

### SWP

सिस्टेमैटिक विड्रॉवल प्लान एक ऐसी सुविधा है जहां आप पहले से निर्धारित अवधि के लिए एक सुनिश्चित रकम को मौजूदा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं।

**#smarTomorrows**

[www.canararobeco.com/smartomorrow](http://www.canararobeco.com/smartomorrow)  
An Investor education and awareness initiative

**म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन होते हैं, स्कीम संबंधी सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।**

निवेशक सिर्फ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स में ही डील करें, जिससे संबंधित जानकारी की पुष्टि सेबी की वेबसाइट (<https://www.sebi.gov.in>) पर 'Intermediaries/Market Infrastructure Institutions' के तहत कर सकते हैं, एक-बार का KYC (नो गोर कस्टमर) पूरा करने की प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिए कृपया विजिट करें <http://bit.ly/cr-mandatory-disclosures>, जिसमें पते, फ़ोन नंबर, बैंक संबंधी जानकारी, इत्यादि में बदलाव की प्रक्रिया भी शामिल है, अगर निवेशक अपने म्यूचुअल फंड्स की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपनी शिकायत स्कोर्स पोर्टल (<https://www.scores.gov.in>) पर दर्ज कर सकते हैं, टैक्स संबंधी मौजूदा नियमों के अधीन, व्यक्तिगत टैक्स अनुमान के लिए, निवेशकों से निवेदन है कि निवेश करने से पहले वे अपने टैक्स एडवाइजर की सलाह लें।